चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

क्या आज़ाद होगा डॉन!

पेज-3

आर्थिक विकास की पोल खोलता मानव विकास

पेज-5

ज़िंदगी संवारती रोशनी

पेज-7

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 07 नवंबर-13 नवंबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

2-जी घोटाले में रॉबर्ट वडेरा अगला निशाना

-सुब्रह्मण्यम स्वामी

2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने देशवासियों का सरकारी तंत्र पर विश्वास ही तोड़ दिया. जब पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इस घोटाले को कोर्ट तक पहुंचाया तो किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि कोई मंत्री किसी घोटाले में जेल भी जा सकता है, लेकिन 2-जी घोटाले में पहले दूरसंचार मंत्री ए राजा जेल गए, फिर डीएमके प्रमुख करुणानिधि की बेटी कनिमोई भी जेल गईं. इनके साथ-साथ बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक और अधिकारी तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने 2-जी घोटाले में जिन-जिन लोगों पर आरोप लगाए, उनके ख़िलाफ़ सबूत भी दिए. फ़िलहाल, गृहमंत्री पी चिदंबरम के ख़िलाफ़ मामले में कोर्ट के आदेश का इंतज़ार है. 2-जी घोटाले में सुब्रह्मण्यम स्वामी का अगला निशाना गांधी परिवार है. चौथी दुनिया ने जब सुब्रह्मण्यम स्वामी से बात की तो उन्होंने कई ऐसी बातें बताईं, जो सनसनीख़ेज़ हैं.

मनीष कुमार

सुब्रह्मण्यम स्वामी का ख़ुलासा

- 2-जी घोटाले में सोनिया गांधी के दामाद भी आरोपी
- राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं
- सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग नहीं किया
- राष्ट्रपति ने सोनिया को प्रधानमंत्री बनने से रोका
- आरएसएस स्वामी को भाजपा में शामिल करना चाहता है

भ्रष्टाचार आज सबसे बड़ा मुद्दा है. रामदेव भ्रष्टाचार को जनजागरण के ज़रिए ख़त्म करना चाहते हैं. अन्ना कहते हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक सशक्त लोकपाल की ज़रूरत है. बिना लोकपाल के भ्रष्टाचार से लड़ा नहीं जा सकता है. सुब्रह्मण्यम स्वामी एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने यह साबित किया है कि मौजूदा क़ानून से भी भ्रष्टाचार से लड़ा जा सकता है. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ देश में जो वातावरण बना है, उसमें 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले का बड़ा योगदान है. वह इसलिए, क्योंकि जिस स्तर का यह घोटाला है, वह दिमाग़ हिला देने वाला है. 1.76 लाख करोड़ रुपये का घोटाला. सिर्फ़ पैसे की ही बात नहीं है, इस घोटाले को जिस तरह अंजाम दिया गया, वह भी अभूतपूर्व है. क्या ख़रीदा गया, क्या बेचा गया, क़ीमत कैसे तय की गई, यह किसी को पता नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों के साथ साठगांठ करके मंत्रियों और नेताओं ने 1.76 लाख करोड़ रुपये की चपत सरकारी खजाने को लगा दी. जब इस घोटाले को लेकर सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो किसी को तनिक भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी घोटाले में कोई मंत्री जेल जा सकता है. लोगों को सुब्रह्मण्यम स्वामी की बातों पर यक़ीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते गए, सुब्रह्मण्यम स्वामी की बात सच साबित होती गई.

उन्होंने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सबसे पहले दूरसंचार मंत्री ए राजा पर निशाना साधा. उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, वह तिहाड़ जेल पहुंच गए. दूसरा निशाना उन्होंने डीएमके प्रमुख करुणानिधि की बेटी कनिमोई पर साधा, वह भी तिहाड़ जेल पहुंच गईं. अदालत में स्वामी सबूत देते गए और बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक एवं अधिकारी भी जेल पहुंचने लगे. इसके बाद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सीधे गृहमंत्री चिदंबरम को निशाना बनाया. वह अदालत पहुंचे और सबूत पेश किए. चिदंबरम पर क्या कार्रवाई हो, यह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित है. सुब्रह्मण्यम स्वामी दावे के साथ कहते हैं कि गृहमंत्री पी चिदंबरम ने अपनी करतूतों को छुपाने का पूरा प्रयास किया और सारा दोष ए राजा पर डाल दिया, लेकिन असल में इस घोटाले में सीनियर पार्टनर पी चिदंबरम हैं और ए राजा जूनियर पार्टनर. 2-जी स्पेक्ट्रम का मामला ऐसा है, जिसके फ़ैसले का इंतज़ार पूरे देश को है और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं.

2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले को देश का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है. इसमें बड़े-बड़े नेता और मंत्री शामिल हैं, उद्योगपति शामिल हैं, अधिकारी शामिल हैं. अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख़ की वजह से सब पर शिकंजा कसता दिख रहा है. सुब्रह्मण्यम स्वामी अकेले ही यह लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्हीं की वजह से आज 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में कई लोग जेल की हवा खा रहे हैं. 2-जी घोटाले में अभी और भी कई बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं, जो क़ानून के शिकंजे से बाहर हैं और जिन्हें पकड़ा जाना है. सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं कि चिदंबरम के बाद उनके निशाने पर रॉबर्ट वडेरा हैं, जो सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति हैं. इनके अलावा दो और बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं. उन्होंने बताया कि फ़िलहाल उनके पास दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ सबूत नहीं हैं, लेकिन 2-जी घोटाले में रॉबर्ट वडेरा की भूमिका का पर्दाफ़ाश करने के लिए वह पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने 2-जी घोटाले में रॉबर्ट वडेरा की भूमिका की अपनी जांच-पड़ताल पूरी कर ली है. उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, जिनसे वह राबर्ट वडेरा के ख़िलाफ़ अदालत में मामला दायर कर सकेंगे. मतलब यह कि सुब्रह्मण्यम स्वामी को 2-जी घोटाले में गृहमंत्री चिदंबरम के मामले में कोर्ट के आदेश का इंतज़ार है. कोर्ट का फ़ैसला आते ही वह गांधी परिवार पर हमला करने की तैयारी में हैं. यह एक निर्णायक लड़ाई होगी. 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में गांधी परिवार के लोगों का हाथ है, वह यह साबित करने में जुट जाएंगे. राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सुब्रह्मण्यम स्वामी अपनी क़ानूनी लड़ाई से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं. अगर अदालत चिदंबरम के ख़िलाफ़ जांच का आदेश देती है तो उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है, सरकार गिरने की आशंका बढ़ जाएगी, मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और अगर चिदंबरम को कोर्ट से राहत मिलती है तो सुब्रह्मण्यम स्वामी रॉबर्ट वडेरा को 2-जी घोटाले में आरोपी बनाकर राजनीतिक भूचाल ला देंगे. दोनों ही स्थितियां कांग्रेस के लिए ख़तरनाक हैं.

सुब्रह्मण्यम स्वामी गांधी परिवार के विरोधी हैं. सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ वह अक्सर बयान देते रहे हैं. चौथी दुनिया से बातचीत के दौरान सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक ऐतिहासिक ख़ुलासा किया है. कांग्रेस पार्टी अब तक यही मानती आई है और देश को यह बताती आई है कि सोनिया गांधी ने अपनी अंर्तात्मा की आवाज़ सुनकर प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया. सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं कि सोनिया गांधी ने कोई त्याग नहीं किया है. यह एक मिथ्या है कि सोनिया गांधी ने पद का त्याग किया है. उनके मुताबिक़, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थीं, लेकिन राष्ट्रपति ने मना कर दिया. 17 मई, 2004 को शाम पांच बजे राष्ट्रपति सोनिया गांधी को सरकार बनाने का न्योता देने वाले थे. उसी दिन दोपहर साढ़े बारह बजे सुब्रह्मण्यम स्वामी राष्ट्रपति से मिले. उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि देश के नागरिकता क़ानून के मुताबिक़ कोई भी विदेशी जब भारत का नागरिक बनता है तो उस पर वही क़ानून लागू होता है, जो उसके पहले वाले देश में लागू होता है. इटली में कोई विदेशी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, इसलिए सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं. इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि ख़ुफ़िया एजेंसी रॉ से विचार-विमर्श कीजिए, क्योंकि सोनिया गांधी के पास भारत के अलावा इटली का भी पासपोर्ट है. स्वामी दावा करते हैं कि आज भी सोनिया गांधी के पास दो-दो पासपोर्ट हैं. सुब्रह्मण्यम स्वामी से बातचीत करने के बाद राष्ट्रपति ने साढ़े तीन बजे सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें पांच बजे आने से मना किया गया था. सुब्रह्मण्यम स्वामी के मुताबिक़, राष्ट्रपति द्वारा सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र में उनकी शिकायत

(शेष पृष्ठ 2 पर)

उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में बनी चयन समिति को अनंत का अर्थशास्त्री होना ही भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् होने के लिए काफी लगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

कैबिनेट सचिव की सक्रियता

एके सेठ के कैबिनेट सचिव बनने के बाद उनके बारे में कुछ ज़्यादा सुनने को नहीं मिला है, लेकिन अब वह सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने कुछ पुरानी प्रणालियों में फेरबदल करने की ठानी है, ताकि शासन को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके. गौरतलब है कि शासन में पारदर्शिता मौजूदा समय में यूपीए सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है. सेठ ने इसके लिए करीब 42 मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों एवं निदेशकों से मुलाकात की और उनसे शासन को पारदर्शी बनाने एवं लोगों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के मुद्दे पर चर्चा की. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत हुई इस बैठक में बाबुओं ने सुधार के लिए अपने-अपने सुझाव दिए. विभाग के सचिव रमेश सी चंद्रा ने कहा कि यह बैठक काफी उत्साहवर्द्धक रही और इसमें भाग लेने वाले बाबुओं ने अच्छी भूमिका निभाई. सेठ ने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन देखना यह है कि लोगों को इसका कितना लाभ मिल पाता है.

बाबू का साहित्य प्रेम

बाबू होने के फायदे और नुकसान दोनों हैं. कुछ ऐसा ही नुकसान केरल कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को हुआ. अपने साहित्य प्रेम के कारण उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा. 1998 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. बी अशोक को न्यू केरल वेटनरी एवं एनिमल साइंस विश्वविद्यालय के कुलपति पद से हटा दिया गया. रूसी साहित्यकार लियो टॉलस्टाय से प्रभावित इस अधिकारी ने एक समाचारपत्र में लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने आईएएस अधिकारियों की तुलना लोभी किसान से कर दी थी. यही नहीं, उन्होंने अपने इस विचार की पुष्टि के लिए अन्य अधिकारियों को भी कहा था. वहां के बाबुओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई. राज्य के मुख्य सचिव पी प्रभाकरन इस समाचारपत्र की प्रति राज्य कैबिनेट के पास ले गए. इसके बाद बी अशोक को पद से हटा दिया गया. अब इस पद पर अतिरिक्त मुख्य सचिव के जयंत कुमार को नियुक्त किया गया है.

कैट का फ़ैसला

क्या आंकड़े गलत नहीं हो सकते? इस बात को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् टी सी अनंत के संदर्भ में देखा जा सकता है. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने अनंत की नियुक्ति इस आधार पर खारिज कर दी कि वह इस पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रखते. कैट ने अपने आदेश में कहा कि इस पद के लिए जिस सांख्कीय और प्रबंधकीय अनुभव की अपेक्षा की गई थी, वह अनंत के पास नहीं है. गौरतलब है कि भारत सरकार ने अपनी ही अधिसूचना की उपेक्षा की है. योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की

अध्यक्षता में बनी चयन समिति को अनंत का अर्थशास्त्री होना ही भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् होने के लिए काफी लगा और उसने इस पद पर उनकी नियुक्ति कर दी. अब कैट ने इस समिति को दो महीने के भीतर अन्य अधिकारियों की अनुशंसा का आदेश दिया है. अहलूवालिया को शायद अर्थशास्त्र और सांख्यिकी एक जैसे लगते हैं, इसीलिए उन्होंने आंकड़ा संबंधी अनुभवों को दरकिनार कर केवल अर्थशास्त्री होने की योग्यता ही ध्यान में रखी.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

अनिल बने सचिव

1984 बैच के आईआरपीएस अधिकारी अनिल कुमार गुलाटी को न्याय विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है. यह पद नवसृजित है.

प्रसाद चले ऊर्जा मंत्रालय

1991 बैच के आईएएस अधिकारी जी साई प्रसाद को ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह डॉ. मेदिथी रविकांत की जगह लेंगे, जिन्हें पीडीआईएल में सीएमडी बनाया गया है.

पंकज शरण को सेवा विस्तार

1982 बैच के आईएफएस अधिकारी पंकज शरण को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है. वह अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव हैं.

मिनई संयुक्त सचिव बनीं

1985 बैच की आईए एंड एएस अधिकारी गजाला मिनई को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा. वह पी पी मित्रा का स्थान लेंगी.

देवदत्त निदेशक बनेंगे

1993 बैच के आईएएस अधिकारी विक्रम देवदत्त को कपड़ा मंत्रालय में निदेशक बनाया जाएगा. वह मनीष कुमार गुप्ता की जगह लेंगे.

2-जी घोटाले में रॉबर्ट वडेरा अगला निशाना

पृष्ठ एक का शेष

का उल्लेख है. यह पत्र आज तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है. सुब्रह्मण्यम स्वामी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देते हैं कि वह उस पत्र को सार्वजनिक करे. उन्होंने इस दौरान हुई एक घटना को भी विस्तार से बताया. उनके मुताबिक़, जब वह राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे तो वहां उन्होंने सांसदों के समर्थन पत्र देखे. 340 सांसदों के समर्थन पत्र थे, जिनमें सबने यह लिखा था कि मैं फलां फलां संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करता हूं. वहां एक पत्र सोनिया गांधी का भी था, जिसमें यह लिखा था कि मैं सोनिया गांधी रायबरेली से निर्वाचित सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करती हूं. स्वामी कहते हैं कि इससे यह साबित होता है कि सोनिया गांधी का त्याग एक झूठी कहानी है.

सुब्रह्मण्यम स्वामी का मानना है कि अपनी मां की तरह राहुल भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते. राहुल गांधी जिस वक़्त पैदा हुए, उस वक़्त सोनिया गांधी इटली की नागरिक थीं और वहां के क़ानून के मुताबिक़ राहुल गांधी भी इटली के नागरिक हैं. स्वामी कहते हैं कि इटली की नागरिकता त्याग करने की जो प्रक्रिया है, उसमें राहुल गांधी ने कभी हिस्सा नहीं लिया. उन्होंने एक घटना के बारे में बताया. घटना बोस्टन शहर की है. राहुल वहां साठ हज़ार डॉलर के साथ पकड़े गए थे, उस वक़्त भी राहुल गांधी के पास इटालियन पासपोर्ट था. मतलब यह कि राहुल गांधी के पास दो-दो पासपोर्ट हैं. सुब्रह्मण्यम स्वामी का यह आरोप एक गंभीर आरोप है. इस आरोप की सच्चाई जनता के सामने आना ज़रूरी है.

सुब्रह्मण्यम स्वामी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं, वह बेख़ौफ़ भी हैं. बातचीत के दौरान हमने उनसे जब यह पूछा कि वह गांधी परिवार और सोनिया गांधी से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपना नाम ग़लत बताया. जन्म प्रमाणपत्र में उनका दूसरा नाम है. उनकी जन्मतिथि को लेकर भी विवाद है. वह 1944 में जन्मी हैं या 1946 में, इस बात को लेकर भी संदेह है. साथ ही सोनिया गांधी ने अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में देश को गुमराह किया है. सुब्रह्मण्यम स्वामी सिर्फ़ आरोप ही नहीं लगा रहे हैं बल्कि वह इन मामलों को लेकर कोर्ट भी गए. उन्होंने बताया कि प्राचीन मूर्तियों की तस्करी और रूसी ख़ुफ़िया एजेंसी केजीबी से पैसे लेने के मामलों को लेकर वह कोर्ट गए. कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए. सीबीआई के अधिकारी विदेश भी गए और जांच की. वापस आकर उन्होंने बताया कि इन मामलों में सबूत तो हैं, लेकिन दूसरे देशों की सरकारें तब तक कोई दस्तावेज़ नहीं देंगी, जब तक भारत सरकार से लेटर रैगोटरी नहीं मिलता है. यह सरकारी चिट्ठी जारी होने के लिए पहले एक एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है, फिर कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है. जिस वक़्त स्वामी ने इस मामले को उठाया था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिसने सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दिया. सोनिया गांधी ने पहले अपने चुनाव आयोग में जमा किए हलफ़नामे में यह लिखा था कि उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बीए की पढ़ाई की है. सुब्रह्मण्यम स्वामी इस मामले को लेकर कोर्ट गए. वह दावा करते हैं कि उनके पास कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक चिट्ठी है, जो कहती है कि इस नाम की कोई छात्रा वहां पढ़ी ही नहीं. उन्होंने बताया कि इस मामले से जुड़े सारे तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो तत्कालीन न्यायाधीश बालाकृष्णन ने आरोपों को एक तरह से सच माना, लेकिन यह कहा कि स्वामी जी, आप थोड़ा बड़े दिल वाले बनो, छोड़ दो, यह पुराना मामला है, अब वह ऐसा काम नहीं करेंगी. सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं कि इस मामले में उनकी जीत हुई है, क्योंकि सोनिया गांधी ने 2009 के चुनाव में जो हलफनामा दिया, उसमें से कैम्ब्रिज का नाम हटा दिया. अगर वह कैम्ब्रिज में पढ़ी हैं तो उन्हें यह बात अपने हलफ़नामे से हटानी नहीं चाहिए थी.

सुब्रह्मण्यम स्वामी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वह भी अकेले. वह एक राजनेता भी हैं, इसलिए क़ानूनी लड़ाई से कैसे राजनीतिक चालें चली जा सकती हैं, यह उन्होंने बख़ूबी साबित किया है. हाल में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक चिट्ठी पेश की, जिससे मनमोहन सरकार में एक भूचाल आ गया. चिट्ठी वित्त मंत्रालय द्वारा लिखी गई थी. हंगामा मच गया कि प्रणव मुखर्जी इस चिट्ठी के सूत्रधार हैं. इस चिट्ठी की वजह से देश के दो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री यानी गृहमंत्री और वित्तमंत्री आपस में भिड़ गए. यह विवाद कांग्रेस पार्टी के लिए ख़तरनाक हो गया, क्योंकि इस चिट्ठी में लिखा था कि अगर गृहमंत्री पी चिदंबरम चाहते तो 2-जी घोटाला नहीं होता. चिदंबरम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यह चिट्ठी बतौर सबूत पेश की. इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर कई मंत्रालयों के अधिकारियों ने सलाह-मशविरा करके मिलजुल कर तैयार किया था. यह चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय के पास थी. जुलाई के महीने में किसी आरटीआई के जवाब में इस चिट्ठी को किसी ने हासिल किया था. ख़बर यह फैलाई गई कि सुब्रह्मण्यम स्वामी को उसी की कॉपी मिली है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि जिस चिट्ठी को स्वामी ने कोर्ट में पेश किया, वह आरटीआई से मिली चिट्ठी नहीं है. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यह नहीं बताया कि उन्हें यह चिट्ठी कहां से मिली, वह मुस्करा कर इस सवाल को टाल गए. समझने वाली बात यह है कि जब चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय में थी तो यह सुब्रह्मण्यम स्वामी को खेल मंत्रालय से नहीं मिली होगी. प्रणव मुखर्जी और चिदंबरम की लड़ाई से यूपीए सरकार की कलई खुल गई.

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जो काम अकेले किया है, वह पूरा विपक्ष नहीं कर सका. भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह सरकार के ख़िलाफ़ एक सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकी. भ्रष्टाचार के जितने भी मामले सामने आए, उन्हें विपक्ष ने नहीं उठाया, बल्कि उन घोटालों का पर्दाफाश मीडिया ने किया. देश में 2-जी, कॉमनवेल्थ, सत्यम और आदर्श सोसायटी जैसे कई घोटाले सामने आने के बाद ही विपक्ष ने उन्हें मुद्दा बनाया. हैरानी इस बात की है कि इन घोटालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ संसद के अंदर हंगामा करती रही, विपक्ष न तो किसी मंत्री का इस्तीफ़ा ले सका और न कोई देशव्यापी आंदोलन छेड़ सका. देश में आज भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो माहौल बना है, उसके पीछे बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और सुब्रह्मण्यम स्वामी का हाथ है. सुब्रह्मण्यम स्वामी अगर अदालत का दरवाज़ा न खटखटाते तो आज 2-जी घोटाले के सारे आरोपी पहले की तरह चैन से अपना-अपना काम कर रहे होते. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जो काम अकेले किया, वह पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकी. स्वामी जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी की स्थिति कमज़ोर है. वह अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करने के लिए तैयार बैठे हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी भी यही चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता विरोध कर रहे हैं. उनका विरोध वे नेता कर रहे हैं, जो बड़े वकील हैं और राज्यसभा में हैं, जो ख़ुद को बुद्धिजीवी मानते हैं, जो जनसभाएं करते हैं. सुब्रह्मण्यम स्वामी के मुताबिक़, ऐसे नेताओं को लगता है कि अगर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी. वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह डर हमेशा लगा रहेगा कि अगर सुब्रह्मण्यम स्वामी पार्टी में शामिल हो गए तो पार्टी नेताओं के भी भ्रष्टाचार उजागर करने में वह नहीं झिझकेंगे.

सुब्रह्मण्यम स्वामी एक परिपक्व राजनेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हें क़ानून और राजनीति की समझ है. उनके आरोपों को ख़ारिज करना आसान नहीं है. उन्होंने जब भी आरोप लगाया, उसका सबूत दिया. अगर सुब्रह्मण्यम स्वामी के आरोप ग़लत हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए. 2-जी घोटाले में चिदंबरम के बाद उनके निशाने पर गांधी परिवार है. सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं. कुछ आरोप तो ऐसे हैं, जिनकी सच्चाई जानना देश की जनता का हक़ है. कुछ ऐसे आरोप हैं, जिनका जवाब कांग्रेस पार्टी को अवश्य देना चाहिए. हमें कांग्रेस पार्टी के जवाब का इंतज़ार है.

(नोटः यह रिपोर्ट सुब्रह्मण्यम स्वामी से हुई बातचीत पर आधारित है. ऐसे में दूसरे पक्ष की बातों को शामिल करना संभव नहीं है. अपने इंटरव्यू में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आडवाणी की रथयात्रा, नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और कई अन्य राजनीतिक विषयों पर बातचीत की है, जिसे आप www.chauthiduniya.tv पर देख सकते हैं.)

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 35
दिल्ली, 07 नवंबर–13 नवंबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

हैरानी की बात यह भी है कि सीबीआई आज तक अबू सलेम के मामले में ऐसे ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी, जिनकी बिना पर भारत दावे के साथ पुर्तगाल के हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दे सके.

क्या आज़ाद होगा डॉन!

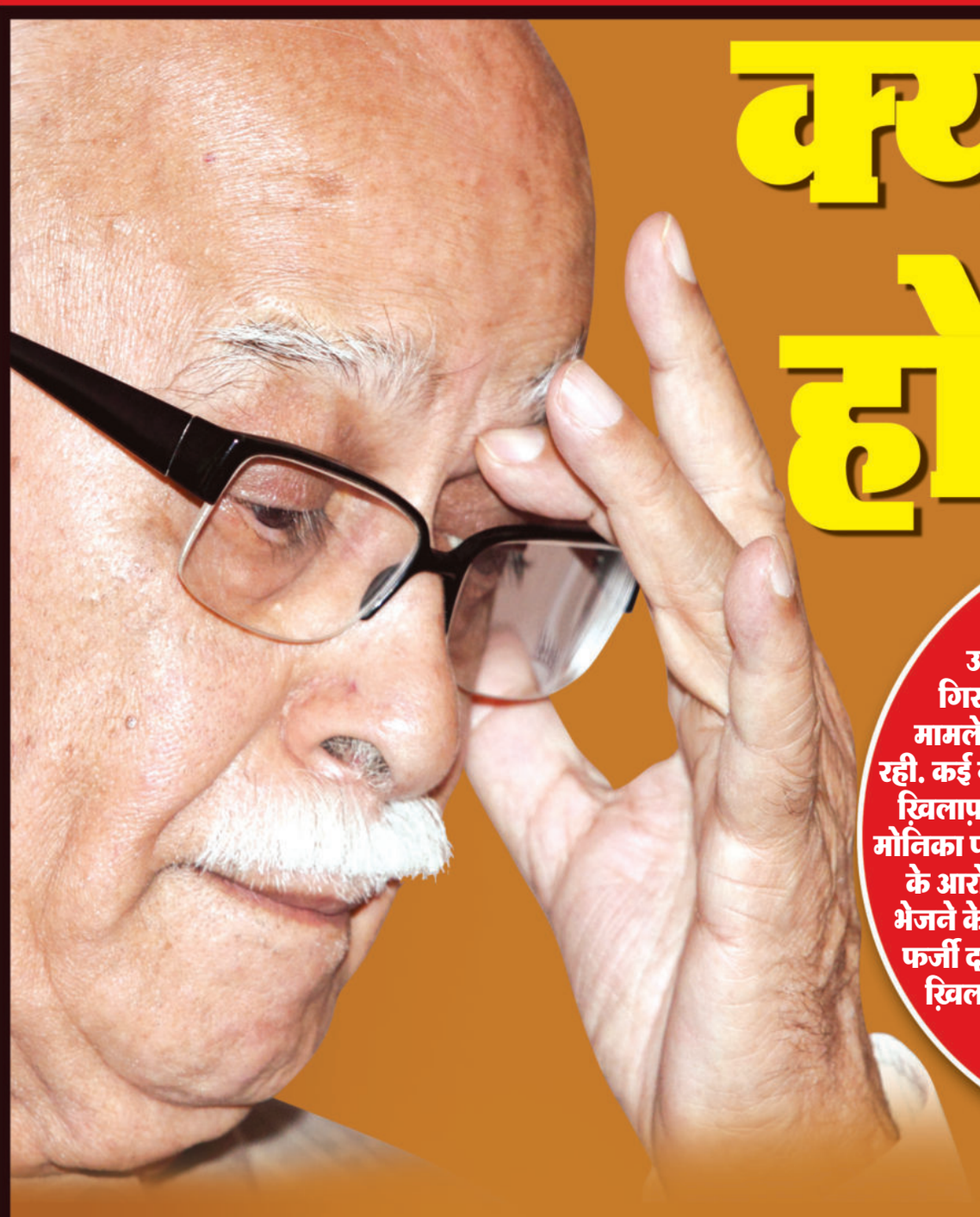

जब लालकृष्ण आडवाणी गृहमंत्री थे, तब अबू सलेम को उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी के साथ गिरफ्तार किया गया था. मोनिका बेदी के मामले में भी पुलिस की कार्रवाई बेहद शर्मनाक रही. कई गवाह पेश करने के बावजूद वह मोनिका के ख़िलाफ़ लगे आरोप साबित करने में नाकाम रही. मोनिका पर 2001 में ग़लत तरीके से पासपोर्ट बनवाने के आरोप थे. पुर्तगाल सरकार ने सलेम को भारत भेजने के आग्रह को यह कहकर ठुकरा दिया था कि फर्जी दस्तावेजों के साथ पुर्तगाल में घुसे सलेम के ख़िलाफ़ पहले पुर्तगाली क़ानून के मुताबिक़ कार्रवाई की जाएगी. पुर्तगाल की अदालत ने उसे 3 साल की सज़ा सुनाई.

रूबी अरुण

फ़र्ज़ कीजिए, अगर माफ़िया सरगना अबू सलेम भारत के बजाय अमेरिका का मुजरिम होता तो क्या पुर्तगाल सरकार या दुनिया की कोई अन्य सरकार उसका प्रत्यर्पण रद्द कर पाती? क्या तब पुर्तगाल सरकार प्रत्यर्पण संधि के नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर उसे फांसी की सज़ा से बचाने की जुगत भी कर पाती? प्रत्यर्पण संधि के नियमों का उल्लंघन होने की सूरत में क्या इस मसले को कूटनयिक और राजनयिक स्तर पर सुलझा नहीं लिया गया होता? क्या सैकड़ों मासूम ज़िंदगियों को ख़त्म करने वाला गुनहगार सरकारी दामाद की तरह जेल के अंदर भी सभी सुविधाओं के बीच ज़िंदगी बसर करता? नहीं ना! पिछले छह सालों से अबू सलेम को अपनी गिरफ्त में रखने के बावजूद आज देश उस स्थिति में नहीं है कि वह उसे सज़ा दिला सके. ये हालात दु:खद होने के साथ शर्मनाक भी हैं कि अबू सलेम एक भारतीय नागरिक है और गुनहगार है, तो भी उसे भारतीय कानून के अनुसार सजा देने से कोई अन्य देश रोक लगा सकता है. चूंकि यह हिंदुस्तान है, जहां राजनयिक और कूटनयिक स्तर पर ग़लतियां करने की आदत है, इसलिए सरकारी बाबुओं की सेहत पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि इस मसले पर सरकार की कितनी फ़ज़ीहत हो रही है या फिर देश की साख ही ख़तरे में है.

जब लालकृष्ण आडवाणी गृहमंत्री थे, तब अबू सलेम को उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी के साथ गिरफ्तार किया गया था. मोनिका बेदी के मामले में भी पुलिस की कार्रवाई बेहद शर्मनाक रही. कई गवाह पेश करने के बावजूद वह मोनिका के ख़िलाफ़ लगे आरोप साबित करने में नाकाम रही. मोनिका पर 2001 में ग़लत तरीके से पासपोर्ट बनवाने के आरोप थे. पुर्तगाल सरकार ने सलेम को भारत भेजने के आग्रह को यह कहकर ठुकरा दिया था कि फ़र्ज़ी दस्तावेजों के साथ पुर्तगाल में घुसे सलेम के ख़िलाफ़ पहले पुर्तगाली क़ानून के मुताबिक़ कार्रवाई की जाएगी. पुर्तगाल की अदालत ने उसे 3 साल की सजा सुनाई. सजा पूरी करने के बाद उसे सितंबर 2005 में प्रत्यर्पण के ज़रिए भारत लाया गया. सवाल यह भी है कि जब सलेम पुर्तगाल में सजा पूरी कर चुका था तो उसे डिपोर्टेशन के बजाय प्रत्यर्पण के ज़रिए भारत क्यों लाया गया? उस समय के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह कहते हैं कि सीबीआई और तत्कालीन एनडीए सरकार ने मिलकर इस केस का बंटाधार कर दिया. जो केस डिपोर्टेशन का था, उसे प्रत्यर्पण का बनाकर सलेम को फ़ायदा पहुंचाया गया. सोचने वाली बात यह है कि सजा पूरी होने के बाद पुर्तगाल सरकार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त एक शख्स को अपने देश में क्यों रखती है?

भारत ने पुर्तगाल को अबू सलेम के अपराधों की जो सूची सौंपी थी, उसके अनुसार 1993 के बम विस्फोटों सहित उस पर कुल आठ मामले चलाए जाने थे. सलेम पर फ़र्ज़ी पासपोर्ट, हत्या, बम विस्फोट और वसूली सहित कई मामले दर्ज थे. सलेम के प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार ने पुर्तगाल को आश्वासन दिया था कि उसे उसके किसी भी जुर्म के बदले मौत की सजा नहीं दी जाएगी और न ऐसे क़ानून के तहत सुनवाई की जाएगी, जिसमें 25 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो. पुर्तगाल ने मोनिका बेदी और सलेम, दोनों को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया था. यह आश्वासन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और तत्कालीन विदेश राज्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया था.

पुर्तगाल के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि के अनुसार, सलेम पर मकोका के तहत भी मामला नहीं बनाया जा सकता था, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए अबू सलेम पर मकोका का मामला बना दिया कि वह संगठित अपराध चला रहा था. इसी को लेकर अबू सलेम के वकील एम एस खान ने 2009 और फिर 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके अबू सलेम पर से मकोका हटाने की मांग की थी. बीते दो सालों से पुलिस इस पर गंभीर नहीं हुई, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि बचाव पक्ष की दलील ठीक है और यह भी समझ में आ गया कि वाकई इससे अबू सलेम का प्रत्यर्पण खत्म हो जाएगा. प्रत्यर्पण की शर्तों के मुताबिक़, सलेम के ख़िलाफ़ दर्ज 9 में से सिर्फ 3 मुक़दमे ही चल सकते हैं.

यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब बतौर गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों को अबू सलेम के खौफनाक जुर्मों की जानकारी थी, सीबीआई में उसके ख़िलाफ़ मामले दर्ज थे, देश की ख़ुफ़िया एजेंसियां उसके पीछे लगी थीं और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका था, फिर भी पुर्तगाल सरकार को अबू सलेम के गुनाहों की जो सूची सौंपी गई, उसमें इस बात का ज़िक्र क्यों नहीं था कि अबू सलेम का आपराधिक नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है और वह सांगठनिक अपराध करता है, इसलिए उस पर मकोका क़ानून भी लगाया जा सकता है. जिस समय लालकृष्ण आडवाणी गृहमंत्री थे, तभी 2002 में अबू सलेम ने दिल्ली के व्यवसायी अशोक गुप्ता को धमकी देकर पांच करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन यह घोर लापरवाही बरती गई. देश के वजूद के लिए ख़तरा बने अपराधी के ख़िलाफ एक्शन लेते समय भी हुक्मरानों ने गंभीरता नहीं बरती. यह जानते हुए भी कि अबू सलेम के रिश्ते दाऊद इब्राहिम और आईएसआई से भी हैं.

देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का तमाशा यहीं नहीं थमता. मई 2009 में सीबीआई ने अदालत में अर्जी देकर यह गुहार लगाई थी कि अबू सलेम के प्रत्यर्पण की शर्तों के हिसाब से उस पर मकोका नहीं लगाया जा सकता. इससे पुर्तगाल सरकार प्रत्यर्पण निरस्त कर सकती है, इसलिए यह केस वापस लिया जाए, लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय की नींद नहीं खुली. बाबुओं की ग़लती की वज़ह से भारत सरकार की किरकिरी करते हुए पुर्तगाल के उच्च न्यायालय ने माफिया सरगना अबू सलेम के प्रत्यर्पण आदेश को ही रद्द कर दिया. तब आनन-फानन में दिल्ली पुलिस ने भी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सलेम पर लगाए गए मकोका के मामले को वापस लेने की मांग कर दी. हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस को न केवल फटकार लगाई, बल्कि निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी. सरकार ने इस मसले पर इतना ढीला रवैया अपनाया कि न सिर्फ सलेम पर मामला बनाया गया, बल्कि आरोप भी तय कर दिए गए.

भारत ने पुर्तगाल को अबू सलेम के अपराधों की जो सूची सौंपी थी, उसके अनुसार 1993 के बम विस्फोटों सहित उस पर कुल आठ मामले चलाए जाने थे. सलेम पर फ़र्ज़ी पासपोर्ट, हत्या, बम विस्फोट और वसूली सहित कई मामले दर्ज थे. सलेम के प्रत्यर्पण के समय भारत सरकार ने पुर्तगाल को आश्वासन दिया था कि उसे उसके किसी भी जुर्म के बदले मौत की सजा नहीं दी जाएगी और न ऐसे क़ानून के तहत सुनवाई की जाएगी, जिसमें 25 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो. पुर्तगाल ने मोनिका बेदी और सलेम, दोनों को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया था.

हैरानी की बात यह भी है कि सीबीआई आज तक अबू सलेम के मामले में ऐसे ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी, जिनकी बिना पर भारत दावे के साथ पुर्तगाल के हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दे सके. हालांकि सीबीआई प्रत्यर्पण आदेश रद्द करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है. सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि अबू सलेम के गुनाहों के हिसाब से उसके ख़िलाफ़ लगाई गई धाराओं में उसे बेहद कम सजा मिली है. सीबीआई की कोशिश होगी कि वह पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट को यह तथ्य समझा सके. सीबीआई इससे संबंधित रणनीति भी तैयार कर चुकी है. अगर पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील ठुकरा दी तो वैसी सूरत में सीबीआई अंतरराष्ट्रीय अदालत में अपील करेगी. सीबीआई के एक आला अधिकारी का कहना है कि भले ही सलेम के ख़िलाफ़ लगाई गई नई धाराओं को वापस लेना पड़े, लेकिन बेहद मुश्किल से शिकंजे में आए अबू सलेम को किसी भी सूरत में छोड़ने को जांच एजेंसियां तैयार नहीं हैं.

पर यहां भी वही सवाल खड़ा है कि क्या सीबीआई पुर्तगाल के सुप्रीम कोर्ट या अंतरराष्ट्रीय अदालत को ऐसे सबूत सौंप पाएगी, जिनके आधार पर अबू सलेम पर मकोका के तहत मुकदमा चलाने या सज़ा देने का अख्तियार भारत को मिल सके. अगर सीबीआई इसमें विफल रहती है तो यकीनन माफ़िया सरगना एक बार फिर भारत में दहशत फैलाने के लिए आज़ाद होगा और एनडीए एवं यूपीए सरकार की गलतियों का खामियाजा भारत की बेगुनाह जनता अपनी और अपनों की ज़िंदगियां गंवाकर चुकाने के लिए मजबूर होगी.

सवाल यह भी है कि जब सलेम पुर्तगाल में सजा पूरी कर चुका था तो उसे डिपोर्टेशन के बजाय प्रत्यर्पण के जरिए भारत क्यों लाया गया? उस समय के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह कहते हैं कि सीबीआई और तत्कालीन एनडीए सरकार ने मिलकर इस केस का बंटाधार कर दिया. जो केस डिपोर्टेशन का था, उसे प्रत्यर्पण का बनाकर सलेम को फ़ायदा पहुंचाया गया.

ruby@chauthiduniya.com

उद्योगपतियों, नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों की अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा ने आदिवासियों को उनके घरों से ही बेदखल कर दिया.

सामाजिक न्याय का मुद्दा

सभी राजनीतिक दल फिसड्डी

शिव दास

अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने चारा डालना शुरू कर दिया है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने करीब छह माह पहले ही अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मामला उछाल दिया था. इसके बाद मुलायम सिंह यादव मुस्लिमों को लुभाने के लिए नए शिगूफे की तलाश करने लगे. मौके की नजाकत भांपते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अल्पसंख्यकों के साथ-साथ कई अन्य वर्गों के लिए आरक्षण की मांग कर डाली. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बाकायदा पत्र भी लिखा और राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए अपने पत्र को मीडिया को जारी कर दिया. केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के साथ-साथ राज्य में मज़बूत पकड़ रखने वाली सपा और बसपा के इन कदमों ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है, जिससे निकलने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है. आरक्षण के बल पर शह और मात का खेल खेलने के लिए वह किसी विशेष मुद्दे की तलाश में है, लेकिन यह रास्ता उसके लिए आसान नहीं होगा. पार्टी में मजबूत पकड़ रखने वाली आरक्षण विरोधी ताकतों को भी यह मंजूर नहीं होगा कि कांग्रेस वोट बैंक के चक्कर में उनके वर्ग को मिलने वाला लाभ दूसरे वर्गों में बांट दे.

इन परिस्थितियों में कांग्रेस के पास एक ही सहारा है और वह है सामाजिक न्याय का मुद्दा, लेकिन उसे वह आरक्षण के माध्यम से नहीं, बल्कि अमीर-ग़रीब के पैमाने पर हल करना चाहती है. इसके लिए उसने ग़रीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या का सहारा लिया, जिसे निर्धारित करने के चक्कर में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने ज़मीनी हक़ीक़त ख़ारिज कर दी. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपये और शहरी क्षेत्र में 32 रुपये से ज़्यादा कमाने वाले को ग़रीबी रेखा के ऊपर बता दिया. किसी को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस धनराशि में एक व्यक्ति को एक दिन गुज़ारने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं. कांग्रेस ने एक दूसरा शिगूफा भी छोड़ा है, वह है अल्पसंख्यक समुदाय की दयनीय स्थिति का. इस वर्ग के लिए वह आरक्षण की नीति अपनाने के लिए तैयार है, जिसका पार्टी में विरोध भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पार्टी में मज़बूत पकड़ रखने वाले नेताओं की जाति-वर्ग पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा. अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल अल्पसंख्यकों को उसी हिस्से में आरक्षण देकर वे उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने का वायदा भी पूरा कर लेंगे.

वाराणसी आदिवासियों की संख्या नगण्य होने के बाद भी आदिवासी बहुल ज़िलों में क्यों शामिल हो गया, वहीं चंदौली आदिवासियों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद आदिवासी बहुल ज़िलों की सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया, जबकि इसी ज़िले से उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद ने अपना सिर उठाया था?

सामाजिक न्याय के सबसे अहम और मज़बूत मुद्दे पर सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियां असफल साबित हुई हैं. हम बात कर रहे हैं भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासियों की, जिनकी कोई जाति नहीं है और न कोई धर्म. जो पेट की भूख मिटाने के लिए वनों और पहाड़ों को अपना घर मान बैठे. उन्हें प्रमाण के लिए न किसी कागज के टुकड़े की ज़रूरत थी और न कंक्रीट से बनी दीवारों की, लेकिन यही उनके जीवन के लिए अभिशाप बन गया. उद्योगपतियों, नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों की अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा ने आदिवासियों को उनके घरों से ही बेदखल कर दिया. फिर भी वे अपने स्वभाव के अनुसार संघर्ष करते रहे. खुद को सभ्य बताने वाली सामंती ताकतों ने उन्हें हिंसक बनने पर मजबूर कर दिया. सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सामाजिक न्याय का खेल सिर्फ़ काग़ज़ों और मीडिया के कैमरों तक सीमित है. यही वजह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है. इसका जीता-जागता नमूना उत्तर प्रदेश के क़रीब बीस लाख आदिवासी हैं. हालात यह है कि अब वे न आदिवासी रह गए हैं और न दलित. यह खेल हुआ सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों के नुमाइंदों के कारण. इनमें देश की सत्ता में सबसे अधिक समय तक क़ाबिज़ रही कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, जिसके युवराज इन दिनों दलितों एवं आदिवासियों के घरों में जाकर पूड़ी-सब्जी खा रहे हैं और रात गुज़ार रहे हैं. क्या उन्होंने कभी उत्तर प्रदेश के आदिवासियों से पूछा कि वे पिछले एक दशक से सोनभद्र एवं मिर्जापुर समेत 13 ज़िलों में अपनी आबादी के आधार पर चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं?

वाराणसी आदिवासियों की संख्या नगण्य होने के बाद भी आदिवासी बहुल ज़िलों में क्यों शामिल हो गया, वहीं चंदौली आदिवासियों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद आदिवासी बहुल ज़िलों की सूची में क्यों नहीं शामिल किया गया, जबकि इसी ज़िले से उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद ने अपना सिर उठाया था? आख़िर क्या कारण हैं कि आज़ादी के छह दशकों बाद भी आदिवासियों को सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया? सोनभद्र, जहां सौ फीसदी आदिवासी हैं, वहां भी वे पंचायत प्रतिनिधि क्यों नहीं बन पा रहे हैं? आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर आदिवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होने जा रहा है. वजह यह कि केंद्र सरकार ने अभी तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के आंकड़े जारी नहीं किए हैं और न विधानसभा चुनाव से पहले इसके जारी होने की संभावना है. अगर राहुल गांधी वास्तव में समाज के हर तबके को सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने की कोशिश करनी चाहिए. उससे भी पहले उन्हें आदिवासियों को चुनाव लड़ने का अधिकार सुनिश्चित कराना चाहिए, तभी कांग्रेस की सामाजिक न्याय की नीति में लोगों का विश्वास बहाल होगा.

feedback@chauthiduniya.com

अवैध खनन को सरकारी संरक्षण

मिर्ज़ापुर का प्रशासन शायद भूल चुका है कि पत्थर के अवैध खनन के आरोप में जनपद के एक सेवानिवृत्त आईएएस को जेल जाना पड़ा था, तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी को निलंबित होना पड़ा था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित टीम ने कई पत्थर माफ़ियाओं को चिन्हित किया था और करोड़ों रुपये के इमारती पत्थर ज़ब्त किए थे. आख़िर वह भूले भी क्यों न, क्योंकि उक्त कार्रवाई प्रशासनिक पहल पर न होकर न्यायालय के भय से की गई थी. सबसे शर्मनाक बात यह है कि ज़ब्त किए गए पत्थर, गिट्टी, मौरंग और बोल्डर विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ग़ायब हो गए, किंतु सरकारी खजाने में एक पैसा नहीं पहुंचा. एक बार फिर न्यायालय के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा है, जिससे पत्थर माफियाओं की चौकड़ी में शामिल लोगों को सबक मिल सके. आश्चर्य तो तब होता है, जब वन विभाग वैधानिक रूप से प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर अनापत्ति देने में आनाकानी करता है, लेकिन अवैध खनन करने वालों के प्रति उसके सारे नियम-क़ानून शिथिल पड़ जाते हैं. विभाग पहले अवैध रूप से खनन किया गया पत्थर ज़ब्त करता है और फिर सौदा पट जाने पर करोड़ों रुपये के पत्थर अवैध खनन करने वालों को ही सौंप देता है. अवैध खनन में केवल वही विभाग शामिल नहीं हैं, जिनका इससे सीधे संबंध है, बल्कि ऐसी कई संस्थाएं हैं, जो वनोपज का इस्तेमाल करती हैं और राजस्व की चोरी में सहायक बनती हैं.

प्रावधान यह है कि वनोपज यानी पत्थर या मौरंग की रॉयल्टी का जमा होना जब तक सुनिश्चित न हो जाए, तब तक कार्यदायी संस्थाओं को ठेकेदार का भुगतान नहीं करना चाहिए. दूसरा विकल्प यह है कि कार्यदायी संस्था रायल्टी काटकर ठेकेदार को भुगतान करे. यह ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है कि यदि किसी स्तर पर रॉयल्टी पहले जमा हो गई हो तो वह उसे वापस ले ले.

प्रावधान यह है कि वनोपज यानी पत्थर या मौरंग की रॉयल्टी का जमा होना जब तक सुनिश्चित न हो जाए, तब तक कार्यदायी संस्थाओं को ठेकेदार का भुगतान नहीं करना चाहिए. दूसरा विकल्प यह है कि कार्यदायी संस्था रॉयल्टी काटकर ठेकेदार को भुगतान करे. यह ठेकेदार की ज़िम्मेदारी है कि यदि किसी स्तर पर रायल्टी पहले जमा हो गई हो तो वह उसे वापस ले ले. अधिकतर मामलों में होता यह है कि ठेकेदार रायल्टी की फ़र्ज़ी रसीद लगा देते हैं, खनिज विभाग की मिलीभगत से उसकी पुष्टि कर दी जाती है और राजस्व की चोरी धड़ल्ले से हो जाती है. इतना ही नहीं, विकास खंडों एवं ग्रामसभाओं द्वारा न के बराबर रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है, जबकि कार्यों का भुगतान प्राय: सरकारी दरों पर होता है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बरकछा स्थित दक्षिण परिसर भी रॉयल्टी जमा करने के मामले में आरोपों के घेरे में है.

पत्थर माफिया पहले तो चोरी-छिपे अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी करते थे, अब वे पहाड़ों और वन भूमि पर पोकलैंड और जेसीबी मशीनें लगाकर खनन कर रहे हैं और इतने सशक्त हो गए हैं कि उनके ट्रकों को पुलिस भी नहीं रोकती. पत्थर माफिया रोक के बावजूद ओवरलोड वाहनों का संचालन कर रहे हैं, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और आम आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अति महत्वाकांक्षी बाण सागर नहर निर्माण योजना अपना लक्ष्य अभी तक नहीं पा सकी है. योजना के तहत बड़े पैमाने पर की गई खुदाई की आड़ में भी माफियाओं को अवैध खनन के भरपूर मौके मिले. यह जांच का विषय है कि कुल कितनी मात्रा में पत्थर खोदकर निकाले गए, कितने की नीलामी हुई और कितनी रॉयल्टी सरकारी खजाने में जमा हुई. ऐसे पत्थरों के निस्तारण के नाम पर पहाड़ के पहाड़ गायब कर दिए गए. कुछ पत्थर माफियाओं ने तो निस्तारण के नाम पर क्रशर तक लगा लिए. योजना के तहत करोड़ों रुपये ख़र्च होने के बावजूद खेतों को एक बूंद पानी नहीं मिल पाया. अवैध खनन में अब एक नया नाम जुड़ा है प्रदूषण नियंत्रण विभाग, जो केवल वसूली कर रहा है. कुछ लोगों ने शिकायत की कि अवैध विस्फोट और वाहन संचालन से जनजीवन खतरे में पड़ गया है, मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया. जनपद के आदिवासी और मेहनतकश किसान एक बार फिर अदालती हस्तक्षेप का इंतजार कर रहे हैं, जैसा 1997 में हुआ था और जिससे उनकी समस्याओं का हल निकल सके. यदि अवैध खनन पर रोक न लगी तो शांत माना जाने वाला यह जनपद असामाजिक तत्वों के लिए तो स्वर्ग साबित हो जाएगा और अकूत वन-खनिज संपदा लुट जाएगी, जिसकी भरपाई पीढ़ियों तक नहीं हो पाएगी.

अमरेश मिश्र
feedback@chauthiduniya.com

निजी अस्पतालों में कितने लोगों का इलाज हो पाता है और बिजलीघर लगाने से कितने ग़रीबों के घरों में रोशनी आती है.

गुजरात बनाम बिहार

आर्थिक विकास की पोल खोलता मानव विकास

औद्योगीकरण और बढ़ती विकास दर एवं जीडीपी, फिर भी बच्चे भूखे और कुपोषित. बेरोज़गारी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और यहां तक कि घरों में शौचालय तक नहीं. मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2011 की कहानी कुछ ऐसी ही है. यह हाल उन राज्यों का है, जिनके विकास की चर्चा देश-विदेश में हो रही है. अमेरिका यहां के मुख्यमंत्रियों की पीठ थपथपा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आख़िर यह किसका विकास हो रहा है, इस आर्थिक विकास का मानव विकास में क्या योगदान है?

शशि शेखर

अमेरिका से प्रशंसा पा चुके नरेंद्र मोदी के लिए यह वाकई अच्छी ख़बर नहीं थी. मानव विकास सूचकांक 2011 की रिपोर्ट ने गुजरात को मानव विकास से संबंधित कुछ मामलों में बिहार से भी पीछे बताया, कुछ मामलों में बिहार और उत्तर प्रदेश को गुजरात से आगे. रिपोर्ट के मुताबिक़, औद्योगिक रूप से विकसित राज्य गुजरात में कुपोषण की दर सबसे अधिक है. गुजरात में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, फिर भी भूख और कुपोषण है. केंद्र सरकार से संबद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात के लगभग 45 फ़ीसदी बच्चे, जो 5 साल से कम उम्र के हैं, कुपोषण के शिकार हैं. वहीं राज्य के 70 फ़ीसदी बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं. दरअसल, यह रिपोर्ट अपने-आप में कई सारे सवाल खड़े करती है. मसलन, जब एक विकसित राज्य या आर्थिक विकास की बात होती है तो असल में वह किसका विकास होता है. बढ़े हुए उत्पादन से कितने ग़रीबों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल पाता है, निजी अस्पतालों में कितने लोगों का इलाज हो पाता है और बिजलीघर लगाने से कितने ग़रीबों के घरों में रोशनी आती है.

गुजरात के मुक़ाबले मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामलों में बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की स्थिति पहले से बेहतर होने की बात कही है, लेकिन यह भी माना है कि अन्य राज्यों की तुलना में स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है. कुपोषण और गंदगी अब भी एक बड़ी समस्या है. बिहार को ख़ुश होने के लिए कुछ और भी बातें इस रिपोर्ट में शामिल हैं, जैसे अन्य पिछड़े वर्ग के लोग बिहार की ऊंची जाति के लोगों से स्वास्थ्य सेवा मानकों के आधार पर बेहतर हालत में हैं या फिर बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों पर 2005-08 के मुक़ाबले अब 0.4 प्रतिशत ज़्यादा ख़र्च किया जा रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में यह बहुत कम है और इसे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करनी होगी.

मानव विकास सूचकांक 2011 की रिपोर्ट में दर्ज तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि किसी राज्य का आर्थिक विकास करना या उसका शोर मचाना वहां की जनता की ख़ुशहाली की गारंटी नहीं हो सकता. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट (मई 2011) के मुताबिक़, अब भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और देश के जीडीपी में इसका योगदान महज़ 2.71 फ़ीसदी है, वहीं 11 फ़ीसदी से भी ज़्यादा विकास दर दिखाकर बिहार सरकार गुलाबी तस्वीर पेश कर रही है. दूसरी ओर शिशु मृत्यु दर अभी भी यहां प्रति एक हज़ार पर 52 है और 2008 के आंकड़े के मुताबिक़, प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर प्रति एक हज़ार पर 298 थी.

मानव विकास सूचकांक	
आगे	पीछे
केरल	छत्तीसगढ़
दिल्ली	उड़ीसा
हिमाचल प्रदेश	बिहार
गोवा	मध्य प्रदेश
पंजाब	झारखंड

बहरहाल, यह रिपोर्ट बिहार जैसे राज्य के लिए किसी सीख से कम नहीं है. पिछले कुछ सालों से बिहार में तीव्र विकास दर हासिल करने की बात कही जा रही है. आंकड़ों की मदद से इसे साबित भी किया जाता रहा है. ऐसा भी नहीं है कि इन दावों को सिरे से ख़ारिज कर दिया जाए. दरअसल, नीतीश सरकार से पहले बिहार 15 सालों तक जिस हालात से गुजरा, उसके मुक़ाबले अब पिछले कुछ सालों में स्थितियां बदली हैं और इसी बदलती स्थिति का फ़ायदा अब बिहार सरकार उठा रही है यानी शून्य से शुरू करने वाली सरकार यह नहीं बताती कि असल में कितना विकास हुआ. इसके उलट वह शून्य के मुक़ाबले हुए विकास का प्रतिशत जनता के सामने रख रही है. उदाहरण के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट (मई 2011) के मुताबिक़, अब भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और देश के जीडीपी में इसका योगदान महज़ 2.71 फ़ीसदी है, वहीं 11 फ़ीसदी से भी ज़्यादा विकास दर दिखाकर बिहार सरकार गुलाबी तस्वीर पेश कर रही है. दूसरी ओर शिशु मृत्यु दर अभी भी यहां प्रति एक हज़ार पर 52 है और 2008 के आंकड़े के मुताबिक़, प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर प्रति एक हज़ार पर 298 थी. ज़ाहिर है, मानव विकास सूचकांक 2011 की रिपोर्ट में दर्ज तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि किसी राज्य का आर्थिक विकास करना या उसका शोर मचाना वहां की जनता की ख़ुशहाली की गारंटी नहीं हो सकता. ज़ाहिर है, यह रिपोर्ट बिहार सरकार के लिए भी एक सबक है. सबक यह कि आर्थिक विकास की अंधी दौड़ में जनता की मूल समस्याओं को भी याद रखना होगा और उनके समाधान के लिए ईमानदारी से काम करना होगा.

shashishekhar@chauthiduniya.com

बिहार

कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा

23 मई, 2009 को नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह को अपने पत्रांक संख्या-4610139 में कोशी पुनर्संरचना और पुनर्वास, कृषि प्रसंस्करण, ऊर्जा, ऋण सुधार, ग़रीबी मानक, सड़क निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी.

अभिषेक रंजन सिंह

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले यह मांग समय-समय पर उठती रही है. ख़ासकर लालू प्रसाद यादव के पंद्रह वर्ष के शासन के बाद जब सूबे में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो यह मांग बेहद तेज़ हो गई. सुशासन के वायदे और बात-बात पर इसकी दुहाई देने वाले नीतीश कुमार के मुताबिक़ आज़ादी के बाद से ही केंद सरकार ने बिहार में विकास के नाम पर सौतेला व्यवहार किया. हालत तब और ख़राब हो गई, जब बिहार से अलग होकर पृथक झारखंड राज्य बन गया. तमाम खनिज संपदाएं झारखंड के हिस्से में चली गई और भूख, बेबसी व ग़रीबी शेष बिहार के हिस्से में रह गई. नीतीश कुमार ने जब प्रदेश की सत्ता संभाली तो उनकी प्राथमिकता में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग सबसे ऊपर थी.

23 मई, 2009 को नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह को अपने पत्रांक संख्या-4610139 में कोशी पुनर्संरचना और पुनर्वास, कृषि प्रसंस्करण, ऊर्जा, ऋण सुधार, ग़रीबी मानक, सड़क निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी. प्रधानमंत्री कार्यालय से 3 जून, 2009 को इस पत्र की प्राप्ति की सूचना जारी की गई और उसे संबंधित विभाग को अग्रसारित कर दिया.

उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(एनडीए) के संसद सदस्यों की ओर से 23 मार्च, 2011 को एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा, जिसमें बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 1912 में बिहार-उड़ीसा बंटवारा और वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड का अलग होना और उसके बाद की बदली परिस्थितियां, ग़रीबी, अशिक्षा, ढांचागत विकास का आभाव जैसी कई बुनियादी ज़रूरतों के मद्देनज़र राज्य को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की गई थी. इस ज्ञापन में इस बात पर ख़ास ज़ोर दिया गया कि झारखंड के बनने से बिहार के राजस्व को काफ़ी क्षति हुई है.

राज्य के विभाजन के बाद खनिज संपदा, बड़े कल कारख़ाने झारखंड के हिस्से में चले गए. कहा यह जाने लगा कि बिहार में सिर्फ़ आलू और बालू ही बच गए. शेष संपदा झारखंड में चली गई जिसका ख़ामियाज़ा बिहार के हर तबक़े को उठाना पड़ा और राज्य से लोगों का पलायन शुरू हो गया. हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते चले गए जो आज तक नहीं सुधरे हैं. ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए और बिहार इसके लिए सभी ज़रूरी शर्तों को पूरा भी करता है. उल्लेखनीय है कि विशेष राज्य वाली श्रेणी में जिस राज्य को शामिल कर लिया जाता है, वहां कोई कारख़ाना या उद्योग लगाने वालों को कई करों में भारी रियायत और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य सरकार को बड़ी छूट मिल जाती है.

फ़िलहाल देश के ग्यारह राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है. इसमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम शामिल है. अपने ज्ञापन में नीतीश कुमार ने कहा है कि वित्त आयोग ग्यारहवीं और बारहवीं वित्तीय अवधि के दौरान बिहार में ***पर कैपिटा टोटल रेवैन्यू*** 2,364 और 2,122 रुपये थी, जबकि दूसरी तरफ़ हरियाणा में ***पर कैपिटा टोटल रेवैन्यू*** 6,066 रुपये और 3,719 रुपये आंकी गई थी. जबकि हिमाचल प्रदेश में ***पर कैपिटा टोटल रेवैन्यू*** 7,952 रुपये और 4,719 रुपये थी. यहां ग़ौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है. आशय यह कि नीतीश कुमार की मांग को अगर किनारे में रख कर भी देखा जाए तो यह सवाल उठता है कि फ़िलहाल योजना आयोग ने जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया है क्या उसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है? वहीं बिहार जैसे बड़े और पिछड़े प्रदेश में अगर विकास की असीम संभावनाएं हैं तो उसे केंद्र सरकार विशेष राज्य की हैसियत क्यों नहीं देती, ताकि यहां हर स्तर पर प्रगति हो. तमाम ऐसे मामले हैं जिनसे यह पता चलता है कि बिहार उन कई लाभों से वंचित रहा है, जिसका वह हक़दार रहा है. जैसे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को क्रमशः बुंदेलखंड सूखा राहत पैकेज के तहत वर्ष 2009-10 में 332.28 करोड़ व 361.51 करोड़ रुपये, जबकि वर्ष 2010-11 में 468.69 करोड़ व 638.93 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2011-12 में 60 करोड़ व 89.46 करोड़ की सहायता दी गई है. जबकि, बिहार में सूखा और बाढ़ की वजह से कई ज़िले प्रभावित हुए. यहां मानवीय क्षति से लेकर फ़सल, पशुपालन और बाग़वानी को काफ़ी नुक़सान पहुंचा, लेकिन जो आर्थिक मदद बिहार को दी गई वह प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुक़सान की बनिस्बत कम थी. बिहार की प्राकृतिक आपदाओं को देखकर चीन का एक प्रसंग याद आता है. बिहार में कोशी नदी तरह ही चीन में हुआंग-हो नदी हर साल भयंकर तबाही मचाती थी. तब वहां की जनता आज़िज़ होकर सरकार से राहत मदद लेने से इनकार कर दिया. उनकी मांग थी कि हमें अस्थायी राहत नहीं, बल्कि बाढ़ से स्थायी निदान चाहिए. नतीजतन वहां की सरकार ने जनता की इस मांग को पूरा करते हुए हुआंग-हो नदी परियोजना पर योजनाबद्ध तरीक़े से काम किया. नतीजतन कल तक शोक कहलाने वाले इस इलाके में आज ख़ुशहाली छाई हुई है. अगर बिहार की बात करें तो हर साल भारी तबाही मचाने वाली कोशी नदी की उफान रोकने के लिए आज़ादी के 64 साल बाद भी कोई उपाय नहीं किए गए है. हालांकि, कोशी परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपये की लूट ज़रूर मची, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहीं. आख़िर क्या वजह है कि केंद्र सरकार नेपाल सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक बात नहीं करती. पिछले दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई भारत आए थे, लेकिन बाढ़ नियंत्रण पर कोई बातचीत नहीं की गई. केंद्र सरकार के इस रवैये से यही ज़ाहिर होता है कि वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार तक नहीं करना चाहती.

arsingh@chauthiduniya.com

डॉ. अयूब का कहना है कि पीस पार्टी लोकतांत्रिक मोर्चा का एक महत्वपूर्ण घटक है. यह मोर्चा प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा. इसमें से क़रीब 250 सीटों पर पीस पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव

पीस पार्टी की अहम भूमिका होगी

फ़िरदौस ख़ान

आज़ादी के छह दशकों बाद भी देश में मुस्लिम नेतृत्व खड़ा नहीं हो पाया है. देश में एक भी सर्वमान्य मुस्लिम नेता ऐसा नहीं है, जिस पर मुसलमान भरोसा जता सकें. इसके कई कारण हैं. पहला यह कि कोई भी सियासी दल नहीं चाहता कि मुस्लिम नेतृत्व पैदा हो. दूसरा यह कि मुसलमानों के हक़ की बात करने के दावे करने वाले सियासी और ग़ैर सियासी दल चुनाव के दौरान भाजपा जैसी पार्टियों से मिल जाते हैं. इसकी वजह से मुसलमान इन मुस्लिम रहनुमाओं पर भरोसा नहीं कर पाते. ज़्यादातर मुस्लिम दल चुनाव में वोट बांटने का ही काम करते हैं. इससे मुसलमानों के वोट बिखर जाते हैं और वे निर्णायक भूमिका नहीं निभा पाते. ऐसे में मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए पीस पार्टी आगे आई है.

पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. मुहम्मद अयूब का कहना है कि आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी राजनीतिक दल आए हैं, सभी का मक़सद सत्ता में आना ही रहता है. सरकारों ने जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने की बजाय उनकी अनदेखी ही की. कुछ सियासी दल सिर्फ़ चुनाव के वक़्त ही जनता के बीच जाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए गठजोड़ करते हैं और इसके बाद गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं. ये सियासी दल क़ौम के बुद्धिजीवियों और शिक्षित तबक़े का समर्थन हासिल करने में भी नाकाम रहते हैं. ऐसे माहौल में मुसलमानों को उनका हक़ दिलाने के लिए एक मज़बूत सियासी दल की ज़रूरत महसूस की गई. ग़ौरतलब है कि माइनारिटीज ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड इंटिग्रेशन के तत्वावधान में 2 दिसंबर, 2007 को लखनऊ में आयोजित दानिश्वरों एवं उलेमाओं की एक बैठक में डॉ. मुहम्मद अयूब ने संपूर्ण नेतृत्व की एक मज़बूत सियासी पार्टी बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था. इसके बाद 10 फरवरी, 2008 को लखनऊ में हुई अगली बैठक में पीस पार्टी की स्थापना की गई. डॉ. मुहम्मद अयूब को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया. पीस पार्टी ने 3 अप्रैल को मऊ , 22 मई को ख़लीलाबाद, 26 जून को डुमरियागंज, 23 जुलाई को पड़रौना और 24 अगस्त को बिजनौर में रैलियां कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

पीस पार्टी अभी ख़ुद को ठीक से स्थापित भी नहीं कर पाई थी कि इसके अध्यक्ष डॉ. मुहम्मद अयूब पर भगवा को बढ़ावा देने और पार्टी के टिकट बाहुबलियों को बेचे जाने के गंभीर आरोप लगने लगे और वह दो फाड़ हो गई. पार्टी से इस्तीफ़ा देने के बाद कई पदाधिकारियों ने मिलकर राष्ट्रीय पीस पार्टी का गठन कर लिया. राष्ट्रीय पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुर्रहमान अंसारी का कहना है कि अन्य सियासी दलों की तरह पीस पार्टी भी भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है. पहले यह तय हुआ था कि पीस पार्टी में कोई माफ़िया शामिल नहीं होगा. वह जनता को इंसाफ़ दिलाने का काम करेगी, लेकिन डॉ. अयूब पार्टी के उद्देश्य से भटक गए. उन्होंने निष्ठावान पार्टी कार्यकर्ताओं को उच्च पदों पर भेजने की बजाय माफ़ियाओं को बड़े-बड़े पदों पर आसीन कर दिया. पीस पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव एवं राष्ट्रीय पीस पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अहमद फ़ुरक़ान अलवी का कहना है कि पीस पार्टी की ग़लत नीतियों की वजह से ही बाराबंकी, गोंडा, सीतापुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं सहित कई अन्य ज़िलों के पदाधिकारी इस्तीफ़ा देकर राष्ट्रीय पीस पार्टी में शामिल हो गए. इस बारे में डॉ. मुहम्मद अयूब का कहना है कि राष्ट्रीय पीस पार्टी का गठन एक साज़िश के तहत किया गया है. यह साज़िश है मुसलमानों के सियासी नेतृत्व को मज़बूत होने से रोकने की. उन्होंने कहा कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव बाक़ायदा प्रेस कांफ्रेंस करके यह ऐलान कर चुके हैं कि पीस पार्टी का उनकी समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है, जबकि यह सरासर झूठ है. उन्होंने राष्ट्रीय पीस पार्टी के अध्यक्ष अब्दुर्रहमान पर आरोप लगाया कि वह समाजवादी पार्टी के इशारे पर मुस्लिम क़यादत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं. भाजपा से करोड़ों रुपये लेने के आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते हुए डॉ. अयूब ने कहा कि उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये आरोप लगाए गए. उन्होंने ग़लत रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले 10 अख़बारों के ख़िलाफ़ मुक़दमे कर रखे हैं.

डॉ. अयूब का कहना है कि पीस पार्टी लोकतांत्रिक मोर्चा का एक महत्वपूर्ण घटक है. यह मोर्चा प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा. इसमें से क़रीब 250 सीटों पर पीस पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे. अन्य सीटों पर पार्टी लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी. लोकतांत्रिक मोर्चा में पीस पार्टी के अलावा भारतीय समाज पार्टी, क़ौमी एकता दल, इंडियन जस्टिस पार्टी, भारतीय लोकहित पार्टी, अति पिछड़ा वर्ग महासंघ, क़ौमी मूवमेंट कांफ्रेंस और राष्ट्रीय लोकदल आदि शामिल हैं. राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन के बारे में उनका कहना है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो वह इसका विरोध करेंगे. उनका आरोप है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा मुसलमानों का अहित किया है. भाजपा जहां हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर अपना हित साधने में लगी रहती हैं. ऐसे हालात में मुसलमान कहां जाएं? उन्हें एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है, जो उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोर्चा की सरकार बनने पर किसी अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. इसके अलावा दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशों को लागू किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 18.5 फ़ीसदी है. 70 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी तादाद 20 फ़ीसदी या इससे ज़्यादा है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 20, पूर्वी उत्तर प्रदेश की 10, मध्य उत्तर प्रदेश की 5 और बुंदेलखंड की एक सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 30-45 फ़ीसदी के बीच है. पीस पार्टी लगातार जनसंपर्क कर मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने में लगी है. पीस पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 संसदीय क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे. उसके एक भी उम्मीदवार को जीत हासिल नहीं हो पाई, लेकिन पार्टी ने चार फ़ीसदी वोट पाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. पीस पार्टी की अहमियत इस बात से आंकी जा सकती है कि विभिन्न सियासी दलों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की सदर सीट से निर्दलीय विधायक अखिलेश सिंह ने दावा किया था कि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के पांच दर्जन से ज़्यादा विधायक पीस पार्टी के लगातार संपर्क में हैं और वे कभी भी उसमें शामिल हो सकते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं कि पीस पार्टी अब बाहुबलियों का दल बनती जा रही है. अखिलेश सिंह के बाद फ़ैज़ाबाद के बाहुबली विधायक जितेंद्र सिंह उर्फ़ बब्लू भी बसपा छोड़कर पीस पार्टी में शामिल हो चुके हैं. वह बसपा में अपनी उपेक्षा से परेशान थे. वह पहले कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने थे. बाद में कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने 2007 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत गए. क़ाबिले-ग़ौर यह भी है कि पीस पार्टी पसमांदा मुसलमानों की बात करती है. पहले कुल मुस्लिम समाज की बात होती थी, लेकिन अब मुस्लिम समाज भी कई तबक़ों में विभाजित नज़र आ रहा है, जैसे शिया, सुन्नी और फिर सुन्नी मुसलमानों में अगड़ी जातियों में शेख़, सैयद, पठान और पिछड़ी जातियों में जुलाहा, क़साई, तेली आदि शामिल हैं. इनके अपने-अपने संगठन हैं. इनमें समानता यही है कि सबकी पीड़ा एक है और सबकी मांगें भी एक जैसी हैं. सभी संगठनों के नुमाइंदों का मानना है कि सभी सियासी दलों ने मुसलमानों को सिर्फ़ वोट बैंक के नज़रिए से देखा है. किसी ने ज़मीनी स्तर पर उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया. कहने को तो मुसलमानों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन उनका फ़ायदा मुसलमानों को नहीं मिला. दरअसल, देश में सामाजिक बदलाव सियासी फ़ैसलों पर निर्भर करता है. देश के समग्र विकास के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों को भी मुख्य धारा में शामिल कर उनका विकास किया जाए. जब तक भारत की यह 15 फ़ीसदी आबादी पिछड़ी रहेगी, तब तक देश की तरक्क़ी संभव नहीं है. हालांकि पीस पार्टी मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में शामिल कराने का वादा कर रही है, लेकिन देखना यह है कि वह जिन वादों और दावों को लेकर आगे बढ़ रही है, उन पर अमल कर पाएगी या फिर वह भी दूसरी सियासी पार्टियों की तरह सत्ता की सियासत तक सिमट कर रह जाएगी?

firdaus@chauthiduniya.com

संसद में मुसलमानों की नुमाइंदगी

संसद में मुसलमानों की नुमाइंदगी चिंताजनक है. लोकसभा के कुल 545 सांसदों में से 29 सांसद मुस्लिम हैं. इनमें कांग्रेस के कुल 206 सांसदों में से 11 मुस्लिम हैं, जबकि भाजपा के कुल 116 में से मात्र एक ही सांसद मुस्लिम है. इसी तरह राज्यसभा में कुल 244 सांसदों में से सिर्फ़ 25 सांसद मुस्लिम हैं. इनमें कांग्रेस के कुल 72 सांसदों में से नौ मुस्लिम हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कुल 51 सांसदों में से मात्र एक सांसद मुस्लिम है. 2001 की जनगणना के मुताबिक़, देश की आबादी में मुस्लिम 13.4 फ़ीसदी हैं, जबकि संसद में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ़ 6.84 फ़ीसदी है.

मेरी दुनिया.... चिंतित सोनिया !

शेखावाटी की नवलगढ़ तहसील के कटरथला गांव निवासी कालू भाट की कहानी भी नीलम जैसी है. कालू भी बचपन से ही विकलांग है.

सोलर लैंप प्रोजेक्ट

ज़िंदगी संवारती रोशनी

ग़रीबी, विकलांगता और बेरोज़गारी की मार जिन लोगों पर पड़ती है, उनके लिए एक ख़ुशहाल जीवन की कल्पना करना बेमानी हो जाता है, लेकिन अगर सोच सही हो और सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो बदहाल ज़िंदगी को भी ख़ुशहाल बनाया जा सकता है. शेखावाटी के बेरोज़गार एवं विकलांग युवकों को ही लें, कल तक ज़िंदगी इनके लिए बदरंग और अंधकारमय थी, लेकिन मोरारका फाउंडेशन के एक प्रयास ने इनकी ज़िंदगी में इंद्रधनुषी रंग भर दिए और रोशनी भी.

राजेश एस कुमार

बचपन से ही विकलांगता से अभिशप्त लोग हमेशा किसी अन्य की मदद के मोहताज रहते हैं. उनके लिए न कोई सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं और न उन्हें सहारा देने के लिए परिवारीजन ही आगे आते हैं. ऐसे में उनका जीवन अभिशप्तता के उस जाल में उलझ जाता है, जिससे बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन होता है. ऐसे में मोरारका फाउंडेशन की महत्वाकांक्षी सोलर लालटेन परियोजना उम्मीद की किरण लिए पूरे परिदृश्य को किस तरह बदल रही है, यह बताने की शुरुआत हम नवलगढ़ के घोड़ीवारा से करते हैं. ऊपरी तौर पर तो यह एक सामान्य गांव की परिभाषा गढ़ता दिखाई देता है, लेकिन जब हम इस गांव की नीलम कंवर की दास्तां सुनते हैं तो एक नई और अनोखी तस्वीर दिखाई देती है. नीलम कंवर के पास न तो ज़मीन का कोई टुकड़ा है और न परिवार चलाने के लिए दो जून की रोटी का इंतज़ाम. उसकी मुश्किलें यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं. नीलम अब तक एक आशियाने के लिए तरस रही है और इससे भी बड़ा घाव विकलांगता का. वह बचपन से ही पोलियोग्रस्त है. ऐसे में उसका दु:ख-दर्द हर कोई समझ सकता है, पर यहां कहानी त्रासदी और अभिशाप की नहीं, बल्कि उस वरदान की है, जो उसे मोरारका फाउंडेशन से इस योजना के रूप में मिला है. नीलम की ज़िंदगी में मोरारका फाउंडेशन ने ख़ुशहाली की दस्तक दी है. दरअसल मोरारका फाउंडेशन ने विकलांग युवाओं के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और उसे रोज़गार का माध्यम बनाने की एक योजना बनाई, जिसके तहत नीलम का चयन हुआ.

योजना के अंतर्गत फाउंडेशन की ओर से नीलम को एक सौर ऊर्जा पैनल दिया गया और 25 सौर ऊर्जा चालित लालटेन. नीलम को सौर ऊर्जा लालटेन के बारे में बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया गया. इससे उसे न सिर्फ़ रोज़गार मिला है, बल्कि घोड़ीवारा के आसपास के गांवों के लोगों को भी अंधेरे से निजात मिल गई. इलाक़े के ज़्यादातर गांवों में बिजली आपूर्ति नियमित नहीं है, इसलिए छात्र और किसान नीलम से सौर ऊर्जा चालित लालटेन किराए पर ले जाते हैं. दुकानों के अलावा शादियों-समारोहों के सीजन में भी सौर लालटेनों की मांग बढ़ जाती है. इसके एवज में नीलम को प्रति लालटेन एक रात के 10 रुपये मिल जाते हैं. नीलम के मुताबिक़, वह लालटेन किराए पर देकर हर महीने लगभग दो हज़ार रुपये कमा लेती हैं. इसके साथ ही नीलम सौर ऊर्जा के उपयोग से संबंधित जानकारी जुटाकर गांव के लोगों को जागरूक भी कर रही हैं. अगर कोई नीलम से उनकी मुश्किलों के बारे में पूछता है तो वह उसे अपनी इस क़ामयाबी की दास्तां सुना देती हैं. नीलम बताती हैं कि फाउंउेशन की इस पहल ने किस तरह उनके जीवन के अभिशापों को वरदान में तब्दील कर दिया.

मोरारका फाउंडेशन का यह कारवां कटरथला में नहीं रुकता. यह एक गांव से दूसरे गांव होते हुए हर उस असहाय युवक-युवती तक पहुंचता है, जिसे सहारे और आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है. इसी उद्देश्य से इस बार यह कारवां जा पहुंचा कोलसिया गांव में. इस गांव के राधेश्याम की कहानी नीलम और कालू से अलग नहीं है. राधेश्याम भी पोलियो की चपेट में है. पिता का साया सिर से उठ चुका है. इससे उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई.

शेखावाटी की नवलगढ़ तहसील के कटरथला गांव निवासी कालू भाट की कहानी भी नीलम जैसी है. कालू भी बचपन से ही विकलांग है. ज़िम्मेदारियों के नाम पर उसके परिवार में 8 सदस्य हैं. वह 9 भाई-बहनों में सबसे बड़ा है. ग़रीबी की वजह से पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी. ज़मीन के नाम पर भी कुछ नहीं है. पिता मज़दूरी करके किसी तरह परिवार चला रहे थे. नौ सदस्यों वाले इस परिवार के भरण-पोषण का भार कालू पर ही है. एक दौर ऐसा भी आया, जब कालू अपने इस असहाय और नीरस जीवन से तंग आकर कोई भी फ़ैसला नहीं कर पा रहा था. इससे पहले कि कालू किसी नतीजे पर पहुंचता, फाउंडेशन ने अपनी इस योजना में उसे भी भागीदार बना लिया. कालू को भी एक सौर ऊर्जा पैनल दिया गया और प्रशिक्षित किया गया. अब कालू को प्रति लालटेन एक रात के 10 रुपये मिल जाते हैं. वह छात्रों को किराए में रियायत भी देता है. आज कालू अपने इस नए रोज़गार से काफी ख़ुश है. अब वह अपने परिवार की सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ उठाने के लायक़ हो गया है. आत्मनिर्भर हो चुका कालू अपनी इस नई ज़िंदगी का श्रेय मोरारका फाउंडेशन को देता है. कालू के जीवन का उजाला पूरे परिवार को रोशन कर रहा है. लालटेन को किराए पर देने से कालू को जो आय होती है, उससे वह अपने भाई-बहनों को पढ़ाता है. वह चाहता है कि उसका परिवार उसी की तरह अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे. फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए कालू की मां बनारसी कहती हैं कि इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की, अब हम बहुत ख़ुश हैं.

मोरारका फाउंडेशन का यह कारवां कटरथला में नहीं रुकता. यह एक गांव से दूसरे गांव होते हुए हर उस असहाय युवक-युवती तक पहुंचता है, जिसे सहारे और आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है. इसी उद्देश्य से इस बार यह कारवां जा पहुंचा कोलसिया गांव में. इस गांव के राधेश्याम की कहानी नीलम और कालू से अलग नहीं है. राधेश्याम भी पोलियो की चपेट में है. पिता का साया सिर से उठ चुका है. इससे उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई. कहने के लिए तो राधेश्याम दसवीं पास है, लेकिन यह आज के स्पर्धा भरे युग में कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है. नतीजतन, वह बेरोज़गारी की मार का शिकार था. पांच बहनों और मां की ज़िम्मेदारी भी विकलांग राधेश्याम पर है. अपने दोनों पैर गंवा चुके राधेश्याम के कंधों पर इतनी सारी ज़िम्मेदारियों का बोझ है कि अच्छा- खासा कमाने वाला भी हार मान जाए, लेकिन इससे पहले कि उसे किसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता, मोरारका फाउंडेशन की इस महत्वाकांक्षी योजना ने उसके जीवन में दस्तक दी. यही दस्तक राधेश्याम को एक मुकम्मल मंजिल तक ले गई. सौर लैंप योजना के तहत राधेश्याम को भी 25 सौर लालटेन और एक सौर ऊर्जा पैनल मिला. इसके अलावा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विकलांगता उसकी पढ़ाई के रास्ते में रोड़ा न बने, फाउंडेशन ने उसे ट्राई साइकिल दी. अब वह आसानी से कहीं भी आ-जा सकता है. फाउंडेशन के प्रयासों का नतीजा है कि आज राधेश्याम बाकायदा स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है. पढ़ाई के साथ-साथ वह लालटेन किराए पर देता है, जिससे उसे हर माह लगभग दो-तीन हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती है और वह न सिर्फ़ अपने परिवार का भरण-पोषण आसानी से कर लेता है, बल्कि स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है. जाहिर है, अब उसे मदद के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता.

मोरारका फाउंडेशन की इस विकास यात्रा के तीन प्रमुख नायक नीलम कंवर, कालू भाट और राधेश्याम आज मिसाल बनकर पूरे नवलगढ़ में चर्चा का विषय बने हुए हैं. लोग आज तीनों की बदली हुई ज़िंदगी देखकर हैरान हैं और ख़ुश भी. इन तीनों की आंखों में एक बेहतर भविष्य का जो सपना पल रहा था, उसे साकार किया एम आर मोरारका फाउंडेशन ने. फाउंडेशन ने अपने इस प्रयोग की सफलता को देखते हुए आसपास के गांवों में भी नीलम, राधेश्याम और कालू जैसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम शुरू कर दी है. इसके लिए इन तीनों के इस नए रोज़गार का प्रचार किया जा रहा है, पर्चे आदि बांटे जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना से लाभांवित हों. इतना ही नहीं, अब तो नवलगढ़ तहसील के सभी गांवों को सौर ऊर्जा क्षेत्र बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है. मोरारका फाउंडेशन ने अपने अभियान के ज़रिए कई और विकासपरक कार्य किए हैं. पहला काम यह कि बेरोज़गार एवं विकलांग युवाओं को रोज़गार दिलाना. दूसरा, उन लोगों का नज़रिया बदलना, जो अपनी शारीरिक अक्षमता को अभिशाप समझते हैं. इसके अलावा सौर ऊर्जा को रोज़गार के साधन में बदलने का काम एक नसीहत है उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जहां आज भी बिजली की व्यवस्था नहीं है. शाम होते ही अंधेरे के आगोश में लुप्त हो जाने वाले इन गांवों में अगर यह योजना लागू की जाती है तो न सिर्फ़ वहां रोशनी फैलेगी, बल्कि हर गांव के कालू, नीलम और राधेश्याम जैसे विकलांग, बेरोज़गार और बेसहारा लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद भी मिलेगी.

rajeshy@chauthiduniya.com

समाजवाद कहता है, इस तरह की प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए. निजी संपत्ति नहीं रहने देनी चाहिए. सारी ज़मीन का, कारख़ाने का या पूंजी का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए.

यूरोप की जनता ने इराक युद्ध के विरुद्ध भी प्रदर्शन किया था और मई 1968 में फ्रांस की जनता ने डी गुएला के विरुद्ध भी सफल विद्रोह किया था.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

बढ़ती हुई पूंजी का अप्रत्यक्ष रूप

आप अपने से पहला प्रश्न यह पूछिए कि दैनिक जीवन में यह असमान वित्त वितरण आपको खटकता कहां है? उत्तर स्पष्ट है. आप आवश्यक सामान ख़रीदने बाज़ार जाते हैं. वहां आप आटा, दाल, गोभी, मटर, घी, तेल इत्यादि खाने का सामान ख़रीदते हैं. कपड़ा, धोती, कोटिंग, शर्टिंग, टोपी इत्यादि पहनने के लिए ख़रीदते हैं. इसी तरह नाटक, सिनेमा की टिकटें मनोरंजन के लिए ख़रीदते हैं. या बीमार हो जाएं तो डॉक्टर को बुलाकर फीस देते हैं और इलाज कराते हैं. या क़ानूनी अड़चन आ जाए तो किसी वकील को फीस देते हैं, इत्यादि. अनेक चीज़ों में या कामों में आप ख़र्च करते हैं. आप विश्लेषण करके देखें तो ज्ञात होगा कि जो चीज़ें आप ख़रीदते हैं या जिनकी भी सेवाओं का मूल्य आप देते हैं, उस रकम में से कुछ भाग आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी दे चुके हैं, जिसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया. अब आप मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की असली क़ीमत से ज़्यादा देने में प्रसन्न नहीं रहता और विश्लेषण से जब आपको पता चलता है कि जो आपको वे चीज़ें या सेवाएं अभीष्ट हैं तो उन–उन पूंजीपतियों के नफे का भाग आपको हर क़ीमत में और हर सेवा के बदले देना ही पड़ता है. यही पूंजीवादी प्रथा का आधार स्तंभ है. बिना कुछ किए ही इन पूंजीवादियों को हर चीज़ में, जो आपने ख़रीदी है और उसकी क़ीमत चुकाई है, उसमें उन्हें भाग मिल रहा है.

समाजवाद कहता है, इस तरह की प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए. निजी संपत्ति नहीं रहने देनी चाहिए. सारी ज़मीन का, कारख़ाने का या पूंजी का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए. यानी सब कारख़ाने– फैक्ट्रियां इत्यादि किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति न रहकर सारे राष्ट्र के हो जाएं. तो फिर जो भी क़ीमत आप वस्तुओं की चुकाएंगे, उसमें किसी अन्य व्यक्ति का मुनाफ़ा छुपा हुआ नहीं होगा. इसमें आपत्ति उठाने वाले कहते हैं, ऐसा हो कैसे सकता है? सारे कारख़ाने, तमाम फैक्ट्रियां राष्ट्र चला कैसे सकेगा? और वह उपयुक्त रूप से चला सके, इसकी गारंटी क्या है? आप विचार कीजिए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बहुत से उद्योग राष्ट्र चला रहा है. देखिए, वे ठीक चल रहे हैं कि नहीं? डाक तार विभाग राष्ट्र चला रहा है. रेलवे–ट्रेन राष्ट्र चला रहा है. फौजें, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, टेलीफोन, सड़कें, पुल, बिजली, गैस इत्यादि अनेक विभाग राष्ट्र के अधीन हैं. और आप या हम किसी भी प्रकार से दु:खी नहीं हैं. क्यों न राष्ट्र इसी तरह से अन्य उद्योग, कारखाने और सेवाएं भी अपने क़ब्ज़े में लेकर उनका यथोचित संचालन करे? राष्ट्र द्वारा चलाए हुए कार्यों में नफे या मुनाफ़े का उसूल नहीं रहता. डाक विभाग को ही लीजिए. 15 नए पैसे में आपका पत्र भारत के किसी भाग से किसी भी भाग में पहुंचा दिया जाता है. पोस्टकार्ड 5 नए पैसे में ही पहुंचा दिया जाएगा. बंबई से कलकत्ता या दिल्ली से त्रिवेंद्रम पत्र पहुंचाने में डाक विभाग का जो व्यय होता है, वह व्यय बंबई शहर में एक जगह से दूसरी जगह पत्र पहुंचाने के व्यय से कई गुना ज़्यादा है, तो भी सबका औसत निकाल कर 15 नए पैसे तय कर लिए गए. अब यही कार्य कोई निजी कंपनी करे तो शायद वह बंबई में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्र पहुंचाने जैसा काम करे, जिसमें कि उसे एक नया पैसा फी पत्र भी ख़र्च न करना पड़े और सुदूर के पत्र पहुंचाने का काम न भी करे अथवा ज़्यादा शुल्क लेकर करे. कुछ भी हो, निजी कंपनी ठीक मुनाफ़ा लिए बिना कोई काम करेगी नहीं. परिणाम होगा औसत में 15 नए पैसे की जगह शायद आपको 16 नए पैसे या 20 नए पैसे अपने पत्र पहुंचाने में ख़र्च करने पड़ें.

बंबई शहर में एक जगह से दूसरी जगह पत्र पहुंचाने के व्यय से कई गुना ज़्यादा है, तो भी सबका औसत निकाल कर 15 नए पैसे तय कर लिए गए. अब यही कार्य कोई निजी कंपनी करे तो शायद वह बंबई में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्र पहुंचाने जैसा काम करे, जिसमें कि उसे एक नया पैसा फी पत्र भी ख़र्च न करना पड़े और सुदूर के पत्र पहुंचाने का काम न भी करे अथवा ज़्यादा शुल्क लेकर करे. कुछ भी हो, निजी कंपनी ठीक मुनाफ़ा लिए बिना कोई काम करेगी नहीं.

जो आवश्यक उद्योग या सेवाएं राष्ट्र चलाए, उन्हें सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे नियम–क़ानून बना दिए जाएं, जिनसे दूसरा कोई उस काम को न करे. क्योंकि मान लीजिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी पत्र पहुंचाने का काम करे तो वह 15 पैसे की जगह 10 या 8 पैसे में ही निकटस्थ तमाम स्थानों को पत्र पहुंचाने का काम कर लेगी. फिर दूर के पत्र पहुंचाने में राष्ट्र को ज़्यादा व्यय करना होगा, क्योंकि कम व्यय वाले पत्र प्राप्त न होने से परिणाम स्वरूप राष्ट्र को घाटा होगा. अतएव आवश्यक हो गया है कि हर उद्योग या सेवा, जिसे राष्ट्र चलाता है, उसे दूसरे किसी को चलाने न दिया जाए. ऐसा हो जाए तो इसी तरह दूसरी आवश्यक चीजें भी आपको एक मूल्य पर ही सब जगह प्राप्त होने लग जाएंगी. आप जो पहनते हैं वे कपड़े, जो खाते हैं वह अन्न या जहां रहते हैं वे मकान इत्यादि, सब चीजें अगर राष्ट्रीयकरण की हुई फैक्ट्री, कारखाने या खेतों से पैदा की हुई हों तो उसी औसत से कर देने वाले क़ानून के हिसाब से, हर आवश्यक वस्तु आपको उचित मूल्य में प्रत्येक स्थान पर मिलने लगे. पूंजीवादी प्रथा में यह सब होना संभव नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

एक आदर्श लोकपाल बिल चाहिए

कई महीनों से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कड़े क़दम उठाने की आवश्यकता बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है. यूं तो भ्रष्टाचार कोई नई घटना नहीं है, लेकिन 1991 के बाद जबसे नई आर्थिक नीति लागू हुई है, भ्रष्टाचार का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है. हमारे समाज में भ्रष्टाचार कई स्तरों पर विद्यमान है. मुंबई के सामान्य लोगों का कहना है कि जब उन्हें राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्र और पासपोर्ट बनवाना होता है अथवा स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराना होता है तो उन्हें भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है. बड़ी संख्या में लोग इस भ्रष्टाचार के शिकार हैं. यूं तो नवीनतम तकनीकों ने लोगों का जीवन थोड़ा आसान बना दिया है, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार पर क़ाबू नहीं पाया जाता, तब तक भारतीयों का जीवन आसान नहीं होने वाला. नगर निगम या अन्य कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सुधार की आवश्यकता है. लोकपाल बिल का मसौदा तैयार हो रहा है. लोकपाल के कारण यदि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर काबू पाने में सक्षम हो जाती है तो यह स्वागत योग्य होगा. हमें होनहार विद्यार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर विद्यालय खोलने की आवश्यकता है और उसके लिए आवश्यकता है संसाधनों की. भ्रष्टाचार के कारण इन उद्देश्यों के लिए संसाधनों की कमी पड़ जाती है. हाल–फ़िलहाल में 2–जी, 3–जी और सीडब्लूजी जैसे बड़े घोटाले प्रकाश में आए हैं. जब भी किसी घोटाले की भनक मिले, उसी समय प्रधानमंत्री को संबंधित मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए. इसमें किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है. अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा किया होता तो इन घोटालों को रोका जा सकता था. लोकपाल बिल में सबसे बड़ी समस्या इसके अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है. कहा यह जाता है कि 6 पूर्व न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. अगर यह सही है तो फिर हम कहां से ईमानदार आदमी लाएंगे, जो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ कर सकें. लोकपाल का दंडात्मक रूप सही है, लेकिन भारत के सामान्य लोगों को चैन से जीने के लिए दंडात्मक संस्था से अधिक भ्रष्टाचार को रोकने वाली संस्था की आवश्यकता है. नागरिक चार्टर की मांग को एक सही क़दम कहा जा सकता है. राशनकार्ड, पासपोर्ट आदि ऐसे मामले हैं, जिनके लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए. अगर ऐसा कर दिया जाता है तो फिर रिश्वत मांगने वालों के पास कोई चारा नहीं बचेगा. किसी एक काम के लिए किसी कार्यालय के बार–बार चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे जल्द समाप्त किया जाना चाहिए. एक बार जब कोई व्यक्ति अपने काम के लिए किसी सरकारी कार्यालय में जाए तो उसी समय उससे सारे काग़ज़ात ले लिए जाएं, ताकि बार–बार उस एक काम के लिए उसे चक्कर न लगाने पड़ें. किसी काम के लिए समय सीमा का निर्धारण न होना भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण है. साथ ही अवैधानिक तरीके से कमाई गई संपत्ति के लिए भी कड़े प्रावधान किए जाने चाहिए. न केवल 2–जी लाइसेंस रद्द होना चाहिए, बल्कि जिन आदर्श फ्लैट्स के आवंटन में घोटाला हुआ है, उनका आवंटन रद्द कर देना चाहिए. ऐसे कानून की आवश्यकता है, जिसमें अवैधानिक तरीके से कमाई गई संपत्ति तत्काल ज़ब्त करने का प्रावधान हो. भारत को एक आदर्श लोकपाल बिल की ज़रूरत है, जो यहां के लोगों को भ्रष्टाचार के दानव से मुक्ति दिला सके.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

आवाज़ में असर के लिए बेक़रार हूं

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह बेबस और लाचार नज़र आते हैं. उनके सहयोगी मंत्रीगण घोटालों और आरोपों का जवाब देने की तैयारी में जुटे रहते हैं. ऐसे में उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है. ग़रीबी, बेरोज़गारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जनता परेशान है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए. दुष्यंत कुमार के शब्दों में–

वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता,
मैं बेक़रार हूं आवाज़ में असर के लिए.

–ओम प्रकाश साव, *कोलकाता, पश्चिम बंगाल.*

जनता किस पर भरोसा करे

पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी द्वारा कार्यक्रम आयोजकों से ज़्यादा किराया वसूले जाने का मामला बेहद गंभीर है. जब भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली किरण बेदी ऐसा कर सकती हैं तो जनता किस पर भरोसा करे. अंग्रेजी का एक प्रमुख अख़बार ऐसे तीस मामलों की सूची छाप चुका है, जिनमें किरण बेदी ने आयोजकों से ज़्यादा पैसे वसूले. इतना ज़रूर है कि वह मान चुकी हैं कि उन्होंने जो किया, वह ग़लत था, तभी तो वह पैसे लौटाने की बात कर रही हैं. सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाने पर कोई गबन की धनराशि वापस करने की बात करे तो क्या क़ानून उसे बख्श देगा?

–सईद, *दिल्ली.*

महंगाई और त्योहार

भारतीय संस्कृति में त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थान है और हर कोई इन मौक़ों पर ख़रीददारी करता है. यह ठीक है कि भारतीय समाज महंगाई से परेशान है, लेकिन यह भी दिन के उजाले की तरह साफ़ है कि उस पर मंदी का दानव कभी हावी नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय उतना ही ख़र्च करते हैं, जितना उनकी जेब इजाज़त देती है. पिछले दिनों रत्न एवं आभूषण की बिक्री में 25 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी, शॉपिंग मॉल्स में जमकर ख़रीददारी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 20 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी और ऑटो सेक्टर की तेज रफ़्तार एक प्रमाण है कि भारतीय बाज़ारों में ख़रीददारों की कमी नहीं है.

–हर्षवर्धन कुमार, *पटना, बिहार.*

भाजपा अपने गिरेबान में झांके

समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कांग्रेस पर आरोप लगाती रहती है. सच्चाई यह है कि भाजपा शासित राज्यों में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है. कर्नाटक और उत्तराखंड को ही देखिए, दोनों जगह भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण ही उसे मुख्यमंत्री बदलने पड़े. यह भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि एक ओर सत्ता में बैठे लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी भाजपा भी भ्रष्टाचार में डुबकी लगाती नज़र आ रही है. ऐसे में अब जनता को कोई तीसरा विकल्प तलाशना होगा.

–प्रताप नारायण सिंह, *बेगूसराय, बिहार.*

देश के दुश्मन

भ्रष्ट नेता, मंत्री और अधिकारी ही देश के असली दुश्मन हैं. इनके रहते देश का भला नहीं हो सकता. यदि हम देश का भला चाहते हैं तो इनका बहिष्कार करना होगा. इनके कारण आर्थिक असमानता बढ़ रही है. देश की सुरक्षा और अखंडता को भी ख़तरा पैदा हो गया है.

–नारायण जी. *छपरा, बिहार.*

गागर में सागर

यह लिखते हुए हर्ष हो रहा है कि चौथी दुनिया ने गागर में सागर भरने की कहावत चरितार्थ की है. इसमें प्रकाशित आलेख पठनीय और ज्ञानवर्द्धक होते हैं. मैं अपने पुस्तकालय के लिए चौथी दुनिया की वार्षिक सदस्यता लेना चाहता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें.

–डॉ. बृजमोहन बौरोलिया, *आगरा, उत्तर प्रदेश.*

टीआरपी का खेल

टैम मीडिया रिसर्च देश में टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट यानी टीआरपी तय करने का काम करती है. टैम ने महानगरों में 8150 मीटर लगा रखे हैं. क्या 121 करोड़ की आबादी वाले देश में टीवी दर्शकों की पसंद–नापसंद 165 शहरों में लगे 8150 मीटरों से तय की जा सकती है? वास्तव में टीआरपी का सारा खेल विज्ञापन हासिल करने के लिए खेला जा रहा है. इस चक्कर में टीवी चैनल दर्शकों को क्या परोस रहे हैं, यह सब जानते हैं.

–रूचिन भाटिया, *करनाल, हरियाणा.*

ज़्यादा पत्र शामिल करें

पाठकों की दुनिया स्तंभ का आकार बहुत छोटा है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पत्र इसमें शामिल किए जा सकें. पाठक समय निकाल कर पत्र लिखते हैं, उन्हें उचित स्थान मिलना चाहिए. वाराणसी जेल के क़ैदी का पत्र पढ़ा. यह एक अच्छा प्रयास है.

–चंद्रशेखर चौधरी, *देवघर, झारखंड.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

दावों और वायदों का कारोबार

एक राजनीतिक अनुमान के हिसाब से मध्यावधि चुनाव भी दूर नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यात्राओं की योजनाएं इस तरह बनाईं कि वह उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हो सके और देश भर में कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश जा सके, पर भाजपा इसमें कितनी सफल हुई है, इसका आकलन तो उसे ही करना होगा. अगर वह ईमानदारी से आकलन करेगी तो पाएगी कि यात्राएं बहुत लाभदायक नहीं रहीं और अगर वह अपने कार्यकर्ताओं में पब्लिसिटी का आधार लेकर कोई संदेश देना चाहेगी तो कह देगी यात्राएं बहुत सफल रहीं. पर शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि आडवाणी जी की यात्रा सारे देश में निकली, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, लेकिन वह कहीं भी लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई. बहुत सारी जगहों पर, छोटी जगहों पर, वह समाचारपत्रों में स्थान भी नहीं पा सकी. टेलीविज़न ने भी अब इन यात्राओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया है.

अगर यात्राओं में भीड़ जुटती, लोग आकर्षित होते और उन्हें भरोसा होता कि इन यात्राओं से उनकी समस्याएं हल हो सकती हैं या कोई नया राजनीतिक विकल्प मिल सकता है तो मीडिया में इन यात्राओं को स्थान अवश्य मिलता. इसका मतलब यही निकलता है कि लोग राजनीतिक पहल करने से निराश हो गए हैं. उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर दीपावली के दिन कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह के बीच मुलाकात हुई, जिसमें मिलकर चुनाव लड़ने का फ़ैसला हुआ. अजीत सिंह समझदार हैं, उन्होंने राजनीतिक प्रासंगिकता की गंभीरता को पहचाना और कांग्रेस भी अपनी घोषित रणनीति से पीछे हटी तथा अकेले चुनाव लड़ने की जगह उसने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ने का नया रास्ता अख्तियार किया. लेकिन क्या कांग्रेस सिर्फ़ अजीत सिंह के सहारे उत्तर प्रदेश में कोई कमाल दिखा सकती है? शायद नहीं. इसलिए हो सकता है कि वह आने वाले दिनों में कुछ और राजनीतिक दलों के साथ अपने क़दम मिलाए या उन्हें साथ लेने की कोशिश करे.

उत्तर प्रदेश में जो तीसरे शख्स चुनाव यात्रा पर हैं, वह बाबा रामदेव हैं. उनकी सभाओं में छोटी जगहों पर भी भीड़ हो रही है और अब उनके निजी चैनल में इन यात्राओं को बहुत ही होशियारीपूर्वक दिखाकर उनका प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया उनकी यात्रा को उस तरह नहीं दिखा रहा है, जिस तरह दिखाना चाहिए. शायद इसलिए, क्योंकि बाबा रामदेव की यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस की मुख़ालिफ़त और शायद मायावती, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी को उसके मुकाबले समर्थन देना है. आख़िर में बाबा रामदेव कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोग, कांग्रेस के मुक़ाबले जो भी उम्मीदवार जीत रहा हो, उसे वोट दें. बाबा रामदेव की बात लोग कितना मानेंगे, नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी भी उनका आकर्षण उनका पुराना योग कार्यक्रम है. बाबा रामदेव की पूछ अभी भी एक अच्छे योग शिक्षक की पूछ है. वह जहां जाते हैं, सवेरे लोग उनसे योगासन सीखने आते हैं और उसी में बाबा रामदेव किसी न किसी व्यक्तित्व को बुलाकर आम लोगों को उसका संबोधन कराते हैं.

उत्तर प्रदेश राजनीतिक युद्ध का ताज़ा मैदान है. मुलायम सिंह यादव की जगह इस चुनाव में अखिलेश यादव का टेस्ट होने वाला है. मुलायम सिंह यादव की थोड़ी तबियत भी ख़राब है और वह लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव को ध्यान में रख ज़्यादातर ज़िलों में घूमने की योजना बनाकर रथ यात्रा पर हैं. अखिलेश की सभाओं की जुटी भीड़ या उनके भाषण अभी भी भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की सभाओं में जुटी भीड़ और उनके भाषणों के मुकाबले ज़्यादा मायने रखते हैं, पर अखिलेश यादव एक चीज में असफल हो रहे हैं, यह कि वह अभी भी इस चुनाव को जातीय दायरे से बाहर निकाल कर सामाजिक दायरे में नहीं ले जा पाए हैं. समाज के ग़रीब और पिछड़े तबके उनके साथ आएं, यह विश्वास अखिलेश यादव अभी तक पैदा नहीं कर पाए. अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कोशिश सफलता की दहलीज़ पर आती है और वापस चली जाती है. अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह फूंकना चाहिए और बाक़ी दूसरे सामाजिक ग्रुपों के कार्यकर्ताओं को आकर्षित करना चाहिए, उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है, लेकिन इन सबके मुक़ाबले एक महिला है, जो चट्टान की तरह खड़ी है.

मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और वह यह इंप्रेशन दे रही हैं कि विपक्ष के बिखराव की स्थिति में बसपा ही उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी. हो सकता है, उसकी सीटें कुछ कम हों, लेकिन मायावती मानती हैं कि उनकी सीटें बढ़ेंगी. उनके दल के लोग उत्साहित हैं, उन्हें लगता है कि कोई भी राजनीतिक नेता इतना बड़ा क़द नहीं बना सका, जितना बड़ा कद मायावती का है. देश के विपक्षी दल एक बार मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं. अब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और वह लोगों को यह संदेश सफलतापूर्वक दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके मुक़ाबले कोई नहीं है और न कोई होगा. इस संदेश का मुक़ाबला अभी तो कोई विपक्षी नेता नहीं कर पा रहा है. अफवाहें यहां तक फैल रही हैं कि ब्राह्मण समाज मायावती का साथ छोड़ रहा है. सच चुनाव में सामने आएगा, लेकिन मायावती ने एक होशियारी बरती है कि उन्होंने अगर ब्राह्मण समाज के मौजूदा एमएलए का टिकट काटा है तो उसी के परिवार के दूसरे आदमी को वहां से टिकट दे दिया है. उन्होंने ब्राह्मण समाज की दावेदारी को चुनौती नहीं दी है, बल्कि ऐसे लोग, जो ब्राह्मण समाज में दाग़दार साबित हो गए थे और जिनसे लोग नाराज़ थे, उन्हें बदलने की बात उन्होंने कही. यही काम उन्होंने दूसरे समाज के लोगों और दलित समाज के साथ किया. जिसके ऊपर भी उन्होंने कोई शंका देखी, जिसे भी दाग़दार पाया, उसे उन्होंने बदला. यह काम दूसरी पार्टियां नहीं कर पा रही हैं. उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने उम्मीदवार बदले तो वे चुनाव में नुक़सान पहुंचाएंगे. जबकि मायावती ऐसा नहीं सोचतीं. इसलिए पहली नज़र में राजनीतिक रणनीति और राजनीतिक समझदारी में मायावती बाक़ी सारे राजनीतिक दलों से आगे हैं.

अन्ना हजारे एक राजनीतिक भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के लोग इंसान से रूबरू होकर, नेता से रूबरू होकर उसके विचार सुनना चाहते हैं. जब विचार सुनेंगे तो फ़ैसला लेंगे कि इसमें कितना तथ्य है और कितना नहीं है. अन्ना हजारे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच न जाकर सारे देश में अपने प्रति संदेह भरा अविश्वास पैदा कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में किसका राज होगा, कितने विधायक किस दल के जीतेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है, पर इतना ज़रूर है कि अभी भी मायावती प्रथम स्थान पर, समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव एवं अखिलेश यादव की टीम दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर लड़ाई है कांग्रेस-अजीत सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच.

कौन है मायावती का सलाहकार? कम से कम कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नज़र नहीं आता. जो सामने हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब हाशिए के लोग हैं. अधिकारियों में वह किसकी राय लेती हैं? माना जाता है कि वह शशांक शेखर सिंह की राय लेती हैं, लेकिन फ़ैसला मायावती की समझ का ही होता है. इस स्थिति में उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में हलचल मच सकती थी या लोग फ़ैसला लेने में समझदारी दिखा सकते थे, अगर अन्ना हजारे भी वहां घूमते, लेकिन वह या तो लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं या अपनी टीम के ऊपर लगे आरोपों से विचलित हैं या फिर उनकी शारीरिक स्थिति ख़राब है, इसलिए उन्होंने अचानक मौन व्रत की घोषणा कर दी और कहा कि जब तक मौन व्रत चलेगा, मैं कहीं पर भी यात्राओं पर नहीं जाऊंगा. अन्ना हजारे एक राजनीतिक भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के लोग इंसान से रूबरू होकर, नेता से रूबरू होकर उसके विचार सुनना चाहते हैं. जब विचार सुनेंगे तो फ़ैसला लेंगे कि इसमें कितना तथ्य है और कितना नहीं है. अन्ना हजारे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच न जाकर सारे देश में अपने प्रति संदेह भरा अविश्वास पैदा कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में किसका राज होगा, कितने विधायक किस दल के जीतेंगे, यह तो भविष्य के गर्भ में है, पर इतना ज़रूर है कि अभी भी मायावती प्रथम स्थान पर, समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव एवं अखिलेश यादव की टीम दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर लड़ाई है कांग्रेस–अजीत सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच. इन दोनों में से कोई भी तीसरे या चौथे स्थान पर आएगा. पीस पार्टी भी धीरे–धीरे अपना दावा ठोकती जा रही है. उत्तर प्रदेश के अधिकांश उपचुनावों में पीस पार्टी ने दूसरे नंबर पर रहकर अपनी प्रासंगिकता साबित की है. पीस पार्टी किसके साथ जुड़ती है या किसे अपना समर्थन देती है या उसके साथ कितना मुस्लिम वोट जुड़ता है, यह उत्तर प्रदेश के चुनाव का एक बड़ा फैक्टर होगा. पहले कहते थे कि प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है. अब शायद यह इतना सार्थक नहीं रहा. अब प्रधानमंत्री पद का रास्ता सारे देश से होकर जाता है, ऐसा कह सकते हैं, पर इसके बावजूद उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन वह यह भूमिका निभाए तो कैसे निभाए? उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समझदारी का अभाव है, राजनीतिक पहल का अभाव है और विकास के लिए राजनीतिक कल्पनाशीलता का अभाव है. यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी दिखाई दे रही है.

ज़रूरत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दावा करने वाले लोग कुछ तो ऐसा कहें, जिससे लोगों को लगे कि यह आदमी या यह महिला बाकियों से बेहतर है, पर अभी तो दावों और वायदों का कारोबार हो रहा है और इन दावों और वायदों के कारोबार में क्रम वही है यानी मायावती प्रथम स्थान पर, मुलायम सिंह दूसरे स्थान पर, तीसरे और चौथे स्थान के लिए कांग्रेस, अजीत सिंह और भाजपा के बीच लड़ाई और इन सबके बीच पीस पार्टी. देखना मज़ेदार होगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके विकास के लिए समर्पित कोई पार्टी या सरकार इस चुनाव में मिल पाएगी या नहीं.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

पूंजीवाद समस्या नहीं है

अचानक पूरे अमेरिका में वाल स्ट्रीट पर कब्जा करने की मुहिम चल पड़ी, साथ ही कई अन्य देशों में भी कुछ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन किए गए. मीडिया ने इसे तवज्जो दिया. यह एक तरह से पूंजीवाद के प्रति लोगों के मन में पनप रही घृणा की पूर्व सूचना है. राजनीति की वामपंथी धारा में भी इस साल कोई विशेष उत्तेजना नहीं है. सीपीएम की विचार धारा पर पुनर्विचार करने वाली बात अभी स्थगित की जा सकती है, साथ ही हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लेनिन की सोच आज भी जीवित है. पूंजीवाद के प्रति लोगों के मन में जो आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, उससे तो साम्यवाद के खात्मे की अटकलें लगाने वाले लोगों को धक्का पहुंचेगा, लेकिन यह भूल भी हो सकती है. अमेरिका में विरोध करने वाले लोग एक तरह से टी पार्टी की तरह उनमें शामिल हो रहे हैं. ये लोग मुक्त बाजार के समर्थक हैं और अगर ओबामा विरोधी नहीं तो सरकार विरोधी हैं. यह एक आवाज है कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और वाल स्ट्रीट पर कब्जा किया जाए. यदि यह पूंजीवाद के अंत का आगाज नहीं है तो फिर क्या है.

अगर देखा जाए तो इससे पहले भी अमेरिका में वियतनाम युद्ध के खिलाफ या नागरिक अधिकारों के पक्ष में इससे बड़े आंदोलन हुए हैं. यूरोप की जनता ने इराक युद्ध के विरुद्ध भी प्रदर्शन किया था और मई 1968 में फ्रांस की जनता ने डी गुएला के विरुद्ध भी सफल विद्रोह किया था. इसके अलावा लगभग दस साल पहले वैश्वीकरण के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद डावोस सम्मेलन के खिलाफ एक सामाजिक सम्मेलन हुआ. हालांकि यूरोप और अमेरिका में चल रहे आंदोलन सही हैं, लेकिन इनमें स्पष्ट लक्ष्य का अभाव है. ऐसा कहा जा सकता है कि वामपंथ अभी जीवित है और यह इन आंदोलनों का नेतृत्व कर सकेगा. अमेरिका में यह आंदोलन चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है. यूरोप और विशेष तौर पर यूरोजोन में इस आंदोलन का रुख कड़वाहट भरा और सब्र करने वाला है. ग्रीक, स्पेन और पुर्तगाल के लोग जानते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था संकट में है. सामान्यत: जहां विरोध हो रहा है, वहां लोग सरकार में परिवर्तन की मांग कर सकते हैं और स्थिति बेहतर होने की उम्मीद भी कर सकते हैं. इस समय प्रदर्शनकारी जानते हैं कि जिस किसी भी दल की सरकार आएगी, उसके सामने कर्ज वापस करने की समस्या होगी. हालांकि यह सही है कि जो भी कर्ज लिए गए, उनसे सभी लोगों को लाभ नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों को ही इसका फायदा मिला. सबसे अधिक लाभ जिन सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों को मिला था, आज वे सड़कों पर हैं.

सामान्यत: जहां विरोध हो रहा है, वहां लोग सरकार में परिवर्तन की मांग कर सकते हैं और स्थिति बेहतर होने की उम्मीद भी कर सकते हैं. प्रदर्शनकारी जानते हैं कि जिस किसी भी दल की सरकार आएगी, उसके सामने क़र्ज़ वापस करने की समस्या होगी. हालांकि यह सही है कि जो भी क़र्ज़ लिए गए, उनसे सभी लोगों को लाभ नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों को ही फ़ायदा पहुंचा. जिन सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों को सबसे अधिक लाभ मिला था, आज वे सड़कों पर हैं.

पूंजीवाद कोई समस्या नहीं है. इसकी गतिशीलता एशिया, लैटिन अमेरिका, यहां तक कि अफ्रीकी देशों में देखी जा सकती है. हालांकि चीन की विकास दर झटका दे रही है, लेकिन फिर भी यह 9.4 फीसदी से घटकर 9.1 फीसदी पर है. भारत के साथ भी परेशानी है, फिर भी यहां विकास दर 7.5 फीसदी है. समस्या पूंजीवाद की नहीं है. समस्या है कि अमीर देशों में जिस प्रकार का पूंजीवाद है, वह कमजोर हुआ है. इस समय पूंजीवाद अपने पुराने आकाओं का साथ छोड़कर नए आकाओं के पास आ गया है. यह दक्षिण या पूर्व की ओर पलायन कर गया है. पहले के पूंजीवादी देशों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वहां के लोगों को भी इस बात की जानकारी है. पंद्रह सालों तक (1992–2002) उनकी स्थिति काफी बेहतर रही. लोगों ने बैंकों से कर्ज लिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का भरपूर उपयोग किया. आज सभी लोग इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनमें से कितने लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बगैर रह सकते हैं. यह आंदोलन बढ़ सकता है. अगर इसे दबाया गया, लोग घायल हुए या उनकी मौत हुई तो यह और भी भड़क सकता है.

बजट में कटौती का सामना कर रही सरकार अगर स्थितियों पर काबू पाने के लिए कुछ नहीं करेगी तो जनता असहाय हो जाएगी. जब अपनी ही सरकार कर्जदारों के यहां गिरवी है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से डरी हुई है तो फिर उसके नागरिकों के पास क्या अधिकार रह जाता है. वैश्वीकरण के इस दौर में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र नहीं है, चाहे सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो. अगर कोई सरकार इस व्यवस्था से बाहर जाती है, अपने यहां सीमा कर में छूट देती है या बंद अर्थव्यवस्था को अपनाती है तो इससे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होने का भ्रम तो हो सकता है, लेकिन इससे वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हो सकता. अत: अमीर देशों की जनता ने यह महसूस कर लिया है कि अब समय पहले जैसा नहीं है, आगे का रास्ता आसान नहीं है, उस पर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा. खर्च करने की प्रवृत्ति कम करनी और बचत की आदत डालनी होगी. गरीब देश इस बात को पहले से जानते हैं, इसलिए उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, उनकी पारी तो अभी शुरू हुई है.

feedback@chauthiduniya.com

रोबोट्स अनुमान लगाते हैं कि दिए गए कामों को किस तरह किया जाए. एसओआईएनएन माहौल की जांच करने के लिए डेटा इकट्ठा करता है.

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

पाठकों के पत्र समस्या और सुझाव

शहर हो या गांव, सरकारी विभागों को लेकर हर आदमी की परेशानी एक सी होती है. कभी बिजली विभाग, कभी जल विभाग, कभी टेलीफोन विभाग. चूंकि इन सभी विभागों से आपका साबका पड़ता है और जब कोई काम समय से न हो रहा हो, तब परेशान होना स्वाभाविक है. इसके अलावा कभी आपके मुहल्ले या मुख्य सड़क की खुदाई करके सरकारी विभाग उसका कबाड़ा कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मर ख़राब हुआ तो महीनों तक ठीक नहीं होता, बुज़ुर्गों को पेंशन के लिए दौड़ाया जाता है और कभी-कभी तो सालों तक आपका काम अटका रह जाता है. एक ज़िम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते आप यह सब ज़रूर जानना चाहेंगे कि आख़िर इस मर्ज की दवा क्या है? इस अंक में हम एक ऐसा आरटीआई आवेदन का प्रारूप प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपने ज़्यादातर सवालों का जवाब पाने के लिए कर सकते हैं. इस अंक में हम अपने पाठकों के कुछ पत्र भी शामिल कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि आप सभी इस आवेदन का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही पाठकों के पत्रों से भी लाभांवित होंगे.

पाठकों के पत्र

सादे काग़ज़ पर आवेदन

क्या हम सादे काग़ज़ पर आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सूचना फॉर्म में इतनी जगह नहीं होती है कि वांछित सवाल पूछे जा सकें. सादे काग़ज़ पर आवेदन कैसे बनाया जा सकता है?

-सत्य प्रकाश, ई-मेल से.

सादे काग़ज़ पर आवेदन बनाया जा सकता है. हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने इसके लिए सूचना फॉर्म की व्यवस्था की है, फिर भी आप सादे काग़ज़ पर आवेदन दे सकते हैं. इसमें पहले लोक सूचना अधिकारी का नाम, विभाग का नाम, विषय में सूचना का अधिकार क़ानून 2005 के तहत आवेदन लिखकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. नीचे अपना नाम और पता अवश्य दें.

पता कैसे मालूम करें

मैंने डीडीए में आरटीआई आवेदन किया था और अपने प्लॉट के अधिग्रहण के बारे में सवाल पूछे थे, लेकिन यह कहते हुए आवेदन लौटा दिया गया कि इसमें पता ग़लत है. क्या करना चाहिए?

-नीरज कादयान, दिल्ली.

सभी सरकारी विभागों में एक लोक सूचना अधिकारी होता है. आपको लोक सूचना अधिकारी का नाम जानने की ज़रूरत नहीं है. सही पता आप इंटरनेट के ज़रिए मालूम कर सकते हैं.

पंचायत से जुड़ी सूचना चाहिए

मैं पंचायत से जुड़ी जानकारी चाहता हूं. ख़ासकर मनरेगा और पंचायत का वार्षिक बजट. मैं पहली बार आरटीआई का इस्तेमाल करने जा रहा हूं. आरटीआई आवेदन कैसे किया जाता है.

-खेमराज संखला, चौखान, जोधपुर.

आप एक आरटीआई आवेदन तहसील कार्यालय में देकर सारी

सूचनाएं मांग सकते हैं. आप जो भी सूचनाएं चाहते हैं, उनसे जुड़े सवाल अपने आवेदन में लिखें और तय सूचना शुल्क के साथ इसे कार्यालय में जमा कर दें. आप चौथी दुनिया के नियमित आरटीआई कॉलम से आवेदन का प्रारूप ले सकते हैं.

एलपीजी कनेक्शन नहीं मिला

मैंने एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया था. छह महीने बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. न जवाब मिला और न कनेक्शन. क्या मैं इस संबंध में आरटीआई का इस्तेमाल कर सकता हूं.

-रवि असरानी, ई-मेल से.

जी हां, आप एक आरटीआई आवेदन देकर देरी की वजह और अपने पत्र पर की गई कार्यवाही के बारे में पूछ सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(किसी भी सरकारी विभाग में रुके हुए काम, जैसे राशनकार्ड, पासपोर्ट, वृद्धावस्था पेंशन, आयु-जन्म-मृत्यु-आवास प्रमाणपत्र बनवाने या इन्कम टैक्स रिफंड मिलने में देरी होने, रिश्वत मांगने या बिना वजह परेशान करने की स्थिति में निम्न प्रश्नों के आधार पर सूचना के अधिकार का आवेदन तैयार किया जा सकता है)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन
महोदय,
मैंने आपके विभाग में............तारीख को................के लिए आवेदन किया था (आवेदन की प्रति संलग्न है), लेकिन अब तक मेरे आवेदन पर संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया है. कृपया इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-

1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्यवाही अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. मेरा आवेदन किन-किन अधिकारियों के पास गया, किसके पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उस अधिकारी ने उस पर क्या कार्यवाही की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.
2. विभाग के नियमानुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए थी? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया?
3. कृपया उन अधिकारियों के नाम एवं पद बताएं, जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्यवाही करनी थी, लेकिन उन्होंने कोई नहीं की.
4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और कब तक?
5. अब मेरा काम कब तक पूरा होगा?

(कुछ अतिरिक्त प्रश्न, यदि आवश्यक हों)

6. कृपया मुझे उन सभी आवेदनों/रिटर्न/याचिकाओं/शिकायतों की सूची उपलब्ध कराएं, जिन्हें मेरे आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत के बाद जमा किया गया. सूची में निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए:-
   क. आवेदक/करदाता/याचिकाकर्ता/पीड़ित का नाम
   ख. रसीद संख्या
   ग. आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की तारीख
   घ. कार्यवाही की तारीख
7. कृपया रिकॉर्ड के उस हिस्से की छाया प्रति दें, जो उपरोक्त आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत की रसीद का ब्योरा रखते हों?
8. मेरे आवेदन के बाद यदि किसी आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत को नंबर आने से पहले निस्तारित किया गया हो तो उसका कारण बताएं.
9. इस आवेदन/रिटर्न/याचिका/शिकायत के नंबर आने से पहले निस्तारण के मामले में, यदि कोई हो, सतर्क पूछताछ कब तक की जाएगी?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.......रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर..........है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम...................
पता...................
फोन नंबर.............

संलग्नक..........
(यदि कुछ हो तो)

ज़रा हट के

दो चुटकी नमक और मेमोरी

सिंगापुर के वैज्ञानिकों का कहना है कि नमक के इस्तेमाल से कंप्यूटर हार्डडिस्क की स्टोरेज क्षमता छह गुना बढ़ाई जा सकती है. मात्र एक वर्ग इंच में 3.3 टेराबाइट डेटा स्टोर होगा. यह खोज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एजेंसी फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च और डेटा स्टोरेज इंस्टीट्यूट ने मिलकर की है. एक ऐसी प्रक्रिया तैयार की गई है, जिसके ज़रिए नमक का इस्तेमाल करते हुए हार्डडिस्क की रिकॉर्डिंग डेंसिटी 3.3 टेराबाइट प्रति इंच बढ़ाई जा सकती है. इसका अर्थ यह है कि जिस हार्डडिस्क में अभी एक टेराबाइट डेटा आता है, नई तकनीक के इस्तेमाल से भविष्य में उसी आकार की डिस्क में छह टेराबाइट जानकारी स्टोर की जा सकेगी. इस आविष्कार की रिपोर्ट विज्ञान मामलों की पत्रिका नैनो टेक्नोलॉजी, जरनल ऑफ वैक्यूम साइंस और टेक्नोलॉजी बी में छपी है. वैज्ञानिकों के मुताबिक़ , यह अच्छे ढंग से कपड़े तह करके सूटकेस में रखने जैसा है. आप जितने करीने से पैकिंग करेंगे, उतने ज़्यादा कपड़े रख सकेंगे. मेमोरी डिवाइस तैयार करने की प्रक्रिया को बिट पैटर्निंग कहा जाता है. पहले वैज्ञानिक बिट्स की बारीक कटिंग लाइन नहीं देख पाते थे. फिल्म पर प्रिंट बिट्स की बारीक लाइनों का बाहरी हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन खाने के नमक के ज़रिए बिट्स की लाइनें साफ देखी गईं. सॉल्ट रेसिपी की खोज करने वालों में से एक जोएल यांग कहते हैं, इसकी मदद से आपको अति उच्च कंट्रास्ट मिल सकता है. अब हम उन लाइनों को भी भलीभांति देख सकते हैं जो धुंधली सी हो जाती थीं. यांग को उम्मीद है कि 2016 तक डेटा स्टोरेज से जुड़े उद्योग सॉल्टेड बिट पैटर्निंग प्रक्रिया को अपनाने लगेंगे. बीते 10 सालों का उदाहरण देते हुए वह कहते हैं कि हार्डडिस्क का आकार बढ़ाने के बजाय उसकी क्षमता बढ़ाना आज के दौर की मांग है.

इमोशनल रोबोट

ऐसी मशीन, जो ख़ुद-बख़ुद ऐसे काम कर सके, जिनके लिए उसे प्रोग्राम न किया गया हो या ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सके, जिन्हें उसने पहले न देखा हो. टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर ओसामु हासेगावा ने पहली बार ऐसी प्रणाली बनाई है, जो रोबोट को आसपास का माहौल देखकर इंटरनेट पर शोध करने की सुविधा देती है. इसके ज़रिए रोबोट्स सोच सकते हैं कि वे किस तरह समस्या का समाधान निकालें. हासेगावा ने बताया, ज़्यादातर मौजूदा रोबोट्स प्रोसेसिंग में बेहतर हैं, लेकिन वे उन्हीं कामों को करने के लिए हैं, जिन्हें पहले से प्रोग्राम किया गया हो. उन्हें असली दुनिया, जहां मनुष्य रहते हैं, के बारे में बहुत कम जानकारी है. हमारी परियोजना रोबोट्स और मानवीय दुनिया के बीच पुल का काम करने की है. सेल्फ ऑर्गनाइजिंग इंक्रीमेंटल न्यूरल नेटवर्क या एसओआईएनएन एक एल्गोरिदम है, जो रोबोट्स को अपने ज्ञान का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसे वे पहले से जानते हैं. रोबोट्स अनुमान लगाते हैं कि दिए गए कामों को किस तरह किया जाए. एसओआईएनएन माहौल की जांच करने के लिए डेटा इकट्ठा करता है. एसओआईएनएन संचालित मशीन से यदि कहा जाए कि वह पानी दे तो वह सिखाई गई विधि के मुताबिक़ काम करने लगती है, जैसे कप पकड़ना, बोतल पकड़ना, बोतल से पानी डालना, बोतल के नीचे कप लगाना आदि. पानी देने वाले ख़ास प्रोग्राम के बिना रोबोट क्रम के मुताबिक़ वह काम करता है, जिससे दिया गया आदेश पूरा होता है. एसओआईएनएन मशीन को जब ऐसे काम करने में कठिनाई होती है तो वह मदद मांगती है. काम पूरा करने के लिए वह जिस जानकारी का इस्तेमाल करती है, उसे अगले कार्य में इस्तेमाल करने के लिए संग्रह भी कर लेती है. एक अलग प्रयोग में एसओआईएनएन का इस्तेमाल कर रोबोट्स को इंटरनेट पर किसी चीज के बारे में खोज के लिए सक्षम बनाया जाता है. हासेगावा और उनके सहयोगी इन क्षमताओं के ज़रिए एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिया गया काम करने के लिए इंटरनेट में कार्य विधि खोजे और उसे पूरा करे. वह कहते हैं, हमें उम्मीद है कि भविष्य में रोबोट इंग्लैंड के कंप्यूटर से चाय बनाने का तरीका सीख सकेगा और जापान में इस काम को अंजाम दे सकेगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल): इस सप्ताह छोटी-छोटी बातों में क्रोध काम बिगाड़ सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी. धनाभाव से कोई सहयोगी उबार लेगा, आपका काम नहीं रुकेगा. जीवनसाथी से मतभेद ख़त्म होंगे. स्वास्थ्य में कुछ शिथिलता आ सकती है. आहार-विहार का ध्यान रखें. यात्रा के योग रहेंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई): कार्यक्षेत्र में सम्मान और पदोन्नति के योग बनेंगे. संतान की ओर से उत्साहवर्द्धक समाचार पूरे परिवार में ख़ुशनुमा माहौल की स्थापना करेगा. संपत्ति में निवेश के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. संयमित दिनचर्या में दिलचस्पी बढ़ेगी. ज़मीन-जायदाद के क्रय-विक्रय में सावधानी की ज़रूरत रहेगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून): चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा. मित्रों से मुलाक़ात होगी. प्रॉपर्टी में लाभ के सूत्र हाथ लगेंगे. प्रेम संबंधों में थोड़े एहतियात की ज़रूरत रहेगी. अनावश्यक बातों से बचें. बदन और जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई): निजी रिश्तों के उतार-चढ़ाव परेशानियां बढ़ा सकते हैं. लंबी एवं पर्वतीय यात्रा में सावधानी अपेक्षित है. अदालती मामलों के प्रति सतर्क रहें. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपका पक्ष मज़बूत होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आजीविका और प्रॉपर्टी में निवेश के लिए किसी निकटवर्ती स्थान की यात्रा हो सकती है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त): विद्युत एवं मशीनरी के कार्यों में नाम बढ़ेगा. परिवार में ख़ुशनुमा माहौल रहेगा. ज़मीन-जायदाद के कार्यों में सफलता मिलेगी. अदालती मामलों में आपका पक्ष मज़बूत होगा. प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेगी. व्यापारिक दौड़धूप के लिए सेहत का उत्तम होना आवश्यक है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर): कृषि के आधुनिक साधनों एवं उन्नत बीजों के प्रयोग में रुचि बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में बड़ा निर्णय करने से पहले माता-पिता की राय आपके लिए हितकर होगी. आर्थिक निवेश के लिए प्रतीक्षा करें. रक्तचाप एवं हृदय रोगों से निजात मिलेगी.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर): आजीविका के स्थायी विकास हेतु निकटजनों के मध्य बैठक हो सकती हैं. स्वजनों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें. वित्तीय स्थिति मज़बूत बनाने की कोशिश कुछ रुकावटों के बाद सफल होगी. आक्रोश में कोई निर्णय लेने से बचें. ज़मीन-जायदाद से जुड़े क़ानूनी मामलों में आपका पक्ष मज़बूत होगा.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर): पार्टनरशिप में धन लगाने से पहले जांच-परख लें. ऐसा न हो कि आपका बहुमूल्य धन आपसे दूर हो जाए. पारिवारिक जीवन स्तर उच्च बनाने की चुनौतियां रहेंगी, जिन्हें आप अपने बौद्धिक कौशल द्वारा काबू कर लेंगे. निवेश करने का अवसर मिल सकता है, जिससे आगे चलकर लाभ हो.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर): कार्यक्षेत्र में आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें. मित्रों के सहयोग से धार्मिक कार्य संपन्न होंगे. किसी भी प्रकार के निवेश के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करें. प्रेमी साथी एक-दूसरे की भावनाओं को समझें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी): व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में निपुणता हासिल होगी. परिवार के साथ ख़ुशनुमा समय बीतेगा. आर्थिक निवेश के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करें. मेडिटेशन या योग अपनाने से नवीन शक्ति का एहसास होगा. प्रेयसी से उलझना रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी): व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में दिलचस्पी बढ़ेगी. परिवार के प्रत्येक सदस्य की भावनाओं का आदर करें. अर्थ लाभ के नए सूत्र हाथ लग सकते हैं. यह समय बौद्धिक एवं शारीरिक उन्नति का है. धार्मिक एवं व्यवसायिक यात्रा के योग बनेंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च): तकनीक एवं साहित्य संदर्भ में उन्नति की ओर दौड़ेंगे. मन में नया उत्साह परिवार के साथ ख़ुशनुमा माहौल बनाएगा और किसी यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करेगा. कोई विरोधी मित्रता के लिए हाथ बढ़ा सकता है. संपत्ति में निवेश के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, जिसके परिणाम सार्थक रहेंगे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

अब ऐसा लगता है कि अपने भाई वली अहमद करजई और पूर्व राष्ट्रपति प्रो. बुरहानुद्दीन की हत्या के बाद हामिद करजई भी पाकिस्तान से ख़ौफ़ खाने लगे हैं.

अफ़ग़ानिस्तान

हामिद करज़ई का बयान और भारत

डॉ. क़मर तबरेज़

अफ़ग़ानिस्तान इस वक़्त इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. एक तरफ जहां अमेरिका ने यह घोषणा कर दी है कि दिसंबर 2014 तक सभी विदेशी सेनाएं अफ़ग़ानिस्तान छोड़ देंगी, वहीं दूसरी तरफ भारत–पाक के बीच इस बात को लेकर होड़ मची है कि 2014 के बाद अफ़ग़ानिस्तान पर किसका वर्चस्व रहेगा. पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के जाने के बाद अफ़ग़ानिस्तान पर उसका ही वर्चस्व रहे और वहां एक बार फिर तालिबानी शासन आए, ताकि वह अपनी मर्जी से अफ़ग़ानिस्तान का भविष्य तय कर सके, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता. भारत चाहता है कि अफ़ग़ानिस्तान के लोगों को आतंकवाद से हमेशा के लिए छुटकारा मिले और इसीलिए वह पिछले कई वर्षों से अफ़ग़ानिस्तान के निर्माण कार्यों में जी–जान से जुटा हुआ है. भारत ने वहां पर विश्व के किसी अन्य देश के मुक़ाबले निर्माण कार्यों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान अपने कई नागरिकों की जानें भी गंवाईं. यही नहीं, वह अब तक अफ़ग़ानिस्तान के निर्माण कार्यों में 2 बिलियन डॉलर ख़र्च कर चुका है और सड़क, पुल, स्वास्थ्य केंद्रों एवं अन्य सरकारी इमारतों के निर्माण से लेकर बिजली उत्पादन जैसे कार्यों को अंजाम दिया. भारत के इन कार्यों की सराहना न सिर्फ़ अफ़ग़ानिस्तान की सरकार और वहां के नागरिक करते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इसका श्रेय भारत को देता है.

मिसाल के तौर पर इसी साल 18 जनवरी को काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन पर उस समय हमला किया गया, जब वहां अफ़ग़ानी मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था. इसके बाद अप्रैल में काबुल के इंटर कांटिनेंटल होटल पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग हताहत हुए.

ऐसे में अचानक अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई का यह बयान भारत सहित पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चौंका देने वाला है कि अगर पाकिस्तान पर अमेरिका, भारत, चीन या किसी और देश की तरफ़ से आक्रमण होता है तो अफ़ग़ानिस्तान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा. यह बात उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कही. आख़िर हामिद करजई के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, जिसके चलते वह ऐसा बयान देने के लिए मजबूर हो गए. इसका केवल एक ही जवाब है कि अफ़ग़ानिस्तान के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकियां पाकिस्तान को किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हैं. वजह यह है कि बीते 4–5 अक्टूबर को हामिद करजई ने दिल्ली आकर भारत के साथ राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक, शिक्षा, संस्कृति, सुरक्षा, विज्ञान एवं तकनीक आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए क़रार किए तो पाकिस्तान को लगा कि अफगानिस्तान उसके हाथों से निकलता जा रहा है. ज़मीनी हक़ीक़त भी इसी ओर इशारा कर रही है कि पाकिस्तान को लगता है कि अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद उसे एक बार फिर वहां की सत्ता हथियाने का अवसर मिलने वाला है. शायद इसीलिए पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई ने तालिबान द्वारा वहां हमले तेज कर दिए हैं.

मिसाल के तौर पर इसी साल 18 जनवरी को काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन पर उस समय हमला किया गया, जब वहां अफगानी मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था. इसके बाद अप्रैल में काबुल के इंटर कांटिनेंटल होटल पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग हताहत हुए. उक्त हमले बताते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान में एक बार फिर तालिबान सक्रिय हो चुका है और उसे करजई हुकूमत की शांति वार्ता में कोई रुचि नहीं है. काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर भी अक्सर हमले होते रहते हैं. इन हमलों के पीछे कहीं न कहीं यही मंशा होती है कि भारत के पैर वहां जमने न दिए जाएं. दूसरी तरफ़ पाकिस्तान यह प्रचार भी करता रहा है कि भारत अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है. ब्लूचिस्तान के हवाले से वह यह इल्ज़ाम काफी समय से लगाता आया है. बीते 12 जुलाई को हामिद करजई के भाई एवं कंधार प्रोविंसियल काउंसिल के अध्यक्ष अहमद वली करजई की हत्या कर दी गई. अगले दिन यानी 13 जुलाई को जब अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति एवं हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन प्रो. बुरहानुद्दीन रब्बानी भारत के दौरे पर आए तो उन्होंने भारत–अफगानिस्तान के संबंध मज़बूत करने पर जोर दिया, लेकिन पाकिस्तान को यह रास नहीं आया और बीते 20 सितंबर को रब्बानी को भी मौत के घाट उतार दिया गया. रब्बानी अक्सर कहते थे कि अफ़ग़ानिस्तान में होने वाले आतंकवादी हमलों के पीछे कुछ ख़ुफ़िया एजेंसियों का हाथ है. ज़ाहिर है, उनका इशारा आईएसआई की तरफ़ था, इसलिए आईएसआई ने उन्हें भी अपने रास्ते से हटा दिया. अब ऐसा लगता है कि अपने भाई वली अहमद करजई और पूर्व राष्ट्रपति प्रो. बुरहानुद्दीन की हत्या के बाद हामिद करजई भी पाकिस्तान से ख़ौफ़ खाने लगे हैं. उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देने और अफ़ग़ानिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को कुसूरवार ठहराने का सिलसिला बंद नहीं किया तो उनके लिए कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन उनके इस ताजा बयान से सबसे ज़्यादा नुक़सान उनके देश को ही होगा, क्योंकि इससे तालिबान के हौसले बुलंद होंगे और आतंकी गतिविधियों में तेजी आएगी.

tabrez@chauthiduniya.com

लीबिया

अभी और बिगड़ेंगे हालात

राजीव रंजन तिवारी

कर्नल मोअम्मर अली गद्दाफ़ी ने 42 सालों तक लीबिया पर शासन किया. उनके मारे जाने के बाद दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनमें यही कहा जा रहा है कि अब लीबिया के लोगों को शांति मिलेगी यानी कर्नल गद्दाफ़ी का मारा जाना अच्छी ख़बर है, किंतु आशंका इस बात की है कि वहां हालात अभी और बिगड़ेंगे. देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रीय अंतरिम परिषद ख़ुद को कैसे व्यवस्थित करेगी, चुनाव कब होंगे, क्योंकि परिषद में कई तरह के आपसी विवाद हैं, विद्रोही सेना में अलग–अलग कई ब्रिगेड हैं. इसके अलावा विभिन्न जनजातियों की अपनी–अपनी समस्याएं और अंतर्विरोध हैं. हालात बता रहे हैं कि अनिश्चितता अभी बनी रहेगी. इससे पश्चिमी देशों की ज़िम्मेदारी बढ़ेगी. उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्रीय अंतरिम परिषद स्थितियों को ठीक से संभाले, आपस में टकराव न हो और शांति का माहौल बना रहे.

गद्दाफ़ी सितंबर 1969 में सत्ता में आए थे. उन्होंने सम्राट इदरीस को एक सैनिक कार्रवाई में सत्ता से हटाया था. उस वक़्त गद्दाफ़ी 27 साल के थे. मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर से प्रेरित गद्दाफ़ी उस समय अरब राष्ट्रवाद की फ़िज़ा में बिल्कुल फिट बैठे थे, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में अपने वक़्त के सभी प्रशासकों को पीछे छोड़ दिया. क़रीब 41 साल सत्ता में रहते हुए उन्होंने सरकार चलाने की अपनी एक अलग व्यवस्था कायम की. उत्तरी आयरलैंड के आईआरए जैसे हथियारबंद चरमपंथी गुटों के साथ–साथ फ़िलीपींस में इस्लामी कट्टरपंथी गुट अबु सय्याफ़ को समर्थन दिया. उन्होंने उत्तरी अफ्रीका के सबसे क्रूर तानाशाह के रूप में लीबिया पर राज किया. आख़िरी दिनों में स्कॉटलैंड में दिसंबर 1988 में पैन एम को उड़ाने के बाद अलग–थलग पड़े लीबिया को गद्दाफ़ी एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वीकार्य बनाने में सफल रहे थे. लीबिया को पश्चिमी देशों एवं कंपनियों ने उसके विशाल ईंधन भंडार की वजह से गले लगाना शुरू कर दिया था. इधर कुछ दिनों से तेल के लिए पश्चिमी देशों एवं कंपनियों के बीच लड़ाई चल रही थी. दरअसल, लीबिया का तेल उच्च स्तर का है. उसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत कम है. हालांकि यह कुल तेल उत्पादन का केवल दो फ़ीसदी है, फिर भी बेहद महत्वपूर्ण है. बदले हालात में जहां तक लीबियाई तेल की मार्केटिंग का सवाल है तो लगता है कि अब यह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में मिलने लगेगा और इसका सकारात्मक असर विश्व स्तर पर दिखाई देगा. तेल की क़ीमतों में कुछ गिरावट भी हो सकती है.

जिस संघर्ष में गद्दाफ़ी मारे गए हैं, उसकी पृष्ठभूमि अरब देशों में हुए सत्ता विरोधी आंदोलन ने तैयार की थी. ट्यूनीशिया और मिस्र में सत्ता विरोधी आंदोलन के बाद लीबिया में इसकी शुरुआत हुई. त्रिपोली में जब गद्दाफ़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ तो बहुत क़ामयाब नहीं हो सका, लेकिन जब बेनगाज़ी में विद्रोह शुरू हुआ तो नाटो की सेना ने विद्रोहियों को हथियार भेजना शुरू कर दिया. नाटो के हस्तक्षेप के बाद गद्दाफ़ी का पतन सुनिश्चित हो गया था. उन्हें सत्ता से हटाने वाला विद्रोह फ़रवरी माह में बेनग़ाजी से शुरू हुआ. गद्दाफ़ी ने अपनी राजनीतिक विचारधारा को अपनी पुस्तक ग्रीन बुक में लोगों की सरकार के रूप में पेश किया. 1977 में गद्दाफ़ी ने लीबिया को एक जमाहिरिया घोषित किया, जिसका अर्थ है लोगों का राज, लेकिन वहां धन और तंत्र पर गद्दाफ़ी का ही क़ब्ज़ा बना रहा. गद्दाफ़ी ने लीबिया में कई राजनीतिक प्रयोग किए, जिन्हें उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति का नाम दिया. अलग–अलग जनजातियों को एक–दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी स्थिति मज़बूत की और वर्षों तक लीबिया के नायक बने रहे. अपनी सांस्कृतिक क्रांति के तहत उन्होंने सभी निजी व्यवसाय बंद कर दिए और अपने विरोधियों का हिंसक दमन भी किया. लॉकर्बी में एक हवाई जहाज़ को निशाना बनाने के बाद गद्दाफ़ी और लीबिया अंतरराष्ट्रीय पटल पर अलग–थलग पड़ गए. 2010 में लीबिया को तेल से 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई, लेकिन अधिकतर लीबियाई लोगों को इस धन से कोई लाभ नहीं हुआ. उनका रहन–सहन किसी ग़रीब देश के लोगों जैसा ही रहा. वहां बेरोज़गारी दर क़रीब 30 प्रतिशत है और लोग गद्दाफ़ी के शासन से त्रस्त थे. लीबिया के समाजवाद में मुफ़्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रियायती दरों पर आवास और यातायात शामिल है, लेकिन वेतन बहुत कम है. विदेशी निवेशों से मिलने वाला अधिकतर धन देश के चुनिंदा लोगों की जेब में जाता रहा है.

दरअसल, अमेरिका की निगाहें तेल निर्यातक देशों पर हैं. इसी के चलते अमेरिका ने रासायनिक हथियारों की जांच की आड़ में इराक पर हमला कर तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया. मिस्र और लीबिया में भी उसका हस्तक्षेप बढ़ा है, जबकि मध्य पूर्व के देश अमेरिकी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते. ईरान इस मामले में खुलकर अमेरिका का विरोध कर रहा है. लीबिया का साथ देना ईरान की मजबूरी है, क्योंकि दोनों देश अमेरिका विरोधी हैं. बेलारूस इसलिए लीबिया का समर्थन कर रहा है, क्योंकि उसमें उसके राजनीतिक–आर्थिक हित हैं. रूस भी लीबिया का परोक्ष समर्थन कर रहा है. मध्य पूर्व में अमेरिका इसलिए विशेष रुचि ले रहा है, क्योंकि उसकी नज़र वहां स्थित तेल भंडारों पर है. गद्दाफ़ी के मारे जाने के बाद लीबिया के हालात बताते हैं कि अभी भी वहां शांति संभव नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
दो टूक–संतोष भारतीय के साथ
ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
स्पेशल रिपोर्ट
नायाब हैं हम–उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
साई की महिमा

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301 www.chauthiduniya.tv

साई बाबा के बारे में गौली बुवा का कथन था कि यही ग़रीबों और असहायों के भगवान पण्ढरीनाथ के अवतार हैं. इसी भावना से सभी भक्त साई बाबा के जीवन काल में उनके दर्शन करने के लिए शिरडी को तीर्थ स्थान मान कर वहां आते थे.

विचारों को दबाया नहीं जा सकता. एक दिन विचार कंदरा फोड़ कर संसार पर छा जाते हैं.
स्व. तारा चंद्र मेहरोत्रा

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए
स्व. मालती कपूर

महा तीर्थ शिरडी

साई बाबा का निवास स्थान होने और वहां ही उनका समाधि मंदिर स्थित होने के कारण शिरडी तीर्थ स्थान बन गया है. साई बाबा के समाधि मंदिर में उनकी मूर्ति का दर्शन कर नित्य हज़ारों लोग अपनी मनोकामना पूरी करते हैं. ऐसा नहीं है कि सन 1918 में साई बाबा के महासमाधि लेने और उनका समाधि मंदिर बनने के बाद शिरडी तीर्थ स्थान बना हो. साई बाबा के जीवन काल में ही भक्त गण शिरडी को पावन तीर्थ स्थल मानते थे. गौली बुवा नाम के एक तीर्थयात्री भक्त थे, जिनका वचन इस तथ्य का साक्ष्य है.

गौली बुवा का कथन

गौली बुवा एक तीर्थयात्री था, जो प्रति वर्ष पण्ढरपुर की यात्रा कर विट्ठल भगवान के दर्शन करता था. उसकी उमर 95 वर्ष की थी. पण्ढरीनाथ के दर्शन करने के बाद गौली बुवा साई बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आता था. वह साई बाबा के सामने बैठ कर उन्हें अपलक नेत्रों से देखा करता था. वह शिरडी को तीर्थ स्थान और साई बाबा को पण्ढरीनाथ विट्ठल भगवान मानता था. साई बाबा के बारे में गौली बुवा का कथन था कि यही ग़रीबों और असहायों के भगवान पण्ढरीनाथ के अवतार हैं. इसी प्रकार, इसी भावना से सभी भक्त साई बाबा के जीवन काल में उनके दर्शन करने के लिए शिरडी को तीर्थ स्थान मान कर वहां आते थे.

साई बाबा की चरण पादुका

सन 1912 में बंबई का डॉक्टर राम राव कोठारे अपने कंपाउण्डर और भाई कृष्णा जी अलीबागकर नाम के मित्र के साथ साई बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आया. दर्शन करने के बाद उसका कंपाउण्डर और भाई कृष्णा जी अलीबागकर सगुन मेरु नायक और जी.के. दीक्षित से मिले. तीनों ने सोचा कि साई बाबा के शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे प्रकट होने के स्मारक के रूप में वहीं चबूतरे पर साई बाबा की चरण पादुका की स्थापना कर दी जाए. चरण पादुका बनवा कर शिरडी के खण्डोवा मंदिर के उपासनी महाराज को दिखाई गई. उपासनी महाराज ने उस चरण पादुका में कुछ सुधार किए और उस पर कमल का फूल, शंख और चक्र बनाए. नीम पेड़ का महत्व और साई बाबा की योग शक्ति का महत्व दर्शाने के लिए यह श्लोक खोद कर अंकित कर दिया गया कि –

सदा निम्ववृक्षस्य मूलाधिवसात
सुधास्रविणं तिक्तमपि प्रियं नम
तरुं कल्पवृक्षाधिकं साश्चयन्तम.
नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम

अर्थात मैं सद्गुरु साईनाथ को प्रणाम करता हूं जिन्होंने नीम वृक्ष के नीचे सदा बैठ कर उनके कड़वे पत्तों को अपने अमृत वचनों से मीठा बना दिया. यह नीम वृक्ष कल्पतरु से भी उत्तम है. इसके बाद साई बाबा से अनुमति ली गई. उन्होंने कहा कि सावन की पूर्णिमा (रक्षाबंधन) के दिन चबूतरे पर नीम वृक्ष के पास चरण पादुका लगा दी जाए. सावन पूर्णिमा के दिन ग्यारह बजे दिन को जुलूस और बाजे के साथ जी.के.दीक्षित पादुका को अपने सिर पर रख कर द्वारकामाई मस्जिद लाए. साई बाबा ने पादुका को स्पर्श करके कहा, यह प्रभु की पादुका है. पादुका नीम वृक्ष के चबूतरे पर लगा दी गई. साई बाबा अधिकतर पादुका के पास नीम के पेड़ के नीचे चिंतन करते हुए बैठे रहते थे. यह शिरडी की बहुत बड़ी विशेषता है.

तात्या की भक्ति

शिरडी में म्हालासपति और तात्या कोते पाटिल दो ऐसे अनन्य भक्त थे, जो साई बाबा के साथ ही रहते और उनके साथ ही रात को मस्जिद और चावड़ी में सोते थे. तात्या कोते पूरे चौदह साल तक बाबा के साथ सोया. तीनों अपने बिस्तर लगाने के बाद लेटते थे. उनमें से एक का सिर पूर्व की ओर, दूसरे का पश्चिम की ओर और तीसरे का उत्तर की ओर रहता था. तीनों के पैर बीच में एक दूसरे का स्पर्श किए रहते थे. लेटने के बाद तीनों आधी रात तक बातचीत करते रहते थे. अगर तीनों में से कोई सोने लगता था तो शेष दो उसे उठा देते थे. तात्या कोते पाटिल धार्मिक वृत्ति का था. उसके माध्यम से साई बाबा ने शिरडी में गणपति, शंकर पार्वती, शनि और मारुति के मंदिरों को सुव्यस्थित कराया था.

बायजा बाई का भाग्य

बायजा बाई हमेशा साई बाबा का ध्यान रखती थी. वह हर दिन मस्जिद में जाती और बाबा को खिलाती थी. समय के साथ वह शिथिल होती जा रही थी तथा बीमार भी रहती थी. एक दिन बायजा मां साई को भोजन करा रही थी. साई बाबा उससे बोले, मां, मेरा एक कहना मान लो. कल से तुम खाना लेकर मत आया करो. कमज़ोर हो गई हो. तो बेटा तुम्हें खिलाएगा कौन? मैं ख़ुद ही तुम्हारे घर पहुंच जाया करूंगा. कहने को तो बाबा ने कह दिया लेकिन वह तो थे अंतर्यामी. उन्हें मालूम था कि बायजा मां का अंत एकदम निकट ही है. दूसरे दिन ही एकदम सवेरे तात्या मस्जिद में रोता हुआ आया लेकिन यह देख कर उसका दिल धक- सा रह गया कि बाबा समाधिस्थ थे. उनका चेहरा लाल-सुर्ख किन्तु चित्त शान्त था. बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं. उनके नेत्र लाल एवं चेहरा भयंकर था. बाबा तुम्हें क्या हो गया है? रोना भूल कर तात्या ने पूछा. साई बाबा का चेहरा शांत हो गया. वह बोले, तात्या, तुम मेरे भाई हो और हमेशा रहोगे. मैंने बायजा मां को वचन दिया है. परंतु बाबा, मां तो तुम्हें याद करते करते मर गई. कहते कहते तात्या सिसकने लगा. मुझे सब मालूम है भाई. धीरज रखो. कह कर बाबा उठे और तात्या के साथ उसके घर चले. घर पहुंच कर मां कहते हुए बायजा मां के चरणों में श्रद्धा अर्पित की और उसके निकट बैठ कर समाधिस्थ हो गए. कुछ क्षणों में एकाएक बायजा बाई के शव में कंपन हुआ. शरीर चैतन्य हुआ और जीवित होकर उसने आंखें खोल दीं और साई बाबा तथा तात्या को आंखें भर कर देखती हुई बोली, बेटा साई, बेटा तात्या, मेरे पास आओ. दोनों उसके निकट आ गए वह कहने लगी, बेटा साई, मेरा अंत समय आ गया है. तात्या का ध्यान रखना. तू फिकर मत कर मां, मेरे जीते जी तात्या को कुछ नहीं होगा कह कर साई बाबा ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया और देखते देखते बायजा बाई फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई.

योग और समाधि

साई बाबा बहुत बड़े योगी थे. जब वे शैशवास्था में थे तभी से गुरु के सानिध्य में योगाभ्यास करने लगे थे. उन्हें योग की सभी क्रियाएं मालूम थीं और सिद्धियां प्राप्त थीं. धौति और नेति की क्रियाएं तो उनके लिये अत्यंत सामान्य थीं. तीन इंच चौड़े और साढ़े बाइस फुट लंबे कपड़े की पट्टी को गीली करके निगल जाने और आधे घंटे तक पेट के भीतर रख कर अंतड़ियों को साफ करने की यौगिक प्रक्रिया को धौति कहते हैं. अंतड़ियां साफ हो जाने के बाद कपड़े की पट्टी बाहर निकाल ली जाती है पर साई बाबा की धौति क्रिया निराली ही थी. वे अपने अंतड़ियों को ही पेट से बाहर निकालकर साफ कर लेते थे.

बाबा की धौति क्रिया

हर तीसरे दिन साई बाबा मस्जिद से काफी दूर एक वट वृक्ष के नीचे कुंए पर जाते थे और अपना मुंह धोकर स्नान करते थे. एक अवसर पर देखा गया कि उन्होंने उल्टी की और अपने अंतड़ियों को मुंह से बाहर निकाल लिया. उन्हें खण्ड योग तो मालूम ही था, इसलिए अपने अंतड़ियों को शरीर से अलग कर लेना उनके लिए संभव था. इसके बाद उन्होंने अपने अंतड़ियों को भीतर-बाहर से साफ किया और जामुन के एक पेड़ पर सूखने के लिए टांग दिया. सूख जाने पर फिर पेट के भीतर ज्यों की त्यों डाल दिया. साई सत्चरित के लेखक हेमाद पंत ने लिखा है कि उन दिनों शिरडी के कुछ लोगों ने साई बाबा की इस धौति क्रिया को देखा था और इसकी जांच भी की थी.

ध्यान की प्रक्रिया

साई बाबा चौबीसों घंटे प्रति पल परमात्मा के ध्यान में ही लीन रहते थे. जब संसार सोता था तब वह जागृत अवस्था में रहते थे. भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि या निशा सर्व भूतानां तस्यांजागर्ति संयमी. साई बाबा इसके मूर्तिमान स्वरूप थे. वह धूनी के बाजू से बैठे बैठे ही ध्यान लगा लेते थे. वे कमलपत्र जलबिन्दु के समान संसार में रहते थे.

साई बाबा का खंड योग

साई बाबा खंड योग में निपुण थे. खण्ड योग, योग की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा योगी अपने अंगों को अलग अलग कर फिर उनको यथा स्थान जोड़ लेता है. साई बाबा योग की यह प्रक्रिया करते थे. एक बार एक सज्जन साई बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में आया. उसने वहां बाबा के कटे अंग अलग अलग पड़े हुए देखा. वह बेहद डर गया और मस्जिद से बाहर आ गया. उसके मन में विचार आया कि किसी ने बाबा को काट काट कर उनके अंगों को इधर-उधर फेंक दिया है. उसने पुलिस को इसकी सूचना देने का विचार किया पर यह सोच कर रुक गया कि सबसे पहले देखने वाला समझ कर पुलिस उसी पर शक न कर ले. दूसरे दिन जब वह मस्जिद में गया तो साई बाबा को कुशल पूर्वक मस्जिद में बैठे पाया. साई बाबा के खण्ड योग का यह अद्भुत उदाहरण है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साई सुन लो विनय हमारी

बाबा आस शरण तुम्हारी, साई सुन लो विनय हमारी
हम न मांगें चांदी-सोना, हम न चाहें राजा होना
हमें चाहिए शरण तुम्हारी, साई सुन लो विनय हमारी
हम दर्शन के प्यासे बाबा, तुम बिन रहें उदास बाबा
बाबा बुझाओ प्यास हमारी, साई सुन लो विनय हमारी
कंटक पथ है रात अंधेरी, हमें न मंज़िल ज्ञात हमारी
बाबा बताओ डगर हमारी, साई सुन लो विनय हमारी
तुम हो दीन दुखी रखवारे, भव सागर में खेवन हारे
डूब न जाए नाव हमारी, साई सुन लो विनय हमारी
पूजा-पाठ हमें नहीं आता, मंदिर-मस्जिद भेद न भाता
जनसेवा अरदास हमारी, साई सुन लो विनय हमारी
जल से दीप जलाने वाले, नीम को मधुर बनाने वाले
सुईकारो बत्ती-धूप हमारी, साई सुन लो विनय हमारी
मृत को जीवन देने वाले, खोई वस्तु बताने वाले
हमको चाहिए कृपा तुम्हारी, साई सुन लो विनय हमारी
शिरडी समाधि लेने वाले, साई सुन लो विनय हमारी
साई राम पहचान तुम्हारी, साई सुन लो विनय हमारी
भेद न जाने काबा-काशी, आबे-ज़म, गंगा जलराशि
जगत जल में ज्योति तुम्हारी, साई सुन लो विनय हमारी
संध्या भजन हो सदन हमारे, जनसेवा हों क़दम हमारे
हमको चाहिए शक्ति तुम्हारी, साई सुन लो विनय हमारी
हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, भक्त सभी हैं शिरडी साई
सुमन समर्पित शरण तुम्हारी, साई सुन लो विनय हमारी
साई सेवा संघ में, मैं हूं चौकीदार
जन सेवा शक्ति दीजिए, निर्बल सेवादार.

-चरण सिंह सुमन, *धामपुर, ज़िला बिजनौर, उत्तर प्रदेश*

श्रीलाल ने अपनी मेहनत का फल बीमार आंखों से जी भरकर देखा, पर उनके अंतर्मन में उपजी ख़ुशी का वह इज़हार नहीं कर पाए.

अनंत विजय

पाठकों तक किताबों का पहुंचना ज़रूरी

हिंदी में जब मैंने पुस्तकों की समीक्षा लिखने का काम शुरू किया था तो समीक्षा के लिए किताबें अख़बारों से या लघु पत्रिकाओं से मिला करती थीं. जिस अख़बार या पत्रिका से समीक्षा लिखने का हुक्म जारी होता था तो वहां से पुस्तकें भेजी जाती थीं या फिर अगर दफ्तर जाता था तो वहां से ही किताबें दे दी जाती थीं. शुरुआत में अख़बार के दफ्तर से समीक्षा के लिए किताब लेकर निकलते हुए एक अजब क़िस्म का संतोष और रोमांच दोनों होता था. लेकिन कई अख़बार के फीचर संपादक या समीक्षा के पृष्ठ के इंचार्ज बेहद कंजूस थे. कुछ तो कवर निकालकर किताबें दिया करते थे, तो कुछ समीक्षा लिखने के बाद किताब भी वापस मांग लेते थे. मुझे कवर का गणित तो समझ में आता था, लेकिन किताबें वापस लेने की वजह का पता कभी नहीं चल पाया. जब मेरी लिखी कुछ समीक्षाएं पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होने लगी तो धीरे-धीरे प्रकाशकों ने किताबें भेजनी शुरू कर दीं. लखनऊ से प्रकाशित पॉयनियर साप्ताहिक में जब मैं स्तंभ लिखने लगा तो प्रकाशकों ने सीधे मुझे पुस्तकें भिजवानी शुरू कर दीं. फिर साल भर के प्रकाशनों के लेखा-जोखा के लिए भी प्रकाशकों ने उदारतापूर्वक किताबें भिजवाईं. मुझे याद है कि 2000 में सामयिक प्रकाशन ने महेश दर्पण के संपादन में बीसवीं शताब्दी की हिंदी कहानियां बारह खंडों में छापी थीं. मैंने सामयिक प्रकाशन के मालिक महेश भारद्वाज से पूरा सेट भेजने का अनुरोध किया और उन्होंने फ़ौरन उसे भिजवा दिया था, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी. उस वक़्त पूरे सेट की क़ीमत तीन हज़ार रुपये थी. 2000 तक तो हालत यह हो गई थी कि मयूर विहार के मेरे पते पर बंडल के बंडल किताबें पहुंचने लगी थीं. उसके बाद समयमान के संपादन के दौरान भी मुझे प्रकाशकों का भरपूर प्यार और सहयोग मिला. जहां भी नौकरी की वहां किताबों से जुड़े या तो पन्ने बनाए या फिर न्यूज चैनलों में काम करते हुए कार्यक्रम बनाए. इस दौरान प्रकाशकों से अच्छा राब्ता और रेपो क़ायम हो गया था. घर पर जब किताबें रखने में दिक्क़त होने लगी तो मैंने प्रकाशकों को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि मुझे जिस किताब पर लिखना होगा वह मैं अनुरोध करके मंगवा लूंगा. कृपया मुझे पुस्तकें नहीं भेजें. एक बार राजकमल प्रकाशन ने अपने नए प्रकाशनों के पूरे सेट की दो-दो प्रतियां भिजवा दीं. उसमें कई कविता संग्रह और साहित्येतर किताबें भी थीं. कविता संग्रहों पर यदा कदा ही लिख पाता हूं. अपने इस स्तंभ में मैं कविता पर नहीं लिख पाने की वजह कई बार बता चुका हूं. जब राजकमल का पूरा सेट खोला तो मुझे लगा कि कई किताबें मेरी रुचि की नहीं हैं. मैंने तय किया कि राजकमल प्रकाशन को किताबें वापस कर दूंगा. मैं अपनी गाड़ी में उन किताबों को लादकर राजकमल प्रकाशन के दरियागंज दफ्तर पहुंचा. मैंने उन सारी किताबों को वापस किया जो मेरी रुचि की नहीं थी और जिनपर मुझे लिखना नहीं था. मुझे राजकमल प्रकाशन के मालिक और मित्र अशोक महेश्वरी की बात अब भी याद है. अशोक जी ने कहा था कि हिंदी में तो लोग किताबों के लिए मारामारी करते हैं और एक आप हैं जिनको मैंने किताबें भेजीं तो अपनी गाड़ी पर लादकर मेरे दफ्तर आकर वापस कर दिया. मैंने अशोक जी से उसी वक़्त कहा था कि मुझे किताबें पढ़ने और उसपर लिखने के लिए चाहिए होती हैं. जिसपर मैं नहीं लिख पाऊंगा उसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है. लिहाज़ा मैंने आपको किताबें वापस कर दीं. उसके बाद से अशोक जी का स्नेह और बढ़ा. बाद के दिनों में तो मैं और कम किताबें मंगवाने लगा. नौकरी की व्यस्तता की वजह से ज़्यादा लिख-पढ़ पाना संभव नहीं था. लेकिन प्रकाशकों का स्नेह बरक़रार रहा. जिस किताब को पढ़ने का दिल किया उसके प्रकाशक को फोन कर मंगवा लेता था. अभी पिछले दिनों वाणी प्रकाशन से अपने मित्र अरुण माहेश्वरी को फोन करके

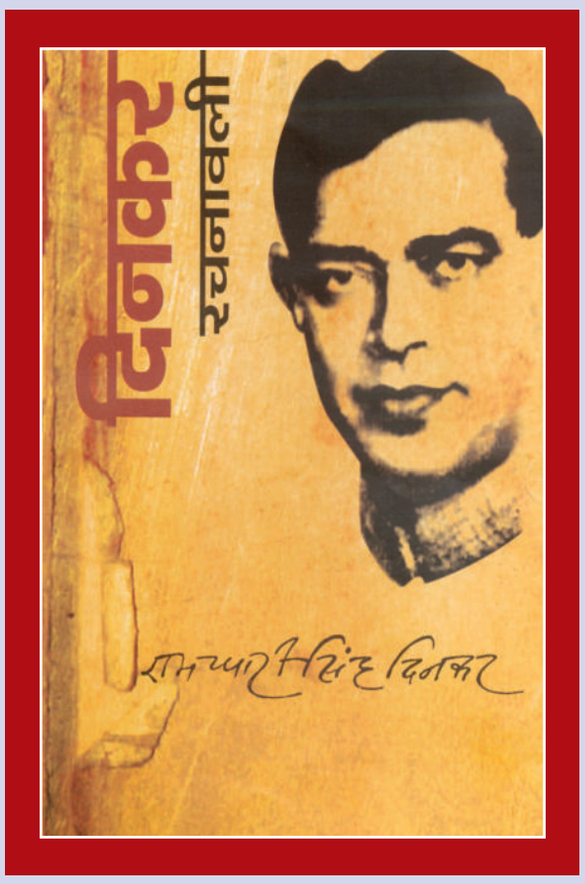

जनसत्ता के संपादक ओम थानवी की किताब मुअनजोदड़ो मंगवाई.

अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि नंदकिशोर नवल और तरुण कुमार के संपादन में लोकभारती प्रकाशन से दिनकर रचनावली का प्रकाशन 14 खंडों में हुआ है. दिनकर हमेशा से मेरे प्रिय लेखक रहे हैं. उनकी कई कविताओं की पंक्तियां याद हैं. संस्कृति के चार अध्याय उनकी बेहतरीन कृति है. उनकी कई किताबें मेरे पास हैं, लेकिन रचनावली देखकर दिनकर को समग्रता में पढ़ने की इच्छा जाग्रत हो गई. जब राजकमल प्रकाशन (लोकभारती प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन समूह का ही हिस्सा है) को मैंने कुछ पुस्तकें मंगवाने के लिए अनुरोध पत्र भेजा तो उसमें मैंने दिनकर रचनावली भिजवाने का भी आग्रह कर दिया. हालांकि मुझे संकोच हो रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं दिनकर रचनावली की लंबी समीक्षा अपने स्तंभ और अन्यत्र लिखूंगा इस वजह से संकोच के बावजूद मैंने दिनकर रचनावली का नाम अपने अनुरोध पत्र में लिख दिया. किताबों का बंडल आया तो उसमें दिनकर रचनावली नहीं थी. मुझे लगा कि शायद क़ीमत (चौदह खंडों की क़ीमत 9800 रुपये) की वजह से सेट नहीं भेजा गया है. चूंकि मैंने दिनकर रचनावली पर लिखना तय कर लिया था इस वजह से मैंने प्रकाशक से फिर से अनुरोध किया कि मुझे दिनकर रचनावली को बिल के साथ भेज दें. रचनावली आ गई. यह प्रसंग मैं सिर्फ़ इस वजह से लिख रहा हूं कि हिंदी में यह स्थिति अब तक नहीं थी कि समीक्षा के लिए किताबें ख़रीदनी पड़ें. हिंदी के प्रकाशक योग्य समीक्षकों को उदारता से किताबें भिजवाते रहे हैं. अंग्रेजी में भी कमोबेश यही हालत है. किताबें चाहे जितनी भी महंगी हों समीक्षार्थ तो भेजी ही जाती हैं. लेकिन राजकमल प्रकाशन से रचनावली नहीं भेजे जाने के मनोविज्ञान को मैं समझ नहीं पाया. पहले मुझे यह लगा था कि सेट की क़ीमत की वजह से रचनावली मेरे पास नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे इस बात का अहसास हुआ कि राजकमल समूह से ही मुझे उससे ज़्यादा मूल्य की किताबें मानार्थ आई हैं. मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मेरा मानना है कि यह प्रकाशकों का विशेषाधिकार है कि वह कौन-सी किताबें किसको समीक्षार्थ भेजते हैं.

मुझे तो जिस पुस्तक की समीक्षा लिखनी होती है उसे मैं ख़रीदकर भी लिखता हूं. विदेशों से प्रकाशित अंग्रेजी की दर्जनों किताबों की समीक्षा मैंने लिखी और उसे या तो फिल्पकॉर्ट से मंगवाया या फिर दुकानों से ख़रीदकर लाया. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी में मेरे लिए यह एक नया और चौंकाने वाला अनुभव था. दिनकर रचनावली को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है. आने वाले दिनों में मैं रचनावली पर लिखूंगा. अभी तो सिर्फ़ चौदह खंडों को उलट-पुलट कर देख पाया हूं. पहले खंड में नवल जी की लिखी भूमिका पढ़ गया. कवर तो शानदार है ही उसके अलावा रचनावली में दिनकर जी के कई दुर्लभ फोटो भी संग्रहित हैं. इस लिहाज़ से यह माना जा सकता है कि इस वर्ष के प्रकाशनों में दिनकर रचनावली का प्रकाशन एक अहम घटना है. दिनकर के प्रशंसकों के लिए यह पूरा सेट संग्रहणीय है. आवश्यकता इस बात की है कि दिनकर रचनावली की उपलब्धता को बढ़ाया जाए और आनेवाले दिनों में अगर इसका पेपरबैक्स संस्करण प्रकाशित हो सके तो पाठकों के लिए मूल्य के लिहाज़ से सहूलियत हो जाएगी. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि लंबे समय तक सरकारी ख़रीद के सहारे प्रकाशन व्यवसाय नहीं चल सकता. अंतत: पाठकों के बूते ही प्रकाशन जगत चलेगा भी और बचेगा भी. ज़रूरत इस बात की है कि पाठकों तक किताबें पहुंचें. हालांकि कई ऑनलाइन वेबसाइट ने इस काम की शुरुआत कर दी है और वहां पाठकों को घर बैठे किताबें तो मिलती ही हैं, साथ ही अच्छी ख़ासी छूट भी हासिल हो जाती है.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

श्रीलाल शुक्ल हमेशा याद रहेंगे

जब ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा हुई थी, तब वह आश्चर्य चकित स्वर में बोले थे-मुझे राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था. पिछले दो-तीन सालों से अस्वस्थ हूं. अमरकांत के साथ मिले ज्ञानपीठ से मैं बहुत ख़ुश हूं.

अजय कुमार

स्मृति शेष

ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल अब हमारे बीच नहीं हैं. उन्हें हाल में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. बीते 18 अक्टूबर को राज्यपाल बीएल जोशी ने साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल को अस्पताल जाकर अपने हाथों से स्मृति चिंह भेंट कर उनका सम्मान किया था. सांस लेने में तकलीफ होने के कारण श्रीलाल शुक्ल का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. उनके क़रीबी लोगों का कहना था कि बोलने में असहज महसूस कर रहे श्रीलाल शुक्ल की तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं थी कि वह समझ नहीं पाते कि राज्यपाल बीएल जोशी उन्हें वर्ष 2009 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार देने आए हैं. राज्यपाल ने क़रीब आधे घंटे का समय उनके साथ बिताया. श्रीलाल शुक्ल को अपनी साहित्यिक यात्रा के दौरान वैसे तो कई पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन उम्र के आख़िरी पड़ाव में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना ठीक वैसे ही था जैसे तपती छूप में पथिक को छाया का मिलना. यह और बात है कि उनके क़रीबी यह मानने को तैयार नहीं हैं. उनका तो यही कहना था कि श्रीलाल शुक्ल किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं थे. हां, वह यह बात ज़रूर स्वीकार करते दिखे कि भी सम्मान तो सम्मान ही होता है. श्रीलाल ने अपनी मेहनत का फल बीमार आंखों से जी भरकर देखा, पर उनके अंतर्मन में उपजी ख़ुशी का वह इज़हार नहीं कर पाए. यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि वह एक शब्द तक बोल नहीं पाए. वह स्मृति चिन्ह और उत्तर प्रदेश के गवर्नर को बस देखते ही रहे. बूढ़ी आंखों ने राज्यपाल को पहचान लिया था. राज्यपाल के हाथ में एक चेक भी उन्होंने देखा. वह गौरव का क्षण था, काश वह उस समय बोल पाते. पूरे अस्पताल में हलचल थी. वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव, कथाकार अखिलेश व इप्टा के राकेश भी मौक़े पर मौजूद थे.

वैसे यह कोई पहला अवसर नहीं था जब उन्हें कोई साहित्य लेखन में पुरस्कार मिला था. प्रख्यात उपन्यासकार व व्यंग्यकार श्रीलाल शुक्ल की 1957 में पहली कृति सूनी घाटी का सूरज प्रकाशित हुई. फिर दूसरी कृति अंगद का पांव प्रकाशित हुई. 1970 में उन्हें प्रसिद्ध कृति राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था. 1999 में व्यास सम्मान, 2005 में उत्तर प्रदेश सरकार का सम्मान यश भारती, 2008 में पद्म भूषण मिला.

श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर, 1925 को लखनऊ ज़िले के अतरौली में हुआ था. उन्होंने अपना सारा जीवन लखनऊ से बाहर ही बिताया, पर जब हाथ-पांव थके तो अपने घर लखनऊ लौट आए. जब ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए उनके नाम की घोषणा हुई थी, तब वह आश्चर्य चकित स्वर में बोले थे-मुझे राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था. पिछले दो-तीन सालों से अस्वस्थ हूं. अमरकांत के साथ मिले ज्ञानपीठ से मैं बहुत ख़ुश हूं. ग़ौरतलब है कि अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से वर्ष 2009 के लिए 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया था.

feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
मेरे बेटे की कहानी

लेखक
नादिन गोर्डाइमर

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
195 रुपये

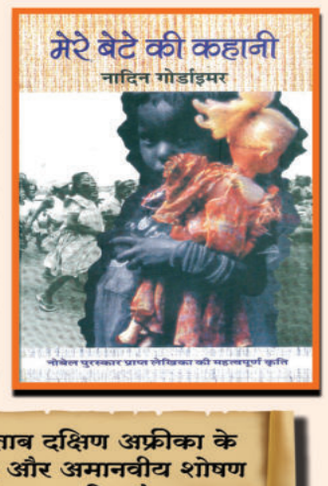

यह किताब दक्षिण अफ्रीका के नस्लवाद और अमानवीय शोषण पर आधारित है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

ब्राईट® की सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

FROM THE HOUSE OF : BRIGHT® Career's® BOOKS | COMPETITION REFRESHER | SCIENCE REFRESHER | G.K. GENERAL KNOWLEDGE REFRESHER

BRIGHT PUBLICATIONS®
Publishers of INDIA'S LARGEST SELLING Competition & School Books
2767, Kucha Chellan, Darya Ganj, New Delhi-110 002 (India) —— (ESTD. 1968)
Ph.: 011-64632226 & 3226, 23282226 & 3226 Fax: 011-23269227 Telefax: 64633226
E-mail: sales@brightpublications.com | Web Site: http://www.brightpublications.com

FOR VPP ORDERS, SEND ₹ 25/- AS ADVANCE & FOR FREE CATALOGUE WRITE TO US

डिवाइस बिना किसी वायर के गोफ्लेक्स मीडिया ऐप के जरिए सीधे गोफ्लेक्स सेटेलाइट ड्राइव से कनेक्ट हो जाती है.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 07 नवंबर–13 नवंबर 2011

एचटीसी रडार

इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक गीगाहर्ट्ज के स्कॉरपियन प्रोसेसर और एडरिनों 205 जीपीयू द्वारा सपोर्ट होता है. एचटीसी रडार में 5 मेगा पिक्सल का शानदार कैमरा है.

गैजेट्स पसंद लोगों के लिए एचटीसी ने एक ख़ास स्मार्ट फोन लांच किया है. एचटीसी रडार विंडोज 7.5 मैंगो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. यह मोबाइल यूजर्स को 25 जीबी क्लाइड बेस्ड स्टोरेज स्पेस देगा. इसकी ख़ूबसूरत एस–एलसीडी टच स्क्रीन भी प्रभावित करती है.

इसकी 3.8 इंच स्क्रीन पूरे 16 मिलियन कलर को सपोर्ट करती है. स्क्रीन में गोरिल्ला ग्लास डिस्पले के साथ मल्टी टच इनपुट की सुविधा है. सिर्फ़ यही नहीं, इसकी स्क्रीन एसेलेरो मीटर सेंसर और गायरोस्कोप से लैस है. इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक गीगाहर्ट्ज के स्कॉरपियन प्रोसेसर और एडरिनों 205 जीपीयू द्वारा सपोर्ट होता है. एचटीसी रडार में 5 मेगा पिक्सल का शानदार कैमरा है, जिसका इस्तेमाल किसी भी साधारण डिजिटल कैमरे की जगह किया जा सकता है. इस कैमरे में कुछ फीचर हैं, जैसे ऑटो फोकस और लेड फ्लैश. इसमें आप जीओ टैगिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. इस स्मार्ट फोन में वैसे तो कोई एक्सटर्नल मेमोरी स्लॉट नहीं है, पर इसमें 8 जीबी तक की इंटरनल मेमोरी है. इसकी लिऑन बैट्री 2 जीबी में 5 घंटे और 30 मिनट का सपोर्ट देगी और 3 जीबी में 7 घंटे तक साथ निभाएगी. इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई और जीपीएस की भी सुविधा है. मैटेलिक फिनिशिंग वाले इस फोन का आकार 120.5/61.5/10.9 एमएम और भार केवल 137 ग्राम है. यह बाज़ार में 23,500 रुपये में उपलब्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

फोटोः सुनील मल्होत्रा

द टाइटन रागा सिल्वर वॉच की लॉचिंग के दौरान अभिनेत्री साक्षी तंवर के साथ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर सोमप्रभ कुमार सिंह.

कूल कैबिनेट बिजली-2

एसेसरीज बनाने वाली कंपनी टॉप नॉच इंफोट्रॉनिक्स ने अपना सबसे नया गेमिंग कैबिनेट बिजली-2 पेश किया है. कई सारी ख़ूबियों से लैस बिजली-2 को ख़ास तरह से डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सभी महत्वपूर्ण अवयवों को पर्याप्त कूलिंग प्रदान कर सके.

जेब्रोनिक्सल ब्रांड के तहत कंप्यूटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, दूरसंचार से जुड़े उत्पाद और एसेसरीज बनाने वाली कंपनी टॉप नॉच इंफोट्रॉनिक्स ने अपना सबसे नया गेमिंग कैबिनेट बिजली-2 पेश किया है. कई सारी ख़ूबियों से लैस बिजली-2 को ख़ास तरह से डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सभी महत्वपूर्ण अवयवों को पर्याप्त कूलिंग प्रदान कर सके. यह एकदम नया और उन्नत संस्करण है. इसमें कई नई ख़ूबियां हैं, जैसे यूएसबी 3.0, जेट ब्लैक इंटीरियर, पीएसयू माइटिंग, मल्टीपल 120 एमएम एलईडी फैन आदि. इसे एयरटेक फ्रंट पैनल, डेल्टा साइड पैनल और हेक्साकोन टॉप पैनल के साथ डिज़ाइन किया गया है. कूलिंग के लिए फ्रंट और साइड में 120 एमएम ब्लू एलईडी इनटेक फैन है, जो बेहतरीन एयर इनटेक उपलब्ध कराता है.

ऊपर 120 एमएम एक्जॉस्ट फैन है और पिछले हिस्से में भी एक 120 एमएम फैन है. एचडीडी इंस्टॉल करने के लिए टूल लेस एचडीडी ट्रेज लगे हैं और 4/3.5 हार्डडिस्क ड्राइव के लिए भी जगह है. पारदर्शी डेल्टा साइड पैनल में पंखे और वेंट्स हैं, जो बेहद आकर्षक हैं और शानदार कूलिंग मुहैया कराते हैं. गेमर्स को एसेंबलिंग में आसानी हो, इसके लिए कई फ्रेंडली फीचर्स हैं.

इनबिल्ट्स एसडी/एमएमसी कार्ड रीडर/राइटर फ्रंट में है, ताकि यह आसानी से इस्तेमाल किया जा सके. इसका पूरा इंटीरियर जेट ब्लैक कलर में है. साधारण लेआउट के बावजूद कैबिनेट काफी स्पेस और स्लॉट उपलब्ध कराता है. इसकी क़ीमत सिर्फ़ 4200 रुपये है.

मारुति की एरटिगा

भारतीय बाज़ार में एमयूवी की श्रेणी में धमाल मचा चुकी जापानी कार निर्माता कंपनी ट्योटा इनोवा को देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति कड़ी टक्कर देने के मूड में है. मारुति भारतीय बाजार में अपने वाहनों की रेंज में जल्द ही इज़ाफ़ा करने वाली है. इस बार वह एमयूवी (मल्टीपरपज यूटीलिटी व्हीकल) पेश कर रही है, जिसका नाम एरटिगा है. कंपनी इसे अगले वर्ष जनवरी में भारत की सड़कों पर उतार देगी. यह नई कार एमयूवी श्रेणी में बेहद शानदार लुक और दमदार इंटीरियर वाली है. जिस तरह इसे तैयार किया गया है, उसे देखकर यही लगता है कि इसकी सीटें आकर्षक और आरामदायक होंगी. इसमें सात लोगों के बैठने की सुविधा होगी. यह कार बड़े भारतीय परिवारों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश होगी. एक एमयूवी के तौर पर जितनी भी आधुनिक सुविधाएं होती हैं, वे एरटिगा में मौजूद है. इसके अलावा इसकी क़ीमत भी ट्योटा इनोवा से कम होगी. मारुति सुजुकी ने भारतीय बाज़ार में हैचबैक कारों की रेंज में अपनी जो छवि बनाई है, वह इस नई एमयूवी को सफलता दिलाने में मदद करेगी.

वायरलेस स्टोरेज

डिवाइस बिना किसी वायर के गोफ्लेक्स मीडिया ऐप के ज़रिए सीधे गोफ्लेक्स सेटेलाइट ड्राइव से कनेक्ट हो जाती है. गोफ्लेक्स मीडिया ऐप आईट्यूंस, ऐपल ऐप स्टोर और एंड्रॉयड मार्केट या वेब ब्राउज़र में उपलब्ध है.

सीगेट (एनएएसडीएक्यू:एसटीएक्स) ने गोफ्लेक्सो सैटेलाइट मोबाइल वायरलेस स्टोरेज पेश किया है. यह बैट्री से चलने वाला पहला एक्सटर्नल हार्डड्राइव है और किसी भी वाईफाई इनैबल्ड मोबाइल डिवाइस की स्टोरेज क्षमता बिना वायर के बढ़ा सकता है. 500 जीबी एवं 802.11 बी/जी/एन वाईफाई एक्सेस और रिचार्जेबल बैट्री से लैस गोफ्लेक्स फैमिली के इस नवीनतम ड्राइव में वीडियो, म्यूज़िक, तस्वीरें एवं डॉक्यूमेंट की चलती–फिरती लाइब्रेरी लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं. डिवाइस बिना किसी वायर के गोफ्लेक्स मीडिया ऐप के ज़रिए सीधे गोफ्लेक्स सेटेलाइट ड्राइव से कनेक्ट हो जाती है. गोफ्लेक्स मीडिया ऐप आईट्यूंस, ऐपल ऐप स्टोर और एंड्रॉयड मार्केट या वेब ब्राउज़र में उपलब्ध है. गोफ्लेक्स सैटेलाइट से अपने साथ पूरी मीडिया लाइब्रेरी लेकर चलना संभव हो सकेगा. यह तीन कनेक्शन तक घंटों मनोरंजन प्रदान कर सकती है. स्टैंडबाई बैट्री लाइफ 25 घंटे की है, जबकि शक्तिशाली लीथियम पॉलिमर बैट्री पांच घंटे तक लगातार स्ट्रीमिंग वीडियो प्ले कर सकती है. गोफ्लेक्स मीडिया ऐप में डाउनलोड फीचर भी है, जो अस्थायी तौर पर एंड्रॉयड डिवाइस पर वीडियो लोड कर सकता है और ड्राइव को स्टैंडबाई मोड में भेज सकता है. इसे खरीदने पर मीडिया सिंक सॉफ्टवेयर मुफ्त दिया जाता है. फाइल स्टोर्ड हो, आप द्वारा बनाई हो या फिर आईट्यूंस लाइब्रेरी की हो, मीडिया सिंक सॉफ्टवेयर के ज़रिए म्यूज़िक, वीडियो, फोटो और डॉक्यूमेंट गोफ्लेक्स सैटेलाइट ड्राइव पर लोड हो जाएंगे. कंप्यूटर से गोफ्लेक्स सैटेलाइट ड्राइव पर मीडिया कंटेंट तेजी से लोड हों, इसलिए वायरलेस मोबाइल स्टोरेज सुपरफास्ट यूएसबी 3.0 केबल से लैस होता है, जो यूएसबी 2.0 पोर्ट्स के साथ भी काम कर सकता है और कहीं ले जाने–लाने के लिए इसे आसानी से हटाया भी जा सकता है. गोफ्लेक्स सैटेलाइट ड्राइव के साथ एक कार चार्जर और वॉल चार्जर भी दिया जाता है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

इन हादसों से सुरक्षा पर सवाल तो खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर इन खेलों से जुड़े अन्य खिलाड़ियों पर पड़ा है. इन दुर्घटनाओं के कारण उनके मनोबल टूटा है.

रफ़्तार के जानलेवा खेल

जहां एक तरफ़ भारत में पहली बार फॉर्मूला रेसिंग के आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह और ख़ुशी है. वहीं बहुत सारे देश ऐसे भी हैं, जहां रफ्तार के इस खेल ने लोगों को मातम में डूबो दिया. जी हां, बात चाहे फॉर्मूला रेस की हो या फिर बाइक रेसिंग की, दोनों ही खेलों ने हाल में कई घरों के चिराग़ बुझा दिए हैं. रफ्तार के नशे से भरे ये खेल इतने घातक कभी नहीं थे, जितने आजकल हैं. जब पिछले दिनों एक हादसे में ब्रिटिश ड्राइवर की मौत हुई थी, तब शायद लोग इस बात से बिल्कुल नावाक़िफ़ थे कि आगे आने वाले समय में यह बेलगाम रफ्तार कई और जानें लेगी. एक हफ्ते में जिस तरह से लगातार दो खिलाड़ियों की मौत हुई है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं. बात चाहे कार रेसिंग में फॉर्मूला की हो या फिर बाइक रेसिंग की. दोनों ही खेलों ने अलग–अलग घटनाक्रमों में दो ऐसे लोगों की जान ली है, जो अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुज़र रहे थे. अब सवाल यह है कि जब इस खेल में अनियंत्रित रफ्तार का नशा इतना ख़तरनाक रूप ले लेता है, तो फिर सुरक्षा के सही इंतज़ाम क्यों नहीं किए जाते हैं. ज़ाहिर सी बात है, अगर एक हफ्ते में दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो जाए तो मामले की गंभीरता का अंदाज़ा हर किसी को हो जाना चाहिए.

ऐसा नहीं है कि दुर्घटनाएं इससे पहले नहीं हुईं, लेकिन पहले के हादसों में चोटें लगती रही हैं. इसलिए सुरक्षा के मसले पर इस तरह के सवाल नहीं उठाए गए, लेकिन अब सवाल खिलाड़ियों की मौत का है. मामला उठा लास वेगस इंडीकार 300 रेस में ब्रिटिश ड्राइवर डैन व्हेलडन की मौत से. रेस के आख़िरी लैप में 15 कारें जब भिड़ीं तो अहसास हो गया था कि दुर्घटना ख़तरनाक है. 77 नंबर की गाड़ी से पहचाने जाने वाले व्हेलडन के आगे चार कारें टकराईं. टक्कर के बाद कारों में आग लग गई. उन दो कारों को बचाने के चक्कर में एक ड्राइवर ने स्पीड कम कर बाएं मुड़ने की कोशिश की तो बायीं तरफ़ से आ रही कारें आपस में भिड़ गईं. व्हेलडन इसी का शिकार बने. उनकी कार कई मीटर तक हवा में उड़ी और फिर किनारे लगी बाड़ से टकरा गई, जिससे उसमें आग लग गई. इमरजेंसी गाड़ियां तुरंत ट्रैक पर पहुंचीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. व्हेलडन बुरी तरह झुलस चुके थे. हेलीकॉप्टर से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दो घंटे बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. ग़ौरतलब है कि डेन व्हेलडन दो बार इंडियाना पोलिज 500 के चैंपियन रह चुके हैं. इसके अलावा वह 16 बार इंडी कार रेस जीत चुके हैं. हालांकि इससे पहले 2006 में वह एक और बड़े हादसे का शिकार हुए थे. उन्हें कहां पता था कि करियर के चरम पर जिस रफ्तार से वह आगे बढ़ रहे हैं, वही रफ्तार एक दिन उन्हें इस ट्रैक से हमेशा के लिए अलविदा कर देगी.

अभी डैन व्हेलडन की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से रफ्तार ने एक और रेसर की जान ले ली. इस बार का हादसा कार रेस का ट्रैक न होकर बाइक रेसिंग ट्रैक का था. इस बार दुर्घटना का शिकार बने इटली के बाइक रेसर मार्को सिमोनसेली. अजीब संयोग है,

ऐसा नहीं है कि दुर्घटनाएं इससे पहले नहीं हुई. लेकिन पहले के हादसों में चोटें लगती रही है. इसलिए सुरक्षा के मसलों पर इस तरह के सवाल नहीं उठाए गए लेकिन अब सवाल खिलाड़ियों की मौत का है. मामला उठा लास वेगस इंडीकार 300 रेस में ब्रिटिश ड्राइवर डैन व्हेलडन की मौत से. रेस के आख़िरी लैप में 15 कारें जब भिड़ी तो अहसास हो गया था कि दुर्घटना ख़तरनाक है. 77 नंबर की गाड़ी से पहचाने जाने वाले व्हेलडन के आगे चार कारें टकराईं. टक्कर के बाद कारों में आग लग गई. उन दो कारों को बचाने के चक्कर में एक ड्राइवर ने स्पीड कम कर बाएं मुड़ने की कोशिश की तो बायीं तरफ़ से आ रही कारें आपस में भिड़ गईं.

2008 में मलेशिया के जिस सर्किट पर सिमोनसेली वर्ल्ड चैंपियन बने थे, उसी ट्रैक पर उन्होंने अपने जीवन की आख़िरी रेस पूरी की. मार्को अभी 24 साल के ही थे. मार्को सिमोनसेली मलेशियन मोटो जीपी के दूसरे ही लैप में हादसे का शिकार हो गए. तीखे मोड़ पर बाइक सिमोनसेली के नियंत्रण से बाहर हो गई. उनके पीछे चल रहे अमेरिकी बाइकर कॉलिन एडवर्डस और इटली के वैलेंटिनो रोसी की तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलें पलक झपकने से पहले ही सिमोनसेली से टकरा गईं. एडवर्डस की मोटरसाइकिल ट्रैक पर फिसल रहे सिमोनसेली के सिर और धड़ से टकराई. टक्कर कितनी ज़ोरदार थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब टक्कर हुई तो सिमोनसेली का हेलमेट उनके सिर से निकलकर दूर छटक गया. उनके साथी प्रतियोगी भी इस टक्कर में ट्रैक पर फिसले, लेकिन उन्होंने अपना नियंत्रण नहीं खोया, लेकिन इस मामले में मार्को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली नहीं रहे. अभी हाल की बात की जाए तो फॉर्मूला वन ड्राइवर रॉबर्ट कूबिका भी इस रफ्तार के शिकार हो चुके हैं, लेकिन वह सिर्फ़ जख्मी ही हुए थे. सही समय पर उनको सुरक्षित बचा लिया गया. ये तीनों घटनाक्रम तो अभी ताज़ा हैं, लेकिन इससे पहले भी कई खिलाड़ी अलग–अलग प्रतियोगिताओं में जख्मी हो चुके हैं.

इन हादसों से सुरक्षा पर सवाल तो खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असर इन खेलों से जुड़े अन्य खिलाड़ियों पर पड़ा है. इन दुर्घटनाओं के कारण उनके मनोबल टूटा है. इस तरह की घटनाओं के लिए अकेले सुरक्षा व्यवस्था ही ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सुरक्षा को लेकर तकनीक और मानक बेहतर नहीं हुए हैं. दरअसल, इस तरह के तेज़ रफ्तार वाले खेलों में जोख़िम तो हमेशा ही बना रहता है. रेस जीतने का जुनून और कुछ भी कर गुज़रने की चाहत में खिलाड़ी भी तेज़ी के नशे में कुछ यूं चूर हो जाते हैं कि नशा उतरते–उतरते किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं.

इसी नशे का नतीजा है कि 2006 से अब तक मोटरसाइकिल रेसों में पांच रेसरों की मौत हो चुकी है तथा 20 से ज़्यादा बुरी तरह घायल हुए हैं. इन्हीं कारणों से बदलाव की बात चल रही है. इस रेस के बड़े आयोजकों में शुमार मोटो जीपी का कहना है कि 2012 से सभी टीमों के लिए एक समान तकनीकी मानक बनाए जाएंगे. कोई भी टीम किसी भी तरह के बदलाव कर इंजन की क्षमता 1000 सीसी से ज़्यादा नहीं कर सकेगा. टायर, सिलेंडर, वज़न और पिस्टन को लेकर सभी टीमों को एक नियम मानना होगा. अब मोटर जीपी जिन बदलावों की बात कर रहे हैं, उससे इतना तो साफ़ हो जाता है कि दुर्घटनाओं को रोकने का समाधान जो 2012 से लागू किए जाने की बात हो रही है, वो पहले भी हो सकती थी. ऐसा होने से हम इतने युवा और होनहार खिलाड़ियों को खोने से तो बच जाते.

राजेश एस कुमार
rajeshy@chauthiduniya.com

एक्सट्रा शॉट्स

वॉर्नर के ख़ुलासे

फीफा के पूर्व उपाध्यक्ष जेक वार्नर ने वादा किया कि वह फीफा अध्यक्ष सर सेप ब्लाटर के बारे में सनसनीख़ेज़ ख़ुलासे करेंगे. त्रिनिदाद और टोबैगो के निर्माण मंत्री वार्नर को फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा के अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले रिश्वत स्कैंडल और फीफा के एक अन्य उपाध्यक्ष मोहम्मद बिन हम्माम की बर्ख़ास्तगी के बाद फीफा कार्यकारी समिति और अमेरिका फुटबॉल परिसंघ के प्रमुख का पद छोड़ना पड़ा था. वार्नर ने एक समाचार पत्र को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि ब्लाटर ने 1998 और 2002 में अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के दौरान उनका और बिन हम्माम का इस्तेमाल इसी तरह के तोहफेकी पेशकश करने के लिए किया था. वार्नर ने लिखा है कि हमने पूरी दुनिया में ब्लाटर के समर्थन के लिए अपील की और वह जीत गया. उन्होंने कहा कि यह पहला मौक़ा था जब मैं फीफा नैतिक समिति केउपाध्यक्ष पेट्रस दामासेब से मिला जो तब नामीबिया फुटबॉल संघ के अध्यक्ष थे. वार्नर के मुताबिक़ वह दुनिया को बताएंगे कि तब बिन हम्माम ने उन्हें क्या तोहफा दिया था, जो उस समय रिश्वत नहीं था,जैसा कि उन्होंने अब कहा है. फीफा के इस पूर्व उपाध्यक्ष ने कैरेबियाई फुटबाल यूनियन(सीएफयू)अधिकारियों के साथ बिन हम्माम की विवादास्पद बैठक का वीडियो लीक करने केलिए फीफा को दोषी ठहराया. पिछले हफ्ते एक ब्रिटिश अख़बार की वेबसाइट पर डाले गए वीडियो में वॉर्नर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह बैठक में बिन हम्माम केसीएफयू प्रतिनिधिमंडल को पैसे की पेशकश करने के पक्ष में नहीं थे.

फिर निशाने पर सचिन

शोएब अख्तर की किताब का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि पूर्व आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और भारत के पूर्व कोच ग्रेग चैपल अपनी किताब को बेचने के चक्कर में एक बार फिर से सनसनी फैला दी है. अपनी नई किताब में चैपल ने तेंदुलकर को मानसिक रूप से कमज़ोर बतया है.फीयर्स फोकस नामक इस किताब में उन्होंने लिखा है कि तेंदुलकर 2006 में मानसिक तौर पर काफी कमज़ोर रहे. उन्होंने लिखा है कि भारतीय टीम के साथ मेरे शुरुआती दौर में तेंदुलकर मुझसे दो-दो घंटे तक बात करते थे. हेराल्ड सन में प्रकाशित किताब के कुछ अंशों में कहा गया कि वह अपने फार्म को लेकर संशय में थे. मलेशिया में 2006 में वनडे टूर्नामेंट से लौटने के बाद मानसिक तौर पर वह आश्चर्यजनक रूप से काफी कमज़ोर हो गए थे और मेरे पास मदद के लिए आते थे. कुछ महीने पहले ही आस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय चयनकर्ता के पद से हटाए गए चैपल ने कहा कि तेंदुलकर अपेक्षाओं के बोझ से दबे हुए थे.टीम जब विदेश दौरे पर जाती थी तो तेंदुलकर हमेशा हेडफोन लगाए रहते थे तथा आजू-बाजू देखते भी नही थे. इतनी अधिक अपेक्षाओं का बोझ डान ब्रैडमेन पर भी नहीं रहा होगा जितना सचिन 1989 से झेल रहे है. वह आराम भी नहीं कर पाते थे. एक बार मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे तो बहुत सारे दोस्त होंगे और उन सबसे संपर्क में रह पाना मुश्किल होता होगा, तो उन्होने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझसे ज़्यादा भारत में आपके दोस्त होगें. चैपल की यह किताब ऐसे समय में आई है, जबकि दो महीने बाद टीम इंडिया चार टेस्ट मैचों का आस्ट्रेलिया दौरा करेगी, जो संभवत: तेंदुलकर का आख़िरी आस्ट्रेलिया दौरा होगा. इससे कुछ दिन पूर्व पाक के पूर्व गेंदबाज़ शोएब अख्तर ने सचिन को डरपोक बताया था. हालांकि बाद में उन्होंने अपनी सफाई भी दी थी.

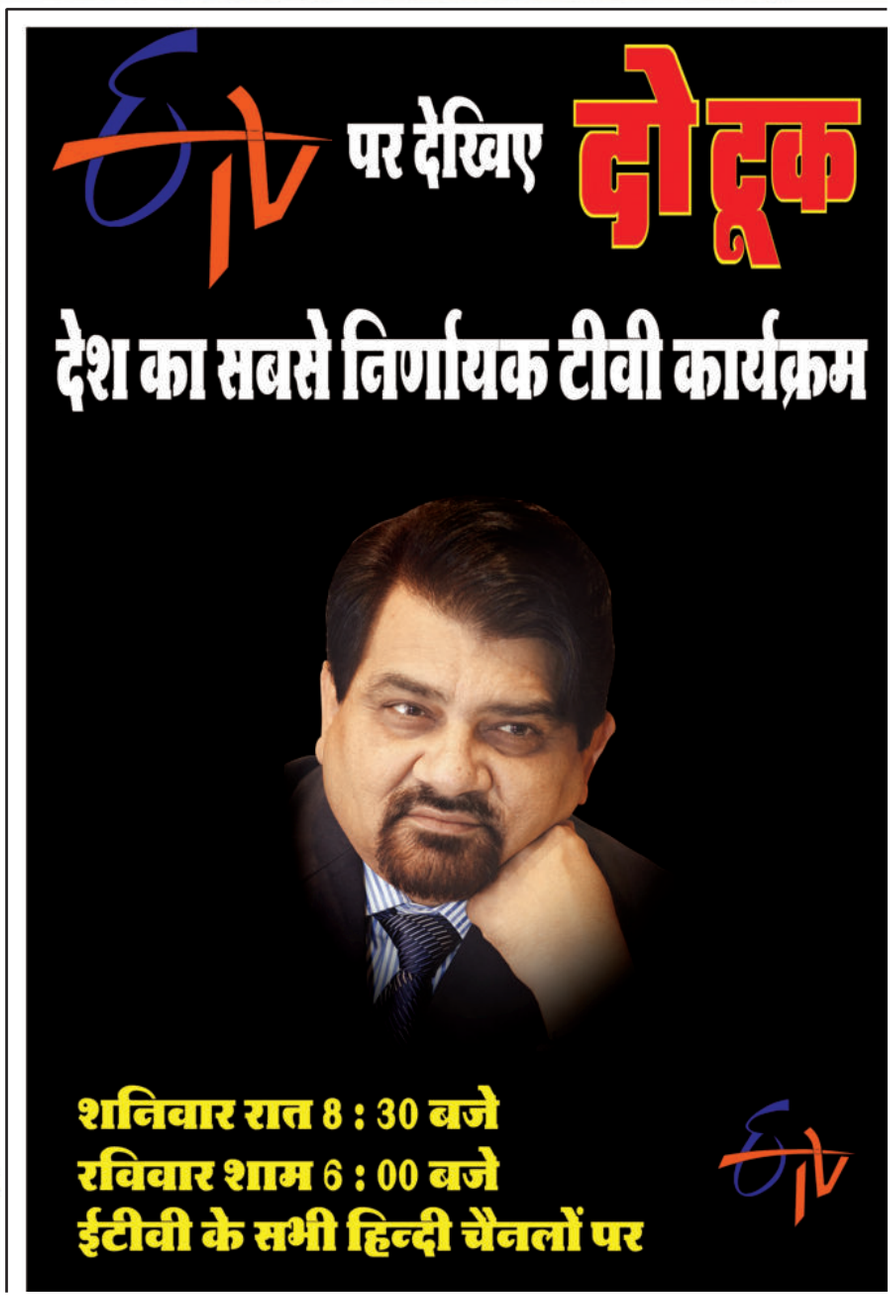

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 07 नवंबर-13 नवंबर 2011

जी हां जैसे की सबको पता है कि विद्या बालन सन्नी देओल के साथ उनके सीक्वल में काम कर रही थीं लेकिन अब घायल रिर्टन्स में अंतिम क्षणों में इंकार कर दिया है.

प्रियंका की नई रेस

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने रेस 2 में काम करने से मना कर दिया है. वह इस समय अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी के लिए काम कर रही है. लेकिन अब ख़बर आई है कि इस फिल्म में काम करने के लिए प्रियंका चोपड़ा से बात की है. अब्बास-मस्तान चाहते थे कि दीपिका की जगह वे किसी नामी हीरोइन को लें और प्रियंका इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. हालांकि प्रियंका के लिए इतनी जल्दी डेट्स एडजस्ट करना मुश्किल है. प्रियंका ने न नहीं की है, लेकिन अगर उनके डेट्स की प्रॉबलम सॉल्व हो जाती है तो वह फिल्म में ज़रूर काम करेंगी. जब अचानक ही फिल्म की हीरोइन काम करने से मना कर दें तो शूटिंग शेड्यूल ख़राब हो ही जाता है. दीपिका के मना करने से फिल्म का काम बढ़ ही चुका है. प्रियंका और अब्बास-मस्तान पहले फिल्म ऐतराज में साथ काम कर चुके हैं. इस फिल्म में प्रियंका नेगेटिव शेड में नज़र आई थी और उनके काम को लोगों ने काफी पसंद भी किया था. देखते हैं अब वह कौन से शेड में नज़र आएंगी.

एमा की ख़्वाहिश

हॉलीवुड ऐक्ट्रेस एमा वाटसन चाहती हैं कि शेक्सपीयर के नाटक रोमियो ऐंड जूलियट पर आधारित फिल्म बने और वह इसमें जूलियट की भूमिका निभाएं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह इच्छा जताई कि वह ट्रेजडी से भरपूर जूलियट जैसा किरदार निभाना चाहती हैं. शेक्सपीयर के ही दूसरे नाटक हेमलेट पर आधारित फिल्म में भी वे ओफीलिया का रोल करना चाहती हैं. मशहूर फिल्म हैरी पॉटर की नायिका एमा बज लुरमैन, गुलरमो डेल तोरो, रिचर्ड कर्टिस, डेरेन आदि निर्देशकों के साथ भविष्य में काम करना पसंद करेंगी. एमा उस समय मात्र नौ साल की थीं, जब उन्होंने हैरी पॉटर फिल्म में हरमियन का रोल किया था. वर्ष 2001-2011 तक हैरी पॉटर के आठों सीरीज में वे डेनियल रेडक्लिफ और रुपर्ट ग्रिंट के साथ काम कर चुकी हैं. इस सीरीज में काम करने की वजह से उन्हें ढेरों पुरस्कार भी अब तक मिल चुके हैं. उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत बरबेरी के कैंपेन से की थी. ग़ौरतलब है कि एमा वाटसन का जन्म पेरिस, फ्रांस में हुआ. उनके माता-पिता वकील थे. जब वे मात्र पांच वर्ष की थीं, तभी माता-पिता का तलाक हो गया. वे और उनके छोटे भाई दोनों मां के साथ इंग्लैंड चले आए. वह छह साल की उम्र से ही अभिनेत्री बनना चाहती थीं. इसलिए उन्होंने इंग्लैंड में स्टेजकोच थियेटर आर्टस से एक्टिंग और गाने-नाचने की ट्रेनिंग ली. उन्होंने बचपन में कई स्टेजकोच प्रोडक्शंस और स्कूल प्ले में एक्टिंग की. बैले शू नॉवेल पर आधारित टीवी शो और एक एनिमेशन फिल्म द टेल ऑफ डिस्पैरेक्स की. वह सह निर्माता भी रह चुकी हैं. उन्होंने ऑक्सफोर्ड शहर के अलग-अलग स्कूल में अपनी पढ़ाई की. जब वह हैरी पॉटर के सेट पर होती थीं, तो उनका ट्यूटर उन्हें दिन भर में पांच घंटे पढ़ाता था. फिल्मों में काम करने के बावजूद एमा पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहीं और उन्होंने इसी तरह पढ़ाई पूरी की. अब देखने वाली बात यह है कि एमा की हसरत, जो जूलियट का रोल करने की है, पूरी होती है या नहीं.

फिल्म प्रीव्यू

रॉक स्टार

बॉलीवुड को जब वी मेट जैसी बेहतरीन फिल्म दे चुके निर्देशक इम्तियाज़ अली अब अपनी अगली फिल्म रॉकस्टार के साथ तैयार हैं. बीते बरसों में बॉलीवुड ने अभिमान, सुर, रॉक ऑन जैसी संगीतप्रधान फिल्में दीं. अब जल्दी ही एक और संगीतप्रधान फिल्म रॉकस्टार आने वाली है, जो बॉलीवुड और संगीत के गहरे रिश्ते को और भी मज़बूत बनाएगी. इम्तियाज़ अली की रॉकस्टार का निर्माण इरोस इंटरनेशनल, श्री अष्टविनायक सिने विजन लिमिटेड ने मिलकर किया है. फिल्म में बॉलीवुड के चॉकलेटी ब्वॉय रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे. रणबीर एक छोटे शहर के लड़के की भूमिका में हैं जिसका सपना एक बड़ा रॉकस्टार बनने का है. इसमें वह विदेशी बाला नरगिस फाखरी के साथ इश्क फरमाएंगे. नरगिस एक अमेरिकी मॉडल और अभिनेत्री हैं. अभिनेता रणबीर कपूर फिल्म रॉकस्टार में 10 अलग-अलग अवतार में नज़र आएंगे. जिसमें रॉकस्टार और कव्वाल रूप भी शामिल है. कव्वाल के रोल में रणबीर को कव्वाली वाली टोपी, लंबे बाल, दाढ़ी और गिटार के साथ दिखेंगे. रॉकस्टार एक ऐसे सफल युवा संगीतकार की है जो प्यार में यक़ीन करता है लेकिन उसके प्यार में धोखा मिलता है. इस फिल्म में दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर ने भी अभिनय किया है. यह शम्मी कपूर की अंतिम फिल्म है. इस फिल्म के लिए गाने लिखे हैं ए आर रहमान ने और दो गानों को इटालियन, कनाडियन गायक नेटाली डी लुसियो ने तैयार किए हैं. फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग दिल्ली में हुई है. साथ ही फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग दिल्ली के सेंट स्टीफन और हिंदू कॉलेज में भी की गई है.

रिया के नखरे

बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाकाम करियर, इसके बावजूद नखरे. यह कहानी है बंगाली ब्यूटी रिया की. अभी हाल ही में निर्देशक इश्राक शाह की फिल्म एक बुरा आदमी के सेट्स पर तब गहमागहमी का माहौल बन गया जब अभिनेत्री रिया सेन ने अरुणोदय सिंह के साथ आइटम नंबर करने से मना कर दिया. यही नहीं उन्होंने तो शूटिंग कवरेज के लिए आमंत्रित मीडिया से भी बात करने से इंकार कर दिया. शाह ने कहा कि यह एक बुरा सपना था. रिया का कहना था कि यह सब कुछ प्रचार के लिए किया जा रहा है. उन्होंने बताया, रिया के साथ फिल्म में एक आइटम गीत के लिए अनुबंध हुआ था. हमने एक बहुत अच्छा गीत उछल गयी छमिया कुंवारों के बीच में रिकॉर्ड किया था. आरक्षण में नृत्य-निर्देशन करने वाले जयेश प्रधान इस गीत के लिए रिया को नृत्य-निर्देशित करने वाले थे. सब कुछ पहले से तय था. बाद में रिया ने कहा कि वह अस्वस्थ हैं और आइटम गीत के लिए रिहर्सल नहीं कर सकतीं. इसके बाद उन्होंने सिर्फ़ एक दृश्य दिया. मैं सहमत था क्योंकि अरुणोदय भी एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए अमेरिका निकल गए थे लेकिन बाद में रिया ने मीडिया से बात करने से भी मना कर दिया. शाह ने कहा, मैं एक नया निर्देशक हूं. मेरे लिए यह सब कुछ बहुत नया और शर्मिंदगीपूर्ण था. रिया के नखरे की वजह से मेरे निर्माता को कम से कम 70-80 लाख रुपये का नुक़सान हुआ. मुझे नहीं पता कि अब हम इस गीत की शूटिंग कैसे करेंगे. अब देखते हैं कि इस नखरे का ख़ामियाज़ा रिया को कितना उठाना पड़ सकता हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मिनीषा का टीवी अवतार

मिनीषा लांबा जल्द ही टीवी पर आने वाली हैं. इस शो को ग्लैमरस से भरपूर रखने के लिए वह डिज़ाइन पर विशेष ध्यान दे रही हैं. इसी सिलसिले में जब उनसे पूछा गया कि वह बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेस की तरह मिनीषा ने कान फिल्म फेस्टिवल में वेस्टर्न डिज़ाइनर की ड्रेस क्यों नहीं पहनी? इस सवाल पर मिनीषा बोलीं, कान फिल्म फेस्टिवल मूवीज सेलीब्रेट करने के लिए होता है, मगर आजकल किसने क्या पहना है, इस पर ज़्यादा ध्यान रहता है. मुझे लगता है कि इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल तय होना चाहिए. और फिर हमारे इंडियन डिज़ाइनर्स की क्रिएटिविटी को अगर हम इज़्ज़त नहीं देंगे तो कौन देगा? फैशन से हटकर फिल्मों पर चर्चा करते हुए मिनीषा ने अपनी चर्चित फिल्म ज़िला गाजियाबाद पर भी बात की. उन्होंने बताया कि यह एक पॉलिटिकल बैंक ड्रॉप की थ्रिलर है. अपने किरदार के बारे में उन्होंने कहा कि मैं पूरी फिल्म में घर की चहारदीवारी में कैद लहंगा चोली पहनने वाली लड़की का रोल कर रही हूं. मिनीषा के मुताबिक़ उन्हें इंडियन ड्रेस अच्छी लगती हैं क्योंकि इसमें वे चटपटा ख़ूबसूरत लुक देती हैं. कार्यक्रम के बारे में उनका कहना था कि वह अपने टॉक शो में गॉसिप नहीं दिखाएंगी.

विद्या का डर्टी स्टाइल

डर्टी पिक्चर अभी रिलीज भी नहीं हुई हैं कि उनका डर्टी व्यवहार सामने आने लगा है. सुनने में आया है कि उन्होंने सनी देओल के साथ कुछ ऐसा किया जो वह बर्दाश्त नहीं कर पाए. जी हां जैसे की सबको पता है कि विद्या बालन सन्नी देओल के साथ उनके सीक्वल में काम कर रही थीं लेकिन अब घायल रिर्टन्स में अंतिम क्षणों में इंकार कर दिया है. उनका कहना है कि जब तक उनकी फिल्म डर्टी पिक्चर्स प्रदर्शित नहीं हो जाती है, वे इस फिल्म की शूटिंग में भाग नहीं ले सकती हैं. यह बात तो विद्या पहले भी कह सकती थी लेकिन जब सब कुछ फिक्स हो गया है तब जाकर विद्या ने मना कर दिया. जिससे फिल्म यूनिट का पूरा कार्यक्रम डगमगा गया है. ख़ैर फिल्म को और ज़्यादा न रोकते हुए अब फिल्म निर्देशक अभिनेत्री बिपाशा बसु से बातचीत कर रहे हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब सन्नी देओल के साथ नायिका के तौर पर बिपाशा बसु नज़र आएंगी. देखना दिलचस्प होगा कि सन्नी और बिल्लो की इस जोड़ी को लोग क्या रिस्पांस देगें या नहीं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

तुम जियो हजारों साल

कलात्मक फिल्मों की नायाब नायिका नंदिता दास

यह मानना मुश्किल होगा कि इंटेलेक्चुअल सिनेमा में कामयाबी का एक सफर तय कर चुकी नंदिता दास का मन पढ़ने में नहीं लगता था. यह बात बचपन की नहीं बल्कि कॉलेज के दिनों की है. हालांकि वह पढ़ने में तो अच्छी थी लेकिन किताबों से दिल नहीं लगा पाई. आज जिस नंदिता को हम जानते हैं उसकी नींव भी कॉलेज के दिनों की ही है, मगर कोर्स की किताबों के बजाय शौक की वजह से. उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह एक अभिनेत्री बनेंगी और न ही उन्हें अभिनय का शौक था, उन्हें केवल लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था. भूगोल से स्नातक करने के बाद उनकी इस विषय से रूचि हट गई, आगे पढ़ने के लिए मां-बाप ने मजबूर किया तो ऐसे विषय को पढ़ना चाहती जिसमें पढ़ाई न करनी पड़े. उन्होंने सोशल वर्क विषय लेकर एम.ए. पूरा किया. वह एनजीओ में काम कर रही थीं उसी वक़्त थिएटर भी करती थीं और फिल्मों में आना भी उसी दौरान हुआ. औरतों के लिए एनजीओ में काम करते हुए एक शॉर्ट फिल्म भी की वह फिल्म एक थी गुंजा. इस फिल्म के बारे में किसी ने लिखा और फिर दीपा मेहता से उनका ज़िक्र किया. बस यही ज़िक्र उनके करियर में फायर जैसी बोल्ड फिल्म आई. फायर के बाद वह 1947-अर्थ में आमिर ख़ान के साथ दिखीं. इस फिल्म में भी नंदिता का अभिनय उल्लेखनीय रहा. नंदिता ने ऑफबीट फिल्मों से मुख्य धारा की फिल्मों की ओर उन्होंने रुख़ किया और अक्स में अमिताभ बच्चन की नायिका के रूप में दिखीं. गंभीर भूमिकाओं में अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन करने के बाद सुपारी में महिला डॉन की भूमिका को भी बड़े प्रभावी अंदाज़ में उन्होंने जिया. बड़े पर्दे पर हर रंग की भूमिकाएं निभाने के बाद नंदिता ने निर्देशन में भी हाथा आजमाया. फिल्म फिराक के निर्देशक के तौर पर नंदिता दास ने गुजरात दंगों के अनछुए पहलुओं पर बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई. अब नंदिता मां भी बन चुकी हैं और साथ ही मानव तस्करी जैसे विषय पर एक और फिल्म बनाने का विचार कर रही हैं. स्मिता पाटिल के बाद हिंदी सिनेमा में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर नंदिता दास का ही नाम लिया जाता है. उम्मीद करते हैं इस बेहतरीन अदाकारा का और भी बेहतरीन काम हमें देखने को मिलता रहेगा. उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.

चौथी दुनिया

दिल्ली, 07 नवंबर–13 नवंबर 2011

www.chauthiduniya.com

आडवाणी ने माना

घर को आग लग गइ घर के चराग़ से

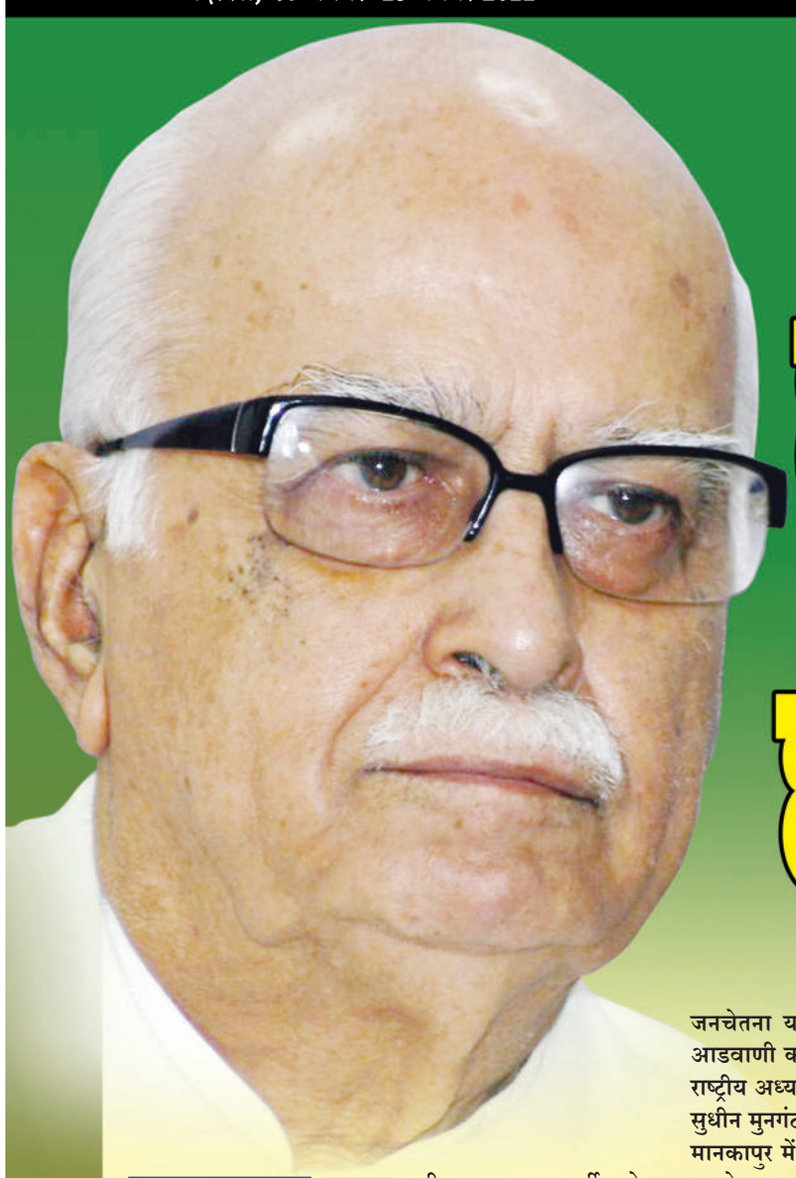

प्रवीण महाजन

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लालकृष्ण आडवाणी जनचेतना यात्रा रथ के साथ जब नागपुर पहुंचे तो उन्हें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा. मसलन क्या आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है? बी.एस. येदियुरप्पा को लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर भ्रष्टाचार का दोषी पाये जाने पर गिरफ्तार किया जा चुका है, फिर भी पार्टी उन्हें पहले क्यों बचाती रही? क्या भ्रष्ट नेताओं की वजह से भाजपा की छवि खराब नहीं हो रही है? आप भ्रष्टाचार और आत्मानुशासन की बात को लेकर पूरे देश में जनचेतना यात्रा निकाल तो रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर क्यों नहीं करते हैं? इन कड़वे सवालों से सामना होने के बाद आखिरकार लालकृष्ण आडवाणी ने स्वीकार किया कि भ्रष्ट नेताओं व कार्यकर्ताओं की वजह से भाजपा कमजोर हुई है और पार्टी की साख को धक्का भी लगा है. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को मैंने भ्रष्टाचार के मामले में चेताया था, लेकिन उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी. इसके पहले जनचेतना यात्रा के महाराष्ट्र में प्रवेश करने पर लालकृष्ण आडवाणी का सावनेर तहसील के केलवद गांव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे और प्रदेशाध्यक्ष सुधीन मुनगंटीवार ने स्वागत किया, लेकिन नागपुर पहुंचने पर मानकापुर में कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए. हालांकि, जनचेतना यात्रा नागपुर के सभा स्थल चिटणीस पार्क में दो घंटे विलंब से पहुंची. जिससे वहां आडवाणी का भाषण सुनने आये लोग निराश होकर वापस जाने लगे. नज़ारा यह था कि चिटणीस पार्क में भाजपा नेताओं की अपेक्षा से भी कम भीड़ जुटी थी. ऊपर से कार्यक्रम देर से शुरू होने के कारण लोग बाहर जाने लगे थे. किसी के कहने पर पुलिस बाहर जा रहे लोगों को गेट पर ही रोक लिया और गेट पर ताला लगा दिया. ताला लगाने का आदेश किसने दिया? लोगों के इस सवाल का पुलिस ने कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया. लोग कहते रहे कि आम जनता को समारोह में जबरन रोकने का कहां का क़ानून है. लोगों को यहां तक कहते सुना गया कि सत्ता पाने के लिए भाजपा इस हद तक जा सकती है यह पता चल चुका है. यहां लोगों को आडवाणी का भाषण जबरन सुनना पड़ा.

आडवाणी समेत सभी भाजपा नेताओं ने केंद्र की यूपीए सरकार और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को निशाना बनाया. आडवाणी ने अपने भाषण में कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में कमजोर सरकार चल रही है. हमें प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह पर दया आती है, क्योंकि उन्हें हर मामले में 10 जनपथ जाकर अनुमति लेनी पड़ती है. देश के गृहमंत्री पी. चिदंबरम और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी पत्र वार में उलझे हुए हैं. देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और महंगाई की ओर किसी का ध्यान नहीं है. विदेशों में जमा कालाधन देश में वापस आने पर उससे करीब छह लाख गांवों में स्कूल और अस्पताल खोले जा सकते हैं. इन पैसों से सड़कें बनाई जा सकती हैं, किसानों को सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती हैं, देश में बिजली की कमी को दूर किया जा सकता है. आडवाणी के मुताबिक कालाधन देश में लाना बेहद ज़रूरी है. सरकार को कालेधन को लेकर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए. उनके अनुसार भाजपा आगामी संसद सत्र में कालेधन के मसले पर श्वेतपत्र लाने की पुरजोर मांग करेगी. हालांकि, उनके भाषण की ख़ास बात यह रही कि आडवाणी ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की गिरफ्तारी का जिक्र कहीं नहीं किया. वे इस मुद्दे पर बात करने से कतराते रहे, लेकिन नागपुर प्रवास के दूसरे दिन हुई प्रेस वार्ता में येदियुरप्पा को आगाह करने की बात कही. उन्होंने यह भी माना कि भ्रष्ट पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के कारण भाजपा की साख को बट्टा लगा है. ख़ास बात यह है कि सभा स्थल में जमा आम लोग आपस में बातचीत के दरम्यान कहते सुने गए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आडवाणी को पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस येदियुरप्पा को भाजपा अब तक क्यों बचाती रही? लोकायुक्त की रिपोर्ट को आडवाणी सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी नज़रअंदाज़ क्यों करते रहे? दूसरों को भ्रष्टाचार पर उपदेश देने वाले भाजपा नेता अब कह रहे हैं कि उन्होंने येदियुरप्पा को आगाह किया था.

संघ ने किया किनारा

भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की जनचेतना यात्रा के नागपुर आगमन पर सभा स्थल पर उनके साथ एक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी मौजूद न रहने से यह साफ हो गया कि उनकी इस यात्रा को संघ का समर्थन प्राप्त नहीं है. संघ का समर्थन न मिलने के कारण हालत यह थी कि सभा स्थल पर भाजपा कार्यकर्ता भीड़ जुटाने में भी असमर्थ नजर आयी. मुश्किल से करीब दो हजार लोग ही सभा स्थल में मौजूद थे. उनमें से भी वापस लौट रहे लोगों को गेट पर ताला लगा कर रोका गया, ताकि आडवाणी जब भाषण दें तो कुछ लोग तो मौजूद रहें. वहीं जब आडवाणी ने अयोध्या रथ यात्रा निकाली थी तब उन्हें संघ का पूरा समर्थन हासिल था और संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तन–मन–धन से उसे सफल कराने में जुटे थे, लेकिन इस बार जनचेतना यात्रा संघ के सहयोग के बिना निष्प्रभावी रही. इससे यह अटकलें लगाई जा रही है कि आडवाणी की इस यात्रा से संघ खुश नहीं है.

येदियुरप्पा को भुलाया और शिवराज की तारीफ़ की

ऐसा लगता है कि जिस नेता का सितारा डूबने लगता है उसे भाजपा तुरंत ही भुलाने लगती है. लालकृष्ण आडवाणी ने नागपुर की सभा में येदियुरप्पा को भुलाने में ही भलाई समझी, क्योंकि वे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं. वहीं आडवाणी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ़ की. इसका कारण शायद यह है कि मध्यप्रदेश में कुछ जगहों पर आडवाणी का रथ पहुंचने के पहले स्थानीय पत्रकारों को गिफ्ट व रुपये बांटे गये, ताकि यात्रा के संबंध में कोई पत्रकार नकारात्मक ख़बर प्रकाशित न करें.

गडकरी और मुंडे का मिलाप

राजनीति में दोस्ती–दुश्मनी कभी टिकाऊ नहीं होती है. यह कहावत लालकृष्ण आडवाणी के नागपुर आगमन पर फिर एक बार सत्य साबित हुई जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और लोकसभा में पार्टी के उपनेता नेता गोपीनाथ मुंडे एक साथ उनकी अगवानी करते नजर आए. वैसे भी कहा जाता है कि राजनीति में विचार और पद को लिये मनमुटाव हो सकते हैं, पर सत्ता के लिए मित्रता जरूरी है. भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी की जनचेतना यात्रा के दरम्यान गडकरी और मुंडे को एक साथ देखकर ऐसा लगा कि दोनों में सुलह हो गई. आडवाणी के नागपुर प्रवास के दरम्यान दोनों जैसे एक ही गाड़ी में बतियाते और साथ बैठकर भोजन करते देखे गए उससे लगता है कि दोनों ने अपने गिले–शिकवे दूर कर गले मिले हैं. यदि यह सच है तो गडकरी–मुंडे का का यह मिलाव भाजपा के हित में है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार

कार्यालय स्थानांतरित

साप्ताहिक चौथी दुनिया के कार्यालय का स्थानांतरण 28 सितंबर को सीताबर्डी स्थित मुरलीधर काम्प्लेक्स में हो गया है. अतः चौथी दुनिया के सभी पाठकों, एजेन्टों व हॉकरो से अनुरोध है कि वे कार्यालयीन कार्य के लिए नीचे दिए पते पर संपर्क करें–

फोन नं.- 0712-2544988, 2549846

साप्ताहिक चौथी दुनिया

आशीर्वाद पब्लिकेशन

मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाड़ा के सामने, होटल गणराज के बाजू में, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी नागपुर

E-mail : chauthiduniyaa@gmail.com

इस अध्यादेश को जारी करने से यह बात साफ हो गई है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीति किसानों के लिए नहीं, बल्कि बैंकों व पूंजीपतियों के लिए फ़ायदेमंद है.

नेहरू ने कहा था कि देश की रक्षा करने के कई तरीके होते हैं. सेना के बल पर देश की रक्षा होती है यह सामान्य समझ है.

महाराष्ट्र हलचल

नागपुर में आयोजित महिला उद्योजक सम्मान समारोह को संबोधित करतीं मुख्य अतिथि अभिनेत्री किरण खेर और मंचासीन महापौर अर्चना डेहनकर, भाजपाध्यक्ष नितिन गडकरी, पश्चिम नागपुर के विधायक सुधाकर देशमुख व अन्य.

नागपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर ममतानी की वेबसाइट का उद्घाटन करते भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और अनंत कुमार.

नरीमन प्वाइंट स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी महासचिव वेंकैया नायडू खड़कवासला विधानसभा उपचुनाव में जीते भीमराव तापकीर का सत्कार करते हुए. इस मौके पर के गोपीनाथ मुंडे, प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, सुनील कर्जतकर, किरीट सोमैया, माधुरी मिसाल, गिरीश बापट और रमेश भेगड़े भी मौजूद रहे.

नायगाव पुलिस मुख्यालय में महाराष्ट्र पुलिस स्मरण दिवस पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण. उनके साथ हैं गृहमंत्री आर.आर. पाटिल, सतेज पाटिल, पुलिस महासंचालक के. सुब्रमण्यम और मुंबई पुलिस आयुक्त अरूप पटनाईक.

युवक कांग्रेस अध्यक्ष विश्वजीत कदम, राज्यमंत्री राजेंद्र मुलक, सांसद दत्ता मेघे, युवा कांग्रेस नागपुर के अध्यक्ष समीर मेघे, नागपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता की मौजूदगी में जरूरतमंद छात्रों के बीच साइकिल वितरित किया गया.

हज यात्रियों को उनके सगे-संबंधी यात्रा की कुशलता की कामना के साथ विदा करते हुए.

नागपुर के मुख्य बाजार सीताबर्डी में दीपावली के पर्व पर खरीददारी करने आए लोगों की भारी भीड़.

भारत-चीन लड़ाई के 49 साल

हार सेना की या नेताओं की

बिग्रेडियर हेमंत महाजन (सेवानिवृत्त)

चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमला किया था. गांधीजी और सरदार पटेल के देहांत के बाद पंडित नेहरू देश के सर्वेसर्वा हो गए. वे जो कहेंगे वही सही होगा यह स्थिति भारत में बन गई थी. भारतीय सैनिकों की बैठक बुलाकर सेना ने युद्ध संबंधी छोटे प्रबंध बनाये. कुछ समय बाद नेहरू ने कहा कि हमें सेना की जरूरत नहीं है. पुलिस बल ही काफी है. हमारी नीति अहिंसावादी है नेहरू ने सेना को कश्मीर भेज दिया. हैदराबाद सेना भेजी गई. गोवा में भी सेना को भेजा गया. हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं इस ओर ध्यान न देने वाला यह नेतृत्व था. नेहरू ने कहा था कि देश की रक्षा करने के कई तरीके होते हैं. सेना के बल पर देश की रक्षा होती है यह सामान्य समझ है. दूसरे देशों से मैत्री संबधी नीति के मद्देनजर देश की सुरक्षा के लिए सेना की अपेक्षा अन्य कई तरीके कामयाब हो सकते हैं. पंडित नेहरू ने जो विदेश नीति के मुख्य आधार स्थापित किए वे केवल कागजी थे. इसलिए यह नीति एक हवा के झोंके से दिया बुझने के समान साबित हुई. सीमा संघर्ष के संबंध में नेहरू ने कहा कि मेरा ध्येय है विश्व शांति का झंडा फहराना है. भारत के साथ धोखा हुआ है. चीन ने हमारे साथ धोखा किया है और दुनिया ने भी हमारे साथ धोखा किया है.

सीमा विवाद कैसे पैदा हुआ

चीन-भारत के मध्य सीमा विवाद कैसे पैदा हुआ यह काफी बड़ा सवाल है? चीन ने तिब्बत पर जब से कब्जा किया तब से सीमा विवाद का प्रश्न सामने खड़ा है. मैकमेहान नाम के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा जो सीमारेखा खींची गई थी वह तिब्बत-भारत सीमारेखा है. नेहरू ने फॉरवर्ड नीति को अपनाया और इस नीति को क्रियान्वित करने का आदेश दिया था. तभी से सेना ने फॉरवर्ड पॉलिसी को पूरी ताकत से अपनाने का काम किया. जिसके जबाव में चीनी प्रतिक्रिया अधिक तीखी हो गई. कश्मीर के पश्चिम भाग की ओर वाहन व अन्य सैन्य साजो-सामान की कमी होने से यदि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया तो इसका जवाब देना भारतीय सेना के समर्थ के बाहर होगा. ऐसा सैन्य विशेषज्ञों का मानना है. राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों के पास सैन्य प्रश्नों का तकनीकी ज्ञान व समाधान नहीं होता है. इस अज्ञानता के कारण राजनीतिक निर्णय लेते समय सैन्य बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता. इन्हीं वजहों से सीमायुद्ध हुआ और इसमें भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा. चीन की युद्ध तैयारी उच्च स्तर की थी. उन्होंने अपने लिए सड़कों का जाल फैलाया. सैनिकों को बेहतर हथियार और सुविधाएं उपलब्ध करायी. लड़ाई के दौरान चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा थी. इसके उलट भारतीय वेस्टर्न कमांड की स्थिति क्या थी? उस समय जनरल दौलत सिंह ने फारवर्ड पॉलिसी के विषय में इशारा किया था. उन्होंने सैनिकों की समस्याओं की सूची दी थी. वेस्टर्न सेक्टर में सैन्य चौकियों की कम क्षमता है. लिहाजा इस समय चीन के साथ संघर्ष टालना चाहिए था.

सातवीं ब्रिगेड का सफाया

20 अक्टूबर को चीन ने तोपों से गोलाबारी शुरू की. इस सीमायुद्ध में महीने भर बाद चीन ने एक तरफा सशर्त युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी. ब्रिगेडियर दलवी नेफात सातवीं ब्रिगेड के कमांडर थे. जनरल प्रसाद (4 थी डिविजन कमांडर) चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम शीघ्र अपने हाथ में लें, ऐसा आदेश जनरल सेन ने दिया था. दलवी और प्रसाद इन दोनों को चीनी सेना को खदेड़ने का आदेश दिया जाना मूर्खतापूर्ण था. गौरतलब है कि लड़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों को युद्धक साजो-सामान की आपूर्ति नहीं की गई. इसके बावजूद चीनी सेना को खदेड़ने का काम छह महीनों के बाद हाथ में लेना पड़ा. ऐसा जनरल दलवी ने स्पष्ट किया था. जनरल थापर (सेना प्रमुख) ने जनरल उमराव सिंह का तबादला कर दिया. इसके बाद जनरल कौल को सेना की नई टुकड़ी देकर भेजने का निर्णय लिया गया. आगे जनरल कौल के सामने उमराव सिंह ने अपनी योजना रखी. जनरल कौल ने उनकी योजना को नकार दिया. लड़ते रहो पर पीछे मत हटना यदि अभी कार्रवाई करने में ढिलाई हुई तो अधिकारियों का कोर्ट मार्शल हो सकता है. उसके बाद चीन के भयानक हमले में सातवीं बिग्रेड का सफाया हो गया. वह बिखर गई और बिग्रेडियर दलवी रास्ते में पकड़े गये.

परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह और चुशूल का युद्ध

चीनी सेना अनुभवी थी और उसके हथियार अत्याधुनिक थे. वहीं हमारी सेना दूसरे महायुद्ध के हथियार और तोपों का इस्तेमाल कर रही थी. वायरलेस सेट उसी समय का था. ब्रिटिश काल के कपड़ों और अन्य सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल होता था. 17 नवंबर को चुशूल की पहाड़ी के आसपास चीनी सेना ने अपनी तोपों का मुंह खोला. उसके बाद चीनी थलसेना ने आमने-सामने चढ़ाई कर दी. हमारे जवानों ने उनको खदेड़ दिया. चुशूल वायुसैनिक अड्डा के निकट रेझांग पहाड़ पर चीनी सेना ने प्रचंड हमला किया. उस समय वहां पर कुमांऊ बटालियन की एक कंपनी तैनात थी. मेजर शैतान सिंह ने चीनी सैनिकों का अपने लहू के आखिरी बूंद तक सामना किया. युद्धोपरांत शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया. लड़ाई के समय बर्फबारी का मौसम था. तीन माह बाद भारतीय अधिकारी पहाड़ों पर गये तब वहां तैनात सभी जवान मोर्चे पर हाथ में हथियार लिए मरणावस्था में थे. उनकी वीरता व शौर्य का स्मारक आज भी चुशूल में मौजूद है. अक्टूबर 1962 में लद्दाख के क्षेत्र में चीन ने हमला किया. संसाधनों की कमियों के बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने युद्ध कौशल दिखाया. चीना सेना का इस युद्ध में बहुत नुकसान हुआ. इस तथ्य का जिक्र कई चीनी सैन्य अधिकारियों ने अपनी लिखी किताबों में किया है. उन्होंने लिखा है कि युद्ध में चीनी सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और भारतीय सेना ने तवांग क्षेत्र स्थित जसवंतगढ़ व वालॉग क्षेत्र में बड़ी कुशलता से युद्ध किया. वालॉग क्षेत्र में कप्तान विष्णु आटले शहीद हो गए. चीनी अधिकारियों ने भारतीय सेना के पराक्रम व युद्धकौशल का बखान किया था. चीन ने जब युद्ध विराम की घोषणा की तब चीनी सेना तवांग क्षेत्र में बामदीला तक पहुंच चुकी थी. वालॉग व लद्दाख क्षेत्र के चुशूल तक चीनी सैनिक पहुंच गये थे.

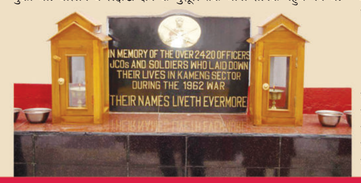

एक तरफा युद्धबंदी की घोषणा करके चीन ने भारत पर अहसान कराने का आभास कराया. नवंबर-दिसंबर से मार्च तक पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका था. बर्फबारी होने के बाद वाहनों की आवाजाही पूरे क्षेत्र में बंद थी. 1962 के समय में आवाजाही के अधिक साधन नहीं थे. चीनी क्षेत्र से नेफा क्षेत्र की ओर आनेवाली गाड़ियों के लिए सड़क भी नहीं था.

तत्कालीन भारत सरकार की लापरवाही के चलते 1962 का युद्ध चीन ने हमारे ऊपर थोप दिया और अपना मकसद पूरा होते ही एकतरफा युद्ध विराम का ऐलान कर दिया. इस बात को भारत सरकार ने चुपचाप मान लिया. 1962 में हमारी सेना को आजाद होकर लड़ने की आज़ादी नहीं मिली. 1962 के युद्ध के बाद रक्षा मंत्री को बदल दिया गया. यशवंत राव चव्हाण के रक्षा मंत्री बनने के बाद हमारी सेना का आधुनिकी करण होना शुरू हुआ. इस आधुनिकी करण के फायदे हमें 1965, 1971 के युद्ध में मिला. चीन से युद्ध में मिली असफलता हमारी सेना की नहीं, बल्कि हमारे नेता की है.

इतिहास की पुनरावृत्ति

भारत के इतिहास में 26 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों.....गाना गाया था. इस गीत से सारा देश भावुक हो उठा था. इस गाने की भूमिका अलग थी. भारत-चीन युद्ध के बाद यह पहला गणतंत्र दिवस था. चीन के साथ जंग में हुई मानहानि, हताशा और शर्मिंदगी की मिलीजुली भावना इस गाने को सुनते समय देश वासियों के मन में उमड़ उठी थी. भारत-चीन युद्ध को इस वर्ष 20 अक्टूबर को 49 साल पूरे हो गए. इन बीते समय में हमने क्या कोई सबक लिया. इस पर मंथन करने की जरूरत है. एक कहावत है- इतिहास खुद को दोहराता है. चीन को लेकर भारत की चिंताएं कभी खत्म नहीं हुई हैं. चीन की ओर से अभी भी घुसपैठ जारी है. 1962 में क्या हुआ था, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए. हिन्दी-चीनी भाई-भाई जैसा वातावरण फिर बन रहा है. दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ रहा है. भविष्य में दोनों देशों के मध्य व्यापार 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है. इसके बावजूद पाक अधिकृत कश्मीर में आज चीनी सैनिकों ने घुसपैठ कर दी है. लिहाजा हमें चीन के साथ संबंधों पर गंभीरता से विचार-विमर्श करना होगा.

भारत-चीन जंग एक दुःस्वप्न

30 सितंबर 2011 को चीनी सैनिकों ने भारतीय हवाई सीमा व जमीनी सीमा का उल्लंघन करते हुए घुसपैठ की थी. उन्होंने इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस दल के चुने हुए बेकार बंकर-तंबू में तोड़फोड़ की थी. चीन की भारत संबंधी नीति हमेशा से संदिग्ध रही है. कश्मीर का सवाल हो, ब्रम्हपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना और हिंद महासागर में चीनी नौसेना का घुसना ये सभी चीन की नीति समझने के लिए काफी है.

feedback@chauthiduniya.com

किसानों की संपत्ति जब्त करने का आदेश

हमारी सरकारें किसानों के हितों का कितना ख्याल रखती हैं. यह उनकी नीतियों से ही पता चलता है. राज्य व केंद्र में बैठे नेता हमेशा यह दिखावा करते हैं कि उनको किसानों के हितों की बहुत चिंता है, लेकिन यह सत्य नहीं है. शासन-प्रशासन पर बैठे लोग निरंतर कृषि व कृषकों को आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं. इन आघातों को बर्दाश्त करने की क्षमता कम से कम विदर्भ के किसानों की नहीं है. वैसे भी विदर्भ का किसान आर्थिक बदहाली से बेजार है. यहां किसानों के खुदकुशी करने की घटनाएं लगातार घटित हो रही है. बावजूद इसके अब केंद्र और राज्य सरकार ने एक अध्यादेश निकालकर कहा है कि, जो किसान कर्ज माफी योजना के तहत अपात्र रहे हैं और उन पर बैंक का कर्ज बकाया है. उन सभी किसानों की जमीन व चल संपत्ति की नीलामी कर बैंक बकाया वसूल कर सकते हैं. इस अध्यादेश के जारी होने से विदर्भ और कोंकण के सात हजार से अधिक किसानों पर बिजली गिरने की आशंका है. इस अध्यादेश को जारी करने से यह बात साफ हो गई है कि केंद्र और राज्य सरकार की नीति किसानों के लिए नहीं, बल्कि बैंक और पूंजीपतियों के लिए फ़ायदेमंद है. अध्यादेश के अनुसार बकाया वसूली की कार्रवाई शिखर बैंक के निर्देशों पर भू-विकास बैंक करेगा. इस अध्यादेश की कॉपी व आदेश सभी संबधित बैंकों को भेज दिया गया है, लेकिन इस अध्यादेश में राजनीतिक पक्षपात साफ झलकता है. इसकी वजह यह है कि विदर्भ और कोंकण से अधिक कर्ज पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों पर बकाया है. इसके बावजूद अध्यादेश में पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों को अभयदान दिया गया है. इससे केंद्र और राज्य सरकार की दोहरी कृषि नीति का खुलासा फिर एक बार हुआ है. महाराष्ट्र में विदर्भ की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. दिन-ब-दिन किसान द्धारा आत्महत्याएं करने की घटनाएं बढ़ रही हैं. किसान आत्महत्या का आंकड़ा चालू वर्ष 2011 में 624 हो गया है. यवतमाल जिले में यह आंकड़ा 120 है. एक तरह से केंद्र और राज्य सरकार की यह नीति किसानों से जबरन वसूली करने की है. इस तरह की नीति से विदर्भ में किसान आत्महत्या के आंकडों में कमी आने की बजाय बढ़ोतरी ही होगी. कोंकण के किसानों की स्थिति विदर्भ के किसान से अलग है. कोंकण में कम बरसात होने के कारण फसल सूखने की कगार पर है. ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि अगर फसल पैदा नहीं होगी तो किसान कर्ज अदायगी कैसे करेंगे. बढ़ती महंगाई के बोझ से किसान पहले ही खासे परेशान हैं. बीजों-खादों के दाम में बढ़ोत्तरी से वैसे भी किसानी करना काफी महंगा हो गया है और ऊपर से पुराने कर्ज का भारी बोझ. इन हालात में किसान समय पर बैंक का कर्ज नहीं चुका पा रहा है. मूल रकम के साथ ही ब्याज की रकम भी बढ़ती जा रही है. इस स्थिति में कर्ज की रकम कैसे चुकाई जाए? यह सवाल किसानों के समक्ष खड़ा है. इस पर सरकार ने अध्यादेश जारी कर उन किसानों के घर से टी.वी, साइकिल, मोटर साइकिल व अन्य कीमती सामान जब्त कर वसूली करने का फरमान जारी किया है जिन पर एक लाख या उससे अधिक का कर्ज बकाया है. घरेलू सामान की नीलामी से कर्ज की वसूली न हो पाने पर उनके खेत व मकान नीलाम करने को कहा गया है.

इस अध्यादेश के तहत विदर्भ और कोंकण के करीब सात हजार किसानों के नाम भू-विकास बैंक की सूची में दर्ज हैं, जिनसे कुल 58 करोड़ 28 लाख 18 हजार की रकम वसूल की जानी है. विदर्भ के 5 हजार 347 किसानों से कुल 30 करोड़ 67 लाख रुपये की राशि वसूली जाएगी. इनमें यवतमाल जिला प्रथम स्थान पर है. यवतमाल में 1 हजार 109 किसानों से 4 करोड़ 57 लाख रुपये वसूल किए जाएंगे. इसको लेकर यहां के लोगों को आशंका है कि यदि जबरन वसूली की गई तो यहां आत्महत्या की घटनाएं और बढ़ सकती हैं. भंडारा जिले के 289 किसानों से कुल 3 करोड़ 90 लाख, नागपुर जिले के 2 हजार 123 किसानों से 13 करोड़ 23 लाख रुपये, चंद्रपुर जिले से 268 किसानों से करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपये, वर्धा जिले में 444 किसानों से 1 करोड़ 61 लाख, अमरावती जिले से 255 किसानों से 1 करोड़ 69 लाख, बुलढाना जिले से 255 किसानों से 1 करोड़ 5 लाख और अकोला जिले के 386 किसानों से 2 करोड़ 58 लाख की राशि की वसूल की जानी है. विशेष बात यह है कि यह वसूली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में करने का निर्देश दिया गया है, जबकि यह महीना त्योहारों का है. इस तरह विदर्भ और कोंकण के किसानों के साथ सरकार अन्याय कर रही है. विदर्भ और कोंकण से दोगुना से भी ज्यादा कर्ज पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों पर बकाया होने के बावजूद भी उनको सरकार किस नियम के तहत अभयदान दे रखा है? उन्हें सरकार खुले दिल से मदद क्यों कर रही है? यह सरकार की नीति में खोट होने को दर्शाता है. एक ही राज्य के क्षेत्र विशेष को मदद और दूसरे क्षेत्र के किसानों से जबरन वसूली यह कहां का न्याय है? सरकार की इस नीति से विदर्भ के किसानों में गहरी निराशा छाई हुई है. जानकारों का कहना है कि यह वसूली अभियान इसलिए शुरू किया गया क्योंकि बैंक के पास अपने अधिकारियों-कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के लिए धन नहीं है. चूंकि केंद्र और राज्य सरकार ने नाबार्ड प्रबंधन को साफ कह दिया कि यदि अधिकारियों-कर्मचारियों को वेतन चाहिए तो किसान पर बकाया कर्ज वसूल करना होगा. भले यह वसूली जबरन करनी पड़े. इसलिए उक्त अध्यादेश के तहत किसानों के पास जो भी चल-अचल संपत्ति है उसको नीलाम कर कर्ज व उसके ब्याज की रकम वसूल करने का अभियान कभी भी शुरू हो सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विदर्भ के किसानों पर कर्ज की बकाया राशि

जिला	किसान	बकाया
यवतमाल	1 हजार 109	4 करोड़ 75 लाख
भंडारा	289	3 करोड़ 90 लाख
नागपुर	2 हजार 123	13 करोड़ 23 लाख
चंद्रपुर	268	1 करोड़ 15 लाख
वर्धा	444	1 करोड़ 61 लाख
अमरावती	255	1 करोड़ 69लाख
बुलढाना	255	1 करोड़ 5 लाख
अकोला	386	2 करोड़ 58 लाख
कुल 5 हजार 347 (किसान)		30 करोड़ 67 लाख

कोंकण विभाग की स्थिति

रायगढ़	52	26लाख
ठाणे	391	1 करोड़.30 लाख
सिंधु दुर्ग	299	92 लाख 18 हजार
रत्नागिरी	904	2 करोड़ 92 लाख
कुल	1 हजार 646	4 करोड़ 51लाख

ये क्या हो रहा है...

बाबा-आबा अंकुश को ले जाओ

नागपुर महाराष्ट्र की आपराधिक शहर में शुमार होता जा रहा है. यहां कानून-व्यवस्था की स्थिति से न जनता खुश है और न ही जनप्रतिनिधि. पुलिस महकमे के आला अधिकारी कहां खोये हैं, पता नहीं. शहर में अपराध बढ़ रहे हैं. इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि नागपुर अपराधियों के लिए स्वर्गलोक सदृश्य हो गया है. आखिर माजरा क्या है कि पुलिस के रहते अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है. कहीं यह आपसी मिली भगत के दुष्परिणाम का नतीजा तो नहीं है. हालत यह है कि शहर में बाल-बच्चे तक सुरक्षित नहीं हैं. यहां हर सप्ताह एकाध हत्या होना आम बात हो गई. मात्र वर्ष 2011 में जनवरी से सितंबर तक यानी 9 माह में ही 89 हत्या, 50 हत्या के प्रयास, 440 चोरी-डकैती और 700 वाहन चोरी के मामले सामने आए हैं. बच्चों का अपहरण कर हत्या करने के मामले से पूरे नागपुर जिले के लोग आशंकित हैं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर. न जाने यहां कौन कब कुश की तरह उनके बच्चे का अपहरण कर हत्या न कर दे. लोगों में असुरक्षा की ऐसी भावना के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है. इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि पुलिस की लापरवाही के चलते ही अपराधियों का हौसला सातवें आसमान पर है. यह कहना गलत नही होगा कि पुलिस आयुक्त अंकुश धनविजय का अपने महकमे के अधिकारियों व पुलिस जवानों पर जरा भी अंकुश नहीं रह गया है. लिहाजा शहर में कानून-व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है. यह शहर की जनता कह रही हैं. नागपुर में कानून व सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि जिले में पुलिस का अस्तित्व है भी या नहीं यह सवाल मुंह बाए खड़ी है. वर्तमान में घटित हो रही घटनाएं भयावह और बुरी हैं. पुलिस को इस बिगड़ते हालात पर तत्काल अंकुश लगाना चाहिए. पुलिस से छूटे हिस्ट्रीशीटर राजनीति में शिरकत कर रहे हैं. राजनेता, अपराधी और पुलिस के अभ्रद युति के कारण शहर में अपराध बढ़ रहे हैं. सुन रहे हैं राज्य के आबा-बाबा (गृहमंत्री व मुख्यमंत्री). आपकी सरकार के नाक तले ये क्या चल रहा है? नागपुर शहर अब उप राजधानी नहीं रहा. दरअसल यह अपराधों की राजधानी बनता जा रहा है. आपके पुलिस आयुक्त अंकुश धनविजय साहब अपराधियों-अपराधों पर विजय पाने पर नाकाम साबित हुए हैं. अपराधी बेफिक्र होकर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं. यहां अवैध कारोबार का धंधा जोर पकड़ता जा रहा है. जब अंकुश साहब यहां अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं तो उनकी यहां क्या जरूरत है? यहां से ले जाइए उनको, जहां आपकी मर्जी हो. विशेष कर गृहमंत्री आर. आर. पाटिल साहब आप कहां खोए हुए हैं. आपको कुछ पता भी है कि राज्य की उप राजधानी में हो क्या रहा है. जरा गौर फरमाइए कि यहां अपराधी और अपराधों का किस गति से विकास हो रहा है. आबा साहिब राज्य में आपके चरित्र की दुहाई दी जाती है. पूरे राज्य में आपकी सोच, आपकी इच्छा और आपके लोगों का राज है. नागपुर में किसी योग्य अधिकारी को पुलिस का मुखिया बनाकर भेजिए, जो इस शहर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगा सके. अंकुश धनविजय साहब को आप अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए यहां से ले जाइए. स्थिति और अधिक बिगड़ने के पहले अपने सद्चरित्र के साथ ही एक्शन में आइए. बालक कुश की अपहरण के बाद हत्या किए जाने से नागपुरकर बहुत ही विचलित हैं. कहीं ऐसा न हो कि लोग कानून को अपने हाथों में लेने को मजबूर हो जाएं और पुनः कोई अक्कू यादव जैसा कांड नागपुरकरों के हाथों घटित हो जाए. इसलिए जागिये. पानी अभी सिर के नीचे है. यदि यह सिर के ऊपर चला गया तो हालात क्या होंगे? जरा सोचिए और कुछ कीजये!

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

महाराष्ट्र विधान मंडल अमृतमहोत्सव के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल वरिष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख का सत्कार करते हुए. साथ में हैं विधानसभाध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और कृषिमंत्री शरद पवार.

कुश कटारिया के अपहरण और हत्या के विरोध में धरना-प्रदर्शन करते नागपुर वासी.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के नांदेड आगमन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण अपने निवास पर उनका स्वागत करते हुए. इस मौके पर पालकमंत्री डी.पी. सावंत, प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे और सांसद भास्कर राव पाटिल खतगावंकर भी मौजूद रहे.

रत्नागिरी जिला कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यकर्ता शिविर का उद्घाटन करने के बाद उद्योग मंत्री नारायण राणे का स्वागत करते कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रमेश कीर, सांसद डॉ. नीलेश राणे और पूर्व विधायक गणपत कदम.

नागपुर में हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन करते हुए खाद्य एवं नागरी आपूर्ति मंत्री अनिल देशमुख. उनके साथ हैं धनंजय दलाल, महाराष्ट्र राज्य हथकरघा उद्योग के अध्यक्ष सज्जाद हुसैन, उप संचालक व अन्य अतिथिगण.

नागपुर में हैंडलूम एक्सपो के उद्घाटन समारोह में मनमोहक नृत्य पेश करतीं अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 07 नवंबर–13 नवंबर 2011

अमरावती ज़िला परिषद की तस्वीर भी कुछ नागपुर से ही मिलती-जुलती है. यहां भी 59 सर्कलों में से 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाने से अनेक जाने-माने राजनीतिक खिलाड़ियों को झटका लगा है.

जिप चुनाव में आरक्षण

सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ीं

नितिन राठी, उपाध्यक्ष, नागपुर जि.प.

बबलू देशमुख, अध्यक्ष, अमरावती जि.प.

मालती चौधरी, महिला व बाल कल्याण सभापति, अमरावती जि.प.

गणेश आरेकर, सभापति, वित्त समिति, अमरावती जि.प.

रमेश मानकर, उपाध्यक्ष, यवतमाल जि.प.

सुरेश भोयर, अध्यक्ष, नागपुर जि.प.

बालासाहब वानखेड़े, सभापति, शिक्षा समिति, अमरावती जि.प.

संतोष महात्मे, उपाध्यक्ष, अमरावती जि.प.

महाराष्ट्र में महानगर पालिका के बाद अब ज़िला परिषद चुनाव के लिए भी पिछले महीने 13 अक्टूबर को आरक्षण की घोषणा कर दी गई. आरक्षण की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दलों के अधिकांश दिग्गजों के पैरों तले से ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है. स्थानीय निकाय चुनाव में भी 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा राज्य सरकार ने पहले ही कर दी थी. उसके बाद अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा ने राजनीतिक दलों के सामने विकट स्थिति पैदा कर दी है. उनके सामने अपना राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है. विदर्भ की नागपुर समेत अमरावती, यवतमाल, बुलढाना, चंद्रपुर, वर्धा और गढ़चिरोली ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की घोषणा लॉटरी निकाल कर किया गया. विदर्भ की सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली नागपुर ज़िला परिषद में आरक्षण की घोषणा होते ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दो सभापतियों सहित कई दिग्गजों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं साफ देखी जा सकती हैं. नई आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद अब राज्य की ज़िला परिषदों में महिलाओं को वर्चस्व हो गया है. नागपुर ज़िला परिषद की बात करें तो अब यहां 59 सदस्यों में से 30 जिप सदस्य महिलाएं होंगी. आरक्षण के परिणाम स्वरूप जो तस्वीर नागपुर ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की उभर कर सामने आयी है, उसके अनुसार 59 सीटों (सर्कल) में से 10 अनुसूचित जाति, 8 अनुसूचित जनजाति और 16 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 25 सीटों को अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए रखी गईं हैं. इस आरक्षण से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांगेस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना सहित सभी दल प्रभावित हुए हैं. इसके साथ ही उन्हें अब नये सिरे से उम्मीदवारों की तलाश करना और चुनावी रणनीति बनाने की चिंता सताने लगी है. खास बात यह है कि वर्तमान घोषित आरक्षण की मार सत्तारूढ़ कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन पर सबसे अधिक पड़ी है. कांग्रेस के वर्तमान 12 सदस्यों को ज़िला परिषद चुनाव लड़ने से विमुख होना पड़ेगा, जबकि 5 सदस्य आरक्षण की मार से बच गए हैं. इनमें वर्तमान ज़िला परिषद अध्यक्ष सुरेश भोयर भी शामिल हैं. वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के 4 सदस्यों को घर बैठना पड़ सकता है. वहीं भाजपा के 20 सदस्यों में 10 को आरक्षण ने क्लीन बोल्ड कर चुनावी जंग से बाहर कर दिया है. बाकी दस सदस्य अपनी जमी जमाई सीट बचाने की कोशिशों में जुट गए हैं. शिवसेना के चार सदस्यों में से महज एक की जगह सुरक्षित बची है. बाकी तीन को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा. आरक्षण से जिन नेताओं को अपनी जगह छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है उसमें ज़िला परिषद अध्यक्ष सुरेश भोयर, उपाध्यक्ष नितिन राठी, पूर्व अध्यक्ष रमेश मानकर, पूर्व उपाध्यक्ष बंडू उमरकर, भाजपा के गट नेता आनंदराव राऊत, पूर्व सत्तारूढ़ दल के नेता बाबा आष्टनकर, पूर्व सभापति सुरेश कुमरे, कुंदा राऊत, दीप्ति कालमेघ आदि प्रमुख हैं. हालांकि उपाध्यक्ष नितिन राठी ने पहले ही चुनाव न लड़ने की घोषणा ज़िला परिषद की बैठक में कर दी थी.

अमरावती ज़िला परिषद की तस्वीर भी नागपुर से ही मिलती-जुलती है. यहां भी 59 सर्कलों में से 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाने से अनेक राजनीतिक खिलाड़ियों को झटका लगा है. इनमें ज़िला परिषद के अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष संतोष महात्मे, शिक्षा समिति सभापति बालासाहब वानखेड़े, महिला व बाल कल्याण सभापति मालती चौधरी, वित्त समिति के सभापति गणेश आरेकर उन सदस्यों में शामिल है जिनके सामने अपना राजनीतिक प्रभुत्व बचाने का संकट खड़ा है. अमरावती ज़िला परिषद में हुए आरक्षण की खास बात यह है कि सभी वर्तमान जि.प. पदाधिकारियों का सर्कल आरक्षित हो जाने से उन्हें चुनावी मैदान में उतरने के लिए नए निर्वाचन क्षेत्र की तलाश करनी पड़ रही है. यहां अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति वर्ग 6, अन्य पिछड़ा वर्ग 8 सर्कल आरक्षित किए गए हैं और 10 सीटें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं. इसके साथ ही ज़िले की 11 पंचायत समिति के लिए भी आरक्षण की घोषणा की गई है. इसी तरह चंद्रपुर ज़िला परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति सहित 38 निवर्तमान सदस्यों को अपनी सीट से बेघर होने की चिंता सताने लगी है. इस हालात में उन्हें अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए अब नये सर्कल की खोज करनी पड़ रही है. इस ज़िला परिषद में कुल 57 सदस्य हैं जिनमें 19 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र नई आरक्षण व्यवस्था के बाद भी सुरक्षित हैं. इनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं. यदि महिला आरक्षण और जातिवार आरक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो आगामी ज़िला परिषद चुनाव में 29 महिला सदस्यों का चुना जाना तय है. ज़िले की 15 पंचायत समितियों में कुल 114 सदस्य हैं जिनमें से 50 प्रतिशत यानी 57 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है. गढ़चिरोली ज़िला आदिवासी बाहुल्य होने के कारण यहां की ज़िला परिषद की अधिकांश सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. 51 निर्वाचन क्षेत्रों का वर्ग आधारित आरक्षण होने से यहां भी कई दिग्गजों को निराश होना पड़ा है. लिहाजा उन्हें अब नये क्षेत्रों की तलाश करनी पड़ रही है. इनमें ज़िला परिषद के निर्माण कार्य समिति के सभापति रमाकांत ठेंगरी, अध्यक्ष रवि ओल्लालवार, राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष अतुल गण्यार पवार, रामरेड्डी बंडावार, शिवसेना के दिगंबर मेश्राम, आनंदराव आखरे, ज्योति सालवे, विश्वास भोवते, जगन्नाथ बोरकुटे प्रमुख हैं, जिन्हें आरक्षण के चलते अपना सियासी वजूद बचाने की चिंता होने लगी है. यवतमाल में ज़िले में भी आरक्षण लागू होने से कई नेताओं की जमीन खिसकने लगी है. आरक्षण से प्रभावित होने वालों में ज़िला परिषद अध्यक्ष राहुल ठाकरे, उपाध्यक्ष रमेश मानकर, शिक्षा समिति सभापति अरुण राऊत, निर्माण कार्य समिति सभापति तातू देशमुख, समाज कल्याण समिति

राहुल ठाकरे, अध्यक्ष, यवतमाल जि.प.

रमेश मानकर, उपाध्यक्ष, यवतमाल जि.प.

ज्योति चव्हाण, सभापति, महिला बाल कल्याण समिति, यवतमाल जि.प.

प्रकाश कासावार, सभापति, समाज कल्याण समिति, यवतमाल जि.प.

अरुण राऊत,सभापति,शिक्षा समिति,यवतमाल जि.प.

तातू देशमुख, सभापति निर्माण कार्य समिति, यवतमाल जि.प.

सभापति प्रकाश कासावार, महिला बाल कल्याण समिति सभापति ज्योति चव्हाण, राकांपा के जिलाध्यक्ष प्रवीण देशमुख, ज़िला बैंक के उपाध्यक्ष बाला साहब गाड़े पाटिल, कांग्रेस नेता सुरेश लोनकर विशेष रूप से शामिल हैं. इन सभी को अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए वैकल्पिक निर्वाचन क्षेत्र की तलाश है. इसी प्रकार बुलढाना ज़िले के 59 सर्कलों और पंचायत समिति की 118 सीटों के लिए आरक्षण की घोषणा की गई है. जिला परिषद की 59 सीटों के लिए घोषित आरक्षण से ज़िला परिषद अध्यक्ष प्रा. नरेन्द्र खेडेकर, उपाध्यक्ष राम जाधव, कृषि समिति सभापति सोपानराव साठे, सभापति अभय चव्हाण, वैशाली ताई सुपेकर समेत कई नेताओं को करारा झटका लगा है. वर्धा ज़िला परिषद में कुल 51 सीटों में से 26 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. यहां भी अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण घोषित किए जाने से नेताओं में गहरी निराशा छाई हुई है.

अगर देखा जाए तो ज़िला परिषद के लिए घोषित आरक्षण से सभी दलों के दिग्गजों का पसीना छूटने लगा है. वहीं इससे उन लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, जिन्हें आरक्षण व्यवस्था के तहत राजनीतिक क्षेत्र में भाग्य आजमाने का अवसर मिलेगा. खासकर महिलाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा. इसीलिए आगामी चुनाव के बाद ज़िला परिषद में महिलाओं की संख्या बढ़ने के साथ ही उनका वर्चस्व भी कायम होगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता आने के साथ ही व्यापक बदलाव आना तय माना जा रहा है.

अदालत की शरण में जाने की तैयारी

नागपुर ज़िला परिषद के 59 सर्कलों के लिए घोषित आरक्षण से कई वर्तमान सदस्य काफी असंतुष्ट हैं. इसे लेकर उनमें नाराजगी व्याप्त है. नाराज़ सदस्यों ने आरक्षण के नियमानुसार न होने का हवाला देते हुए अदालत की शरण में जाकर न्याय पाने की बात कही है. जिन सर्कलों से पहले महिलाएं निर्वाचित हुई थीं वही सर्कल पुन: महिलाओं के लिए आरक्षित घोषित किया गया है. असंतुष्ट सदस्यों का तर्क है कि पहले 33 प्रतिशत महिला आरक्षण था. जिसे रद्द कर 50 फ़ीसदी आरक्षण का नियम लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इससे तुलनात्मक दृष्टि से आरक्षण करने में न्याय नहीं किया जा सका है. इसके अलावा नियमानुसार एक सर्कल में 30 से 35 हज़ार मतदाता होना चाहिए. यहां कई सर्कलों में 45 हज़ार से भी अधिक मतदाता हैं. सर्कलों के निर्धारण के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार द्वारा 2001 की जनगणना को आधार बनाने के कारण ज़िला परिषद सर्कलों की संख्या नहीं बढ़ पायी है. इन तथ्यों को लेकर नई आरक्षण व्यवस्था से असंतुष्ट सदस्य अब उच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं.

छह तहसीलों में होगा महिलाराज

ज़िला परिषद के लिए घोषित आरक्षण के पश्चात नागपुर ज़िले की 6 तहसीलों में महिलाओं का राज होना तय है. यह संभव हुआ है स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फ़ीसदी आरक्षण लागू किए जाने से. काटोल तहसील के चार सर्कलों में से तीन महिलाओं के पास ही रहेंगे. रामटेक तहसील के पांच सर्कलों में से चार का नेतृत्व महिला सदस्य करेंगी. इसी तरह कामठी तहसील के 4 सर्कलों में 3 सर्कल पर महिला सदस्य होंगी. उसी तरह कलमेश्वर और भिवापुर तहसील के तीन सर्कलों में से दो पर महिला सदस्यों का चुना जाना तय है. नरखेड़ तहसील व हिंगणा में 50-50 प्रतिशत का मामला है. नरखेड़ तहसील के चार सर्कलों में दो महिला, नागपुर ग्रामीण तहसील के सात सर्कलों में से चार महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं. इसी तरह हिंगणा के छह सर्कलों में से तीन का प्रतिनिधित्व महिलाएं करेंगी. पुरुषों के वर्चस्व वाली तहसीलों में पारशिवनी, कुही और मौदा हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No.RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

जी हां जैसे की सबको पता है कि विद्या बालन सन्नी देओल के साथ उनके सीक्वल में काम कर रही थीं लेकिन अब घायल रिर्टन्स में अंतिम क्षणों में इंकार कर दिया है.

प्रियंका की नई रेस

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने रेस 2 में काम करने से मना कर दिया है. वह इस समय अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी के लिए काम कर रही है. लेकिन अब ख़बर आई है कि इस फिल्म में काम करने के लिए प्रियंका चोपड़ा से बात की है. अब्बास-मस्तान चाहते थे कि दीपिका की जगह वे किसी नामी हीरोइन को लें और प्रियंका इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. हालांकि प्रियंका के लिए इतनी जल्दी डेट्स एडजस्ट करना मुश्किल है. प्रियंका ने न नहीं की है, लेकिन अगर उनके डेट्स की प्रॉबलम सॉल्व हो जाती है तो वह फिल्म में ज़रूर काम करेंगी. जब अचानक ही फिल्म की हीरोइन काम करने से मना कर दें तो शूटिंग शेड्यूल ख़राब हो ही जाता है. दीपिका के मना करने से फिल्म का काम बढ़ ही चुका है. प्रियंका और अब्बास-मस्तान पहले फिल्म ऐतराज में साथ काम कर चुके हैं. इस फिल्म में प्रियंका नेगेटिव शेड में नज़र आई थी और उनके काम को लोगों ने काफी पसंद भी किया था. देखते हैं अब वह कौन से शेड में नज़र आएंगी.

एमा की ख़्वाहिश

हॉलीवुड ऐक्ट्रेस एमा वाटसन चाहती हैं कि शेक्सपीयर के नाटक रोमियो ऐंड जूलियट पर आधारित फिल्म बने और वह इसमें जूलियट की भूमिका निभाएं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह इच्छा जताई कि वह ट्रेजडी से भरपूर जूलियट जैसा किरदार निभाना चाहती हैं. शेक्सपीयर के ही दूसरे नाटक हेमलेट पर आधारित फिल्म में भी वे ओफीलिया का रोल करना चाहती हैं. मशहूर फिल्म हैरी पॉटर की नायिका एमा बज लुरमैन, गुलरमो डेल तोरो, रिचर्ड कर्टिस, डेरेन आदि निर्देशकों के साथ भविष्य में काम करना पसंद करेंगी. एमा उस समय मात्र नौ साल की थीं, जब उन्होंने हैरी पॉटर फिल्म में हरमियन का रोल किया था. वर्ष 2001-2011 तक हैरी पॉटर के आठों सीरीज में वे डेनियल रेडक्लिफ और रुपर्ट ग्रिंट के साथ काम कर चुकी हैं. इस सीरीज में काम करने की वजह से उन्हें ढेरों पुरस्कार भी अब तक मिल चुके हैं. उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत बरबेरी के कैंपेन से की थी. ग़ौरतलब है कि एमा वाटसन का जन्म पेरिस, फ्रांस में हुआ. उनके माता-पिता वकील थे. जब वे मात्र पांच वर्ष की थीं, तभी माता-पिता का तलाक हो गया. वे और उनके छोटे भाई दोनों मां के साथ इंग्लैंड चले आए. वह छह साल की उम्र से ही अभिनेत्री बनना चाहती थीं. इसलिए उन्होंने इंग्लैंड में स्टेजकोच थियेटर आर्टस से एक्टिंग और गाने-नाचने की ट्रेनिंग ली. उन्होंने बचपन में कई स्टेजकोच प्रोडक्शंस और स्कूल प्ले में एक्टिंग की. बैले शू नॉवेल पर आधारित टीवी शो और एक एनिमेशन फिल्म द टेल ऑफ डिस्पैरेक्स की. वह सह निर्माता भी रह चुकी हैं. उन्होंने ऑक्सफोर्ड शहर के अलग-अलग स्कूल में अपनी पढ़ाई की. जब वह हैरी पॉटर के सेट पर होती थीं, तो उनका ट्यूटर उन्हें दिन भर में पांच घंटे पढ़ाता था. फिल्मों में काम करने के बावजूद एमा पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहीं और उन्होंने इसी तरह पढ़ाई पूरी की. अब देखने वाली बात यह है कि एमा की हसरत, जो जूलियट का रोल करने की है, पूरी होती है या नहीं.

फिल्म प्रीव्यू

रॉक स्टार

बॉलीवुड को जब वी मेट जैसी बेहतरीन फिल्म दे चुके निर्देशक इम्तियाज़ अली अब अपनी अगली फिल्म रॉकस्टार के साथ तैयार हैं. बीते बरसों में बॉलीवुड ने अभिमान, सुर, रॉक ऑन जैसी संगीतप्रधान फिल्में दीं. अब जल्दी ही एक और संगीतप्रधान फिल्म रॉकस्टार आने वाली है, जो बॉलीवुड और संगीत के गहरे रिश्ते को और भी मज़बूत बनाएगी. इम्तियाज़ अली की रॉकस्टार का निर्माण इरोस इंटरनेशनल, श्री अष्टविनायक सिने विजन लिमिटेड ने मिलकर किया है. फिल्म में बॉलीवुड के चॉकलेटी ब्वॉय रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे. रणबीर एक छोटे शहर के लड़के की भूमिका में हैं जिसका सपना एक बड़ा रॉकस्टार बनने का है. इसमें वह विदेशी बाला नरगिस फाखरी के साथ इश्क फरमाएंगे. नरगिस एक अमेरिकी मॉडल और अभिनेत्री हैं. अभिनेता रणबीर कपूर फिल्म रॉकस्टार में 10 अलग-अलग अवतार में नज़र आएंगे. जिसमें रॉकस्टार और कव्वाल रूप भी शामिल है. कव्वाल के रोल में रणबीर को कव्वाली वाली टोपी, लंबे बाल, दाढ़ी और गिटार के साथ दिखेंगे. रॉकस्टार एक ऐसे सफल युवा संगीतकार की है जो प्यार में यक़ीन करता है लेकिन उसके प्यार में धोखा मिलता है. इस फिल्म में दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर ने भी अभिनय किया है. यह शम्मी कपूर की अंतिम फिल्म है. इस फिल्म के लिए गाने लिखे हैं ए आर रहमान ने और दो गानों को इटालियन, कनाडियन गायक नेटाली डी लुसियो ने तैयार किए हैं. फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग दिल्ली में हुई है. साथ ही फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग दिल्ली के सेंट स्टीफन और हिंदू कॉलेज में भी की गई है.

रिया के नखरे

बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाकाम करियर, इसके बावजूद नखरे. यह कहानी है बंगाली ब्यूटी रिया की. अभी हाल ही में निर्देशक इश्राक शाह की फिल्म एक बुरा आदमी के सेट्स पर तब गहमागहमी का माहौल बन गया जब अभिनेत्री रिया सेन ने अरुणोदय सिंह के साथ आइटम नंबर करने से मना कर दिया. यही नहीं उन्होंने तो शूटिंग कवरेज के लिए आमंत्रित मीडिया से भी बात करने से इंकार कर दिया. शाह ने कहा कि यह एक बुरा सपना था. रिया का कहना था कि यह सब कुछ प्रचार के लिए किया जा रहा है. उन्होंने बताया, रिया के साथ फिल्म में एक आइटम गीत के लिए अनुबंध हुआ था. हमने एक बहुत अच्छा गीत उछल गयी छमिया कुंवारों के बीच में रिकॉर्ड किया था. आरक्षण में नृत्य-निर्देशन करने वाले जयेश प्रधान इस गीत के लिए रिया को नृत्य-निर्देशित करने वाले थे. सब कुछ पहले से तय था. बाद में रिया ने कहा कि वह अस्वस्थ हैं और आइटम गीत के लिए रिहर्सल नहीं कर सकतीं. इसके बाद उन्होंने सिर्फ़ एक दृश्य दिया. मैं सहमत था क्योंकि अरुणोदय भी एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए अमेरिका निकल गए थे लेकिन बाद में रिया ने मीडिया से बात करने से भी मना कर दिया. शाह ने कहा, मैं एक नया निर्देशक हूं. मेरे लिए यह सब कुछ बहुत नया और शर्मिंदगीपूर्ण था. रिया के नखरे की वजह से मेरे निर्माता को कम से कम 70-80 लाख रुपये का नुक़सान हुआ. मुझे नहीं पता कि अब हम इस गीत की शूटिंग कैसे करेंगे. अब देखते हैं कि इस नखरे का ख़ामियाज़ा रिया को कितना उठाना पड़ सकता हैं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मिनीषा का टीवी अवतार

मिनीषा लांबा जल्द ही टीवी पर आने वाली हैं. इस शो को ग्लैमरस से भरपूर रखने के लिए वह डिज़ाइन पर विशेष ध्यान दे रही हैं. इसी सिलसिले में जब उनसे पूछा गया कि वह बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेस की तरह मिनीषा ने कान फिल्म फेस्टिवल में वेस्टर्न डिज़ाइनर की ड्रेस क्यों नहीं पहनी? इस सवाल पर मिनीषा बोलीं, कान फिल्म फेस्टिवल मूवीज सेलीब्रेट करने के लिए होता है, मगर आजकल किसने क्या पहना है, इस पर ज़्यादा ध्यान रहता है. मुझे लगता है कि इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल तय होना चाहिए. और फिर हमारे इंडियन डिज़ाइनर्स की क्रिएटिविटी को अगर हम इज़्ज़त नहीं देंगे तो कौन देगा? फैशन से हटकर फिल्मों पर चर्चा करते हुए मिनीषा ने अपनी चर्चित फिल्म ज़िला गाजियाबाद पर भी बात की. उन्होंने बताया कि यह एक पॉलिटिकल बैंक ड्रॉप की थ्रिलर है. अपने किरदार के बारे में उन्होंने कहा कि मैं पूरी फिल्म में घर की चहारदीवारी में कैद लहंगा चोली पहनने वाली लड़की का रोल कर रही हूं. मिनीषा के मुताबिक़ उन्हें इंडियन ड्रेस अच्छी लगती हैं क्योंकि इसमें वे चटपटा ख़ूबसूरत लुक देती हैं. कार्यक्रम के बारे में उनका कहना था कि वह अपने टॉक शो में गॉसिप नहीं दिखाएंगी.

विद्या का डर्टी स्टाइल

डर्टी पिक्चर अभी रिलीज भी नहीं हुई हैं कि उनका डर्टी व्यवहार सामने आने लगा है. सुनने में आया है कि उन्होंने सनी देओल के साथ कुछ ऐसा किया जो वह बर्दाश्त नहीं कर पाए. जी हां जैसे की सबको पता है कि विद्या बालन सन्नी देओल के साथ उनके सीक्वल में काम कर रही थीं लेकिन अब घायल रिर्टन्स में अंतिम क्षणों में इंकार कर दिया है. उनका कहना है कि जब तक उनकी फिल्म डर्टी पिक्चर्स प्रदर्शित नहीं हो जाती है, वे इस फिल्म की शूटिंग में भाग नहीं ले सकती हैं. यह बात तो विद्या पहले भी कह सकती थी लेकिन जब सब कुछ फिक्स हो गया है तब जाकर विद्या ने मना कर दिया. जिससे फिल्म यूनिट का पूरा कार्यक्रम डगमगा गया है. ख़ैर फिल्म को और ज़्यादा न रोकते हुए अब फिल्म निर्देशक अभिनेत्री बिपाशा बसु से बातचीत कर रहे हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो अब सन्नी देओल के साथ नायिका के तौर पर बिपाशा बसु नज़र आएंगी. देखना दिलचस्प होगा कि सन्नी और बिल्लो की इस जोड़ी को लोग क्या रिस्पांस देगें या नहीं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

तुम जियो हजारों साल

कलात्मक फिल्मों की नायाब नायिका नंदिता दास

यह मानना मुश्किल होगा कि इंटेलेक्चुअल सिनेमा में कामयाबी का एक सफर तय कर चुकी नंदिता दास का मन पढ़ने में नहीं लगता था. यह बात बचपन की नहीं बल्कि कॉलेज के दिनों की है. हालांकि वह पढ़ने में तो अच्छी थी लेकिन किताबों से दिल नहीं लगा पाई. आज जिस नंदिता को हम जानते हैं उसकी नींव भी कॉलेज के दिनों की ही है, मगर कोर्स की किताबों के बजाय शौक की वजह से. उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वह एक अभिनेत्री बनेंगी और न ही उन्हें अभिनय का शौक था, उन्हें केवल लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था. भूगोल से स्नातक करने के बाद उनकी इस विषय से रूचि हट गई, आगे पढ़ने के लिए मां-बाप ने मजबूर किया तो ऐसे विषय को पढ़ना चाहती जिसमें पढ़ाई न करनी पड़े. उन्होंने सोशल वर्क विषय लेकर एम.ए. पूरा किया. वह एनजीओ में काम कर रही थीं उसी वक़्त थिएटर भी करती थीं और फिल्मों में आना भी उसी दौरान हुआ. औरतों के लिए एनजीओ में काम करते हुए एक शॉर्ट फिल्म भी की वह फिल्म एक थी गुंजा. इस फिल्म के बारे में किसी ने लिखा और फिर दीपा मेहता से उनका ज़िक्र किया. बस यही ज़िक्र उनके करियर में फायर जैसी बोल्ड फिल्म आई. फायर के बाद वह 1947-अर्थ में आमिर ख़ान के साथ दिखीं. इस फिल्म में भी नंदिता का अभिनय उल्लेखनीय रहा. नंदिता ने ऑफबीट फिल्मों से मुख्य धारा की फिल्मों की ओर उन्होंने रुख़ किया और अक्स में अमिताभ बच्चन की नायिका के रूप में दिखीं. गंभीर भूमिकाओं में अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन करने के बाद सुपारी में महिला डॉन की भूमिका को भी बड़े प्रभावी अंदाज़ में उन्होंने जिया. बड़े पर्दे पर हर रंग की भूमिकाएं निभाने के बाद नंदिता ने निर्देशन में भी हाथा आजमाया. फिल्म फिराक के निर्देशक के तौर पर नंदिता दास ने गुजरात दंगों के अनछुए पहलुओं पर बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई. अब नंदिता मां भी बन चुकी हैं और साथ ही मानव तस्करी जैसे विषय पर एक और फिल्म बनाने का विचार कर रही हैं. स्मिता पाटिल के बाद हिंदी सिनेमा में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर नंदिता दास का ही नाम लिया जाता है. उम्मीद करते हैं इस बेहतरीन अदाकारा का और भी बेहतरीन काम हमें देखने को मिलता रहेगा. उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 07 नवंबर-13 नवंबर 2011

www.chauthiduniya.com

हाशिए पर भूमिहार समाज

भूमिहार नेता समाज के अपमान को भी याद नहीं रख रहे हैं. लालू प्रसाद ने बेगूसराय में भूरा बाल साफ़ करने का नारा दिया था. मंडल आंदोलन के दौरान नीतीश ने भी मोकामा में चुटकी भर बता कर मसलने की बात कही थी. गौर करने वाली बात है कि ये दोनों इलाक़े भूमिहार बहुल थे. इसके बावजूद इस समाज की तरफ़ से कोई आवाज़ नहीं उठी. आज दोराहे पर खड़े इस समाज को इंतज़ार है असली हीरो यानी सर्वमान्य नेता का.

सरोज सिंह

राजनीतिक दलों और राजनेताओं द्वारा राजनीतिक महापुरुषों की जयंती मनाने का पुराना प्रचलन रहा है. जयंती और पुण्यतिथि राजनीतिक तापमान को मापने का पुराना थर्मामीटर रहा है और ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा राजनीतिक वजन को तौले जाने का भी चलन रहा है. बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंति भी भूमिहार नेताओं के राजनीतिक वजन को तौले जाने का राजनीतिक तराजू रही है. इस वर्ष भी श्री बाबू के वंशजों में उनकी रजनीतिक थाती पर अधिकार जताने की ऐसी होड़ मची कि दो दिन उनकी जयंती मनाई गई. एक समारोह का आयोजन डॉ. अखिलेश सिंह ने किया तो दूसरे कार्यक्रम की बागडोर सत्ता की मलाई चाटने क लिए कांग्रेस से जदयू में गए विधान पार्षद डॉ. महाचंद्र सिंह ने संभाली. बिहार केसरी डॉ. श्री कृष्ण सिंह के जयंती समारोहों में उनके चित्र पर पुष्प चढ़ा कर उनके सिद्धांतों को अमल मे लाने की कसमें भले ही खाई गईं हो पर हक़ीक़त के आइने में दावे और वादे पूरी तरह धुंधले नजर आते हैं. हर साल बस श्री कृष्ण बाबू के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का नाटक किया जाता है पर भूमिहार समाज जिस तरह की समस्याओं से रूबरू है, उसकी चिंता किसी भूमिहार नेता को नहीं है. कहने को तो यह समाज विकास के पायदान पर काफी आगे माना जाता है पर ऐसा कुछ लोगों पर ही लागू होता है. समाज का बड़ा तबका आज भी रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रहा है. किसानी में हो रही दिक्कत ने इस तबके को और भी संकट में डाल दिया है. हक़ीक़त यह है कि इस समाज का एक छोटा वर्ग काफी आगे निकल गया है, जबकि बड़ा वर्ग जीने की लड़ाई लड़ रहा है.

अखिलेश सिंह काफी वर्षों से श्री बाबू की जयंती मनाते आए हैं. इनके द्वारा आयोजित पूर्व के जयंती समारोहों की खासियत यह होती थी कि अखिलेश सिंह भूमिहार समाज में लालू प्रसाद की पैठ जमाने के लिए जुगत भिड़ाते रहते थे. भूमिहार समाज में लालू प्रसाद का क्या स्थान था, यह हर कोई जानता था. इसके बावजूद समाज की गालियां सुनकर भी अखिलेश सिंह राजद सुप्रीमो को भूमिहारों के बीच स्वीकार्य बनाने के लिए प्रयासरत रहते थे. श्री बाबू की जयंती समारोह में ब्रह्मर्षियों और लालू के बीच नफ़रत की दरार पाटने की कोशिश का ही यह नतीजा था कि लालू ने ब्रह्मर्षियों और यादवों के बीच रोटी-बेटी के संबंध होने की बात कही थी. अखिलेश सिंह द्वारा आयोजित पूर्व के समारोहों और इस बार के समारोह का अंतर मंच पर मौजूद नेताओं के साथ-साथ मंच से कही गई बातों में नज़र आया. श्री बाबू की जयंती पर आयोजित समारोह में ब्रह्मर्षि समाज के हित में कम और दलित पसमांदा मुस्लिम समाज के हित की ज़्यादा बातें कहीं. ललन सिंह ने सरकार के ख़िलाफ़ भड़ास ज़रूर निकाली. अखिलेश सिंह ने 20 अक्टूबर को श्री कृष्ण सिंह का जन्म दिन मनाया, वहीं जदयू की सरपरस्ती में महाचंद्र सिंह ने अगले दिन यानी 21 अक्टूबर को समारोह का आयोजन किया. बैनरों-पोस्टरों और लक्ज़री गाड़ियों के सहारे आयोजित कार्यक्रम में राजनीतिक चतुराई का परिचय देत हुए समरस समाज की स्थापना की बात भले ही कही गई पर मंच से कही गई बातें पूरी तरह संदेह के घेरे में हैं. महाचंद्र सिंह को उनका अपना ही समाज विश्वसनीय नहीं मानता. लंगड़ी मार राजनीति के लिए चर्चित महाचंद्र सिंह ने जब कभी किसी को लंगड़ी मारने के लिए पैर बढ़ाया तब उन्होंने अपने ही स्वजातीय को निशाना बनाया. श्री बाबू के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को दरअसल न कभी उनके सिद्धांतों की परवार रही और न ही समाज की. विधान पार्षद नीरज कुमार कहते हैं कि राजनीतिक महापुरुषों की जयंतियां मनाना अनुचित नहीं है पर उनके सिद्धांतों को अमल में लाना ज़रूरी है. भूमिहार समाज में इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर कोई चर्चा तक नहीं करता है. ब्रह्मर्षियों को भी मालूम है कि इस प्रकार के कार्यक्रम महज अपना राजनीतिक वजन तौलने के लिए आयोजित किए जाते हैं. कारण स्पष्ट करते हुए एक भूमिहार नेता कहते हैं कि भूमिहार समाज प्रारंभ से ही प्रगतिशील रहा है और इस विरादरी का कभी कोई सर्वमान्य नेता नहीं रहा है. हनुमानकूद के लिए चर्चित नामों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है और इनमें जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार, विधानपार्षद नीरज कुमार, पूर्व मंत्री वीणा शाही, श्याम सुन्दर सिंह धीरज, रामजतन सिन्हा, जहानाबाद सांसद जगदीश शर्मा, लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, पूर्व सांसद सूरजभान व रोहित सिंह सहित कई अन्य शामिल हैं. हैरानी तो इस बात की है कि नेता समाज के अपमान को याद नहीं रखते हैं. लालू यादव ने बेगूसराय में भूरा बाल साफ करने का नारा दिया था. मंडल आंदोलन के दौरान नीतीश ने मोकामा में चुटकी भर बता कर मसलने की बात कही थी. दोनों इलाक़े भूमिहार बहुल थे और दोनों जगहों पर लोग ख़ामोश रहे. इनसे एक कदम आगे बढ़कर उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवर्णों को अपमानित किया था. पटना में आयोजित जगदेव प्रसाद जयन्ती समारोह में उपेंद्र कुशवाहा ने सरेआम कहा था कि पिछड़े गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे. यदि कोई पिछड़ों को गाली देगा तो गर्दन तक उनके हाथ पहुंच जाएगा. कांग्रेस पार्टी में मान-सम्मान प्राप्त होने के बावजूद अरुण कुमार दोबारा नीतीश के सिपहसालार बनने को तैयार हो गए. जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ बाढ़ की अदालत द्वारा सम्मन जारी करने के निर्देश मामले में सत्ता-शासन ने बतौर साजिशकर्ता अरुण कुमार को लक्षित किया था. पंडारक के ढीबर निवासी रामानन्द सिंह के कथित अपरहण मामले में अरुण कुमार के घर पुलिस का छापा पड़ा था तथा कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या मामले के गवाह रामानंद सिंह की बरामदगी भी पुलिस ने अरुण कुमार के आवास से दिखाई थी. मोकामा के एमएलसी नीरज कुमार का भी राजनीतिक जीवन हनुमानकूद का रहा है. जब नीतीश कुमार से ललन सिंह की दूरी बढ़ी और ललन ने किसान महापंचायत का झंडा बुलंद किया तब नीरज किसान रथ लेकर बिहार की सड़कों पर हांकने लगे. नीरज के कारनामे को अवसरवादिता की पराकाष्ठा माना गया. जहानाबाद के सांसद डॉ. जगदीश शर्मा की पलटीमारी ने तो सबको हतप्रभ कर दिया. विधानसभा उपचुनावों में पार्टी लाइन के विपरीत जाकर जगदीश शर्मा ने अपनी पत्नी शांति शर्मा को घोसी के समर में उतारा तो सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने एसटीएफ के जवानों को उतार दिया था. जगदीश शर्मा के समर्थकों की मतदान के दिन चुन-चुन कर पिटाई की गई. जदयू से निलंबित होने के बाद किसान महापंचायत के शुरुआती दिनों में समर्थन करने वाले जगदीश शर्मा ने न सिर्फ़ ख़ुद को महापंचायत से अलग किया बल्कि नीतीश के इशारे पर अब स्वामी सहजानंद किसान महाचौपाल के आयोजन में भी जुटे रहे. रामजतन सिन्हा भी दल-बदल के लिए चर्चित रहे हैं. कांग्रेस में हमेशा गुटबाजों की अग्रिम पंक्ति में शामिल रहें रामजतन सिन्हा के भी लोजपा के पदाधिकारी बने और फिर बाद में अपना संगठन भी बनाया. फ़िलहाल कांग्रेस में है. पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की स्थिति फ़िलहाल बेहतर है, लेकिन समाज से कहीं ज़्यादा उन्हें अपनी ख़ुद की चिंता है. बात यदि महाचंद्र प्रसाद की करें तो कांग्रेस के खूंटे से बंध कर रहने के बावजूद समाज के लोगों का कभी उन पर विश्वास नही रहा. अतीत को याद करते हुए जेपी आन्दोलन में सक्रिय रहे पत्रकार वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि मंडल आयोग का कतिपय लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा विरोध किया और यही कारण है कि अगड़ावाद-पिछड़वाद को बढ़ावा मिला और सवर्ण समुदाय राजनीति में हाशिए पर चला गया. भूमिहार समाज के बड़े तबके का मानना है कि नीतीश कुमार की राजनीति जब पिछड़ा-अतिपिछड़ा, महादलित-मुस्लिम समीकरण के सहारे आगे बढ़ेगी तो फिर बिरादरी के नेता क्यों नीतीश की सदारत कबूल करने को बेताब हैं. दोराहे पर खड़े भूमिहार समाज को इंतजार है इसके असली हीरो का. देखना है इस कसौटी पर कौन नेता खरा उतरता है.

feedback@chauthiduniya.com

बड़े नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने की चिंता

पटना में आयोजित जगदेव प्रसाद जयंती समारोह में उपेंद्र कुशवाहा ने सरेआम कहा था कि पिछड़े गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे. यदि कोई पिछड़ों को गाली देगा तो गर्दन तक उनका हाथ पहुंच जाएगा. कांग्रेस पार्टी में मान-सम्मान प्राप्त होने के बावजूद अरुण कुमार दोबारा नीतीश के सिपहसालार बनने को तैयार हो गए. जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ बाढ़ की अदालत द्वारा सम्मन जारी करने के निर्देश के मामले में शासन ने बतौर साजिशकर्ता अरुण कुमार को लक्षित किया था.